चिंतन

ट्रंप को दबाव में लेने में सफल रहा ईरान

आखिरकार 107 दिन से अधिक समय तक जारी संघर्ष के बाद अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो ही गया। अब उम्मीद है कि खाड़ी क्षेत्र में तनाव खत्म होगा और महंगाई से जूझ रही दुनिया को कुछ राहत मिलेगी। हालांकि समझौते की शर्तों को देखकर लगता है कि यह काफी पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन दोनों देशों के अड़ियल रुख के कारण अटका हुआ था। अब ईरान आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दबाव में लेने में सफल रहा और दोनों देश शांति समझौते पर सहमत हुए हैं। यदि 19 जून को जेनेवा में प्रस्तावित समझौते पर हस्ताक्षर हो जाते हैं तो यह केवल दो देशों के बीच युद्धविराम नहीं होगा, बल्कि वैश्विक राजनीति में शक्ति संतुलन का एक महत्वपूर्ण संकेत भी होगा। दिलचस्प बात यह है कि जिस ईरान को अमेरिका लगातार आर्थिक प्रतिबंधों, सैन्य दबाव और कूटनीतिक अलगाव के जरिए झुकाने की कोशिश कर रहा था, वही ईरान आज अपनी प्रमुख शर्तें मनवाने में सफल रहा। ट्रंप ने समझौते की घोषणा करते हुए इसे अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत बताया है। उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य को वाणिज्यिक जहाजों के लिए खोलने और नौसैनिक नाकेबंदी हटाने की बात कही है, लेकिन सवाल यह है कि यदि अमेरिका को अंततः यही कदम उठाने थे तो फिर 107 दिनों की तबाही, क्षेत्रीय अस्थिरता और वैश्विक आर्थिक संकट की आशंका क्यों पैदा की गई? दरअसल यह समझौता बताता है कि केवल सैन्य शक्ति के दम पर किसी राष्ट्र को हमेशा झुकाया नहीं जा सकता। ईरान की सबसे बड़ी सफलता यह रही कि उसने दबाव झेलते हुए भी अपने मूल हितों से समझौता नहीं किया। तेहरान ने स्पष्ट कर दिया कि यदि अमेरिका को स्थायी शांति चाहिए तो उसे नौसैनिक नाकेबंदी हटानी होगी, सैन्य कार्रवाई रोकनी होगी और ईरान के जमे हुए फंड जारी करने होंगे। हालांकि इस समझौते को अंतिम सफलता मान लेना जल्दबाजी होगी। स्वयं ट्रंप ने कहा है कि परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका की संतुष्टि जरूरी होगी, अन्यथा सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। इसका अर्थ है कि अविश्वास अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी दुश्मनी किसी एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर से समाप्त नहीं होगी। इस पूरे घटनाक्रम में इजराइल का रुख भी महत्वपूर्ण है। समझौते की घोषणा से ठीक पहले लेबनान में की गई बमबारी और इजराइली नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया इस बात का संकेत है कि क्षेत्रीय राजनीति अभी भी जटिल बनी हुई है। ऐसे में यदि अमेरिका और ईरान के बीच रिश्तों में नरमी आती है तो यह इजराइल की रणनीतिक चिंताओं को बढ़ा सकती है। यही वजह है कि शांति प्रक्रिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल वाशिंगटन और तेहरान नहीं, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया की जटिल भू-राजनीति है। इस समझौते का सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। होर्मुज जलडमरूमध्य से दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। यहां तनाव बढ़ने पर तेल की कीमतों में उछाल और महंगाई का खतरा लगातार बना हुआ था। यदि समुद्री मार्ग सामान्य होते हैं और क्षेत्रीय स्थिरता लौटती है तो ऊर्जा बाजार को राहत मिलेगी। इसका लाभ उन देशों को भी मिलेगा जो पहले से महंगाई और आर्थिक सुस्ती से जूझ रहे हैं। फिलहाल इतना कहा जा सकता है कि इस दौर में कूटनीति ने हथियारों पर बढ़त बनाई है और ईरान ने यह साबित किया है कि दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और रणनीतिक धैर्य के बल पर बड़ी से बड़ी महाशक्ति को भी बातचीत की मेज तक लाया जा सकता है।

राष्ट्रभक्ति
महेन्द्र तिवारी

सैन्य परंपरा-पोशाक में ऐतिहासिक बदलाव

वर्तमान समय में भारतीय सेना अपनी इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में एक युगांतरकारी और अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। सेना द्वारा अपनी वेशभूषा नीति, औपचारिक परंपराओं और सदियों पुराने रीति-रिवाजों में किए जा रहे बदलाव इस बात के जीवंत प्रमाण हैं कि अब देश अपनी औपनिवेशिक विरासत को पीछे छोड़ने के लिए मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार हो चुका है। इन महत्वपूर्ण और दूरगामी सुधारों का मुख्य उद्देश्य भारतीय सेना को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराकर विशुद्ध रूप से भारतीय संस्कृति, सभ्यता और अपनी ऐतिहासिक जड़ों से गहराई से जोड़ना है। यह संपूर्ण प्रक्रिया भारत सरकार के उन 5 महासंकल्पों का एक अनिवार्य हिस्सा है, जिन्हें पंच प्रण के नाम से जाना जाता है।

भारतीय सेना का इतिहास पराक्रम, शौर्य और अप्रतिम बलिदान की गाथाओं से समृद्ध है। स्वतंत्रता के बाद से ही हमारी सेना ने देश की सीमाओं की रक्षा करने और राष्ट्रीय संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने में अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। हालांकि, स्वतंत्रता के कई दशकों बाद भी सेना की कुछ आंतरिक व्यवस्थाओं, नियमों, पोशाक और प्रतीकों में ब्रिटिश काल की स्पष्ट छाप दिखाई देती थी। वर्तमान समय में भारतीय सेना अपनी इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में एक युगांतरकारी और अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। सेना द्वारा अपनी वेशभूषा नीति, औपचारिक परंपराओं और सदियों पुराने रीति-रिवाजों में किए जा रहे बदलाव इस बात के जीवंत प्रमाण हैं कि अब देश अपनी औपनिवेशिक विरासत को पीछे छोड़ने के लिए मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार हो चुका है।

इन महत्वपूर्ण और दूरगामी सुधारों का मुख्य उद्देश्य भारतीय सेना को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराकर विशुद्ध रूप से भारतीय संस्कृति, सभ्यता और अपनी ऐतिहासिक जड़ों से गहराई से जोड़ना है। यह संपूर्ण प्रक्रिया भारत सरकार के उन 5 महासंकल्पों का एक अनिवार्य हिस्सा है, जिन्हें पंच प्रण के नाम से जाना जाता है। इन संकल्पों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रण गुलामी की हर सोच और उसके प्रत्येक प्रतीक से पूर्ण मुक्ति पाना है, जिसे भारतीय सेना अब धरातल पर पूरी निष्ठा के साथ उतार रही है। ब्रिटिश शासनकाल से ही यह व्यवस्था निरंतर चली आ रही थी कि जब भी कोई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी किसी सैनिक कदमताल या विदाई समारोह की सलामी लेता था, तो वह समीक्षा अधिकारी के रूप में अपने साथ एक विशेष औपचारिक तलवार रखता था। यह तलवार ब्रिटिश काल में औपनिवेशिक शासकों द्वारा अपनी शक्ति, सर्वोच्च कमान और भारतीय सैनिकों पर अपने प्रभुत्व का प्रदर्शन करने का एक मुख्य माध्यम मानी जाती थी। स्वतंत्र भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संप्रभु राष्ट्र में इस तरह के सामंती प्रतीकों की कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी।

इसी ऐतिहासिक तथ्य को ध्यान में रखते हुए अब समीक्षा अधिकारी द्वारा सैन्य मार्च के दौरान या किसी भी अन्य औपचारिक निरीक्षण में तलवार रखने की इस पुरानी प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही, वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों द्वारा अपनी कमान और नेतृत्व के प्रतीक के रूप में ले जाई जाने वाली विशेष छड़ी के इस्तेमाल को अब बेहद सीमित कर दिया गया है। यह निर्णय स्पष्ट करता है कि भारतीय सेना में नेतृत्व और सम्मान का आधार कोई बाहरी वस्तु या औपनिवेशिक दिखावा नहीं, बल्कि अधिकारी की अपनी योग्यता, कर्तव्यपरायणता और अपने देश के प्रति अटूट निष्ठा है।

इस वैचारिक परिवर्तन का सीधा और गहरा असर सैन्य अधिकारियों के पहनावे और पोशाक से जुड़े नियमों पर भी दिखाई दे रहा है। एक लंबे समय से यह देखा जा रहा था कि सैन्य अधिकारियों के भोजनालयों और अन्य महत्वपूर्ण औपचारिक आयोजनों में पश्चिमी देशों के कोट, औपचारिक वस्त्रों और गले के बंध का ही प्रचलन अनिवार्य बना हुआ था। भारतीय जलवायु और यहां की गौरवशाली संस्कृति के सर्वथा विपरीत इस तरह के विदेशी पहनावे को ढोना भी एक प्रकार की मानसिक परतंत्रता का ही हिस्सा माना जा सकता है। इस पुरानी व्यवस्था को बदलते हुए अब अधिकारियों की औपचारिक

पोशाक में पहली बार 'बंदी' नाम के पारंपरिक भारतीय परिधान को आधिकारिक तौर पर स्थान दिया गया है। यह बिना आस्तीन का एक विशेष वस्त्र है, जिसे आम बोलचाल में पारंपरिक कुर्ता या भारतीय नेहरू वेशभूषा के रूप में भी जाना जाता है। अब सैन्य अधिकारी इसे अपनी कमीज और पतलून के साथ अत्यंत गर्व से धारण कर सकते हैं। यह कदम न केवल भारतीय वस्त्र उद्योग और स्थानीय शिल्पकला को नया सम्मान देता है, बल्कि सैन्य जीवनशैली में एक विशिष्ट भारतीय पहचान का समावेश भी करता है। इसके माध्यम से यह दृढ़ संदेश दिया गया है कि हमारे अपने पारंपरिक परिधान भी दुनिया के किसी भी उच्च स्तरीय आधिकारिक आयोजन के लिए पूरी तरह से गरिमापूर्ण और सर्वश्रेष्ठ हैं। इस प्रकार, सैन्य व्यवस्था और उसकी जीवनशैली में किए गए ये सभी बदलाव केवल ऊपरी या सतही परिवर्तन नहीं हैं, बल्कि यह भारतीय समाज और राष्ट्र की सोच में आ रहे एक व्यापक गुणात्मक सुधार को रेखांकित करते हैं। सेना के सभी संगीत दल अब विदेशी धुनों की बजाय भारतीय शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत और देश की माटी से जुड़ी देशभक्ति की धुनों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। यह युगांतरकारी बदलाव भविष्य की पीढ़ियों को भी अपनी अनूठी संस्कृति पर गर्व करने की निरंतर प्रेरणा देता रहेगा। परंपराओं के इस शुद्धिकरण के अंतर्गत केवल पहनावा ही नहीं बदला गया है, बल्कि अधिकारियों की विदाई के तौर-तरीकों में भी बड़े सुधार किए गए हैं। पूर्ववर्ती नियमों के अनुसार, जब भी सेना के शीर्ष पदों पर आसीन अधिकारी, जैसे थल सेनाध्यक्ष या सैन्य कमान प्रमुख अपनी लंबी सेवा के बाद सेवानिवृत्त होते थे, तो उन्हें विदाई देने के लिए घोड़ों से खिंचने वाली एक पुरानी पारंपरिक बग्घी का उपयोग किया जाता था। यह घोड़ों वाली बग्घी प्रथा पूरी तरह से ब्रिटिश राजसी ठाट-बाठ और आम जनता तथा साधारण सैनिकों से दूरी बनाए रखने की औपनिवेशिक मानसिकता से प्रेरित थी, जो एक लोकतान्त्रिक देश की सेना में उचित नहीं जान पड़ती थी। अब सेना ने इस सामंती विदाई प्रथा को भी हमेशा के लिए बंद करने का ऐतिहासिक फैसला किया है। अब अधिकारियों की विदाई बेहद सादगीपूर्ण, अनुशासित और भारतीय मूल्यों के अनुरूप की जाती है। यह बदलाव सैन्य अधिकारियों और उनके अधीन काम करने वाले जवानों के बीच की दूरी को कम करने तथा सेना के भीतर एक समतावादी और आत्मीय वातावरण स्थापित करने में बहुत सहायक सिद्ध हो रहा है।

सैन्य संस्कृति का एक और बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण हिस्सा उसका संगीत होता है, जो सैनिकों के भीतर अदम्य साहस का संचार करता है। युद्ध के मैदान से लेकर शांति काल के समारोहों तक, सैन्य संगीत दल हमेशा से जवानों में जोश और देशप्रेम की भावना भरते रहे हैं। लेकिन स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी हमारे विभिन्न सैन्य संगीत दल पुरानी अंग्रेजी और स्कॉटिश धुनों को बजाने के लिए विवश थे। गणतंत्र दिवस उत्सव के समापन समारोह के अवसर पर आयोजित होने वाले भव्य कार्यक्रम में वर्षों तक एक विदेशी प्रार्थना धुन बजाई जाती थी, जिसका भारतीय जनमानस से कोई भी भावनात्मक जुड़ाव नहीं था। अब इस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए उस पुरानी विदेशी धुन के स्थान पर 'ऐ मेरे वतन के लोगों' जैसी अमर, लोकप्रिय और हृदयस्पर्शी भारतीय देशभक्ति धुन को शामिल किया गया है। जब सैन्य वाद्यों से भारतीय राग और लोक धुनें निकलती हैं, तो वे न केवल सैनिकों का मनोबल बढ़ाती हैं बल्कि पूरे देश को एक सांस्कृतिक सूत्र में पिरोने का काम करती हैं। इन सुधारों के माध्यम से सेना ने यह साबित कर दिया है कि वह आधुनिकतम तकनीकों और घातक हथियारों से लैस होने के साथ-साथ वैचारिक रूप से पूरी तरह भारतीय मूल्यों, सिद्धांतों और राष्ट्रभक्ति के प्रति समर्पित है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **haribhoomi@gmail.com** पर दे सकते हैं।

डिजिटल पंचायत

बलकार सिंह

ई-गवर्नेंस पुरस्कार से दिखी गांवों की बदलती तस्वीर

भारत के लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति उसकी पंचायतों में निहित है। संविधान के 73वें संशोधन ने जिस पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक आधार प्रदान किया था, आज वही व्यवस्था डिजिटल तकनीक, डेटा आधारित निर्णय और नागरिक-केंद्रित सेवाओं के माध्यम से विकास की नई इबारत लिख रही है। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के परिणाम इस परिवर्तन के सशक्त प्रमाण हैं। इन पुरस्कारों ने न केवल पंचायतों की उपलब्धियों को राष्ट्रीय पहचान दी है, बल्कि यह भी सिद्ध किया है कि विकसित भारत 2047 का सपना गांवों की भागीदारी के बिना साकार नहीं हो सकता। पंचायती राज मंत्रालय की चार पहलों का राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के लिए चयनित होना अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल तकनीक के उपयोग का सम्मान नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने के प्रयासों की स्वीकृति है। यह पहल देशभर की ग्राम पंचायतों के विकास प्रदर्शन का वैज्ञानिक और डेटा-आधारित मूल्यांकन करती है। स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों के नौ विषयों पर आधारित यह सूचकांक पंचायतों को केवल योजनाओं के क्रियान्वयन तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें परिणामोन्मुख शासन की ओर प्रेरित करता है। यह पहली बार है जब ग्राम पंचायतों के विकास को इतने व्यापक और तथ्यपरक तरीके से मापा जा रहा है। डेटा आधारित शासन की यह संस्कृति आने वाले समय में ग्रामीण प्रशासन की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में महाराष्ट्र के सांगली जिले की कादेपुर ग्राम पंचायत का स्वर्ण पुरस्कार जीतना विशेष रूप से प्रेरणादायक है। यह पंचायत आज डिजिटल भारत की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करती है। यहां 4,300 से अधिक लाभार्थियों को 1,355 से अधिक सेवाएं पूर्णतः ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं। पूरी पंचायत कागज रहित ई-ऑफिस प्रणाली पर कार्य कर रही है। आठ एआई-संचालित प्रशासनिक अनुप्रयोग, ब्लॉकचेन आधारित रिकॉर्ड प्रबंधन और जीआईएस आधारित संपत्ति जियो-टैगिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग यह दर्शाता है कि तकनीकी नवाचार केवल महानगरों तक सीमित नहीं है। कादेपुर देश की एकमात्र ग्राम पंचायत है जिसके पास कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, नैनो तकनीक, जैव प्रौद्योगिकी और रोबोटिक्स पर औपचारिक रूप से स्वीकृत नीतियां हैं। यह उपलब्धि बताती है कि यदि नेतृत्व दूरदर्शी हो तो गांव भी वैश्विक स्तर की तकनीकी प्रयोगशाला बन सकते हैं। इसी प्रकार त्रिपुरा की बिजॉय नगर ग्राम पंचायत ने रजत पुरस्कार प्राप्त कर यह सिद्ध किया है कि डिजिटल परिवर्तन केवल तकनीक का प्रश्न नहीं, बल्कि सामाजिक भागीदारी का भी विषय है। इस पंचायत ने सहभागी शासन, वित्तीय जवाबदेही और डिजिटल समावेशन का उत्कृष्ट मॉडल प्रस्तुत किया है। पंचायत उन्नति सूचकांक में इसका स्कोर 88.55 तक पहुंच गया है, जो पिछले संस्करण की तुलना में 38 प्रतिशत अधिक है। सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि महिलाओं में 100 प्रतिशत डिजिटल साक्षरता प्राप्त करना है। यह उदाहरण बताता है कि जब तकनीक समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है, तभी उसका वास्तविक उद्देश्य पूरा होता है। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिला परिषद की 'ई-आरोग्य धामनी' पहल को मिला स्वर्ण पुरस्कार ई-गवर्नेंस की सामाजिक उपयोगिता को रेखांकित करता है। आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल माध्यमों से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना आसान कार्य नहीं है। इस पहल ने सिद्ध किया है कि तकनीक का सर्वोत्तम उपयोग तभी है जब वह उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। पंचायत उन्नति सूचकांक, कादेपुर, बिजॉय नगर और ई-आरोग्य धामनी जैसी पहलें दिखाती हैं कि गांवों में परिवर्तन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज का जो सपना देखा था, वह आत्मनिर्भरता, पारदर्शिता और जनभागीदारी पर आधारित था। आज डिजिटल तकनीक उस स्वप्न को आधुनिक स्वरूप प्रदान कर रही है। यदि देश की पंचायतें इसी प्रकार तकनीक को जनकल्याण का माध्यम बनाती रहीं, तो विकसित भारत 2047 केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक साकार होती हुई वास्तविकता बन जाएगा। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 ने यह साबित कर दिया है कि भारत की विकास यात्रा की सबसे मजबूत नींव गांवों में ही रखी जा रही है और डिजिटल पंचायतें ही भविष्य के भारत की नई पहचान बनने जा रही हैं।

(लेखक इग्नू में सहायक प्रोफेसर हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

भजन ही शरीर का प्राण

संकलित
दर्शन

काकभुशुंडि जी कहते हैं, मेरे इस भाव परिवर्तन से मेरे परमकृपालु सदाशिव विश्वनाथ मुझ पर और भी अधिक प्रसन्न हो गए। उन्हें लगा कि मेरे इस भक्त (काकभुशुंडि) का प्रवेश मेरे हृदय में हो गया है और इसने देख लिया कि मेरे इष्ट तो बालक राम हैं, जो अयोध्या में दशरथ के अजिर में मालपुआ लेकर घूमते रहते हैं। काकभुशुंडि जी हमें और आपको यह बताना चाहते हैं कि जब उन्होंने कौआ होकर भी भगवान को पा लिया तो हम लोगों के भाग्य के लिए तो शब्द ही नहीं हैं। प्रभु श्रीरामचंद्र जी ने स्वयं भी समस्त चराचर के कल्याण के लिए मनुष्य का ही शरीर धारण कर लिया है। वे कहते हैं कि इस शरीर को पाने का मात्र एक ही लाभ है कि व्यक्ति भगवान का भजन करे। भक्त काकभुशुंडि ने मनुष्य शरीर से भजन करने के प्रताप और फल को बताते हुए कहा कि ज्ञानी ऋषि लोमश ने मेरे अंदर भक्ति के प्रति पक्षपात देखकर भले ही मुझे अपनी दृष्टि से कौआ बनने का शाप दिया था, पर वह मेरे लिए वरदान हो गया। महत्व इसका नहीं है कि हम किस शरीर, किस देश, किस जाति और धर्म के हैं। काकभुशुंडि जी कहते हैं कि महत्वपूर्ण यह है कि हम भगवान की भक्ति और भजन कर रहे हैं या नहीं? भजन ही शरीर का प्राण है। गोस्वामी जी ने इस बात पर जोर दिया है कि जिसने इस धरा पर जन्म लेकर भगवान का भजन कर लिया, बस वही धन्य है। उसी की विजय होती है, वही संसार में सबके प्रति विनयी होता है, वही गुणों की खान होता है और सारे विश्व में उसी का यश त्रैलोक्य में उजागर होता है।

ईश्वर बहुत दयालु है

संकलित
प्रेरणा

एक राजा का एक विशाल फलों का बगीचा था, उसमें तरह-तरह के फल होते थे और उस बगीचा की सारी देखरेख एक किसान अपने परिवार के साथ करता था। वह किसान हर दिन बगीचे के ताजे फल लेकर राजा के राजमहल में जाता था। एक दिन किसान ने पेड़ों पे देखा नारियल, अमरुद, बेर, और अंगूर पक कर तैयार हो रहे हैं, किसान सोचने लगा आज कौन सा फल महाराज को अर्पित करूँ। फिर उसे लगा अँगूर करने चाहिए, क्योंकि वो तैयार हैं। इसलिए उसने अंगूरों की टोकरी भर ली और राजा को देने चल पड़ा! किसान राजमहल में पहुंचा, राजा किसी दूसरे ख्याल में खोया हुआ था और नाराज भी लग रहा था। किसान रोज की तरह मीठे रसीले अंगूरों की टोकरी राजा के सामने रख दी और थोड़े दूर बैठ गया। अब राजा उसी ख्यालों-ख्यालों में टोकरी में से अंगूर उठाता एक खाता और एक खींच कर किसान के माथे पे निशाना साधकर फेंक देता। राजा का अंगूर जब भी किसान के माथे या शरीर पर लगता था तो किसान कहता था, ईश्वर बड़ा दयालु है। राजा फिर और जोर से अंगूर फेकता था, किसान फिर वही कहता था, ईश्वर बड़ा दयालु है। थोड़ी देर बाद राजा को एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है और प्रत्युत्तर क्या आ रहा है, वो सम्भल कर बैठा। उसने किसान से कहा, मै तुझे बार-बार अंगूर मार रहा हूँ और ये अंगूर तुम्हे लग भी रहे हैं, फिर भी तुम यह बार-बार क्यों कह रहे हो कि ईश्वर बड़ा दयालु है।

अंतर्मन

आज की पाती

बढ़ती असहिष्णुता

राजधानी रायपुर में मामूली विवाद से शुरू हुआ झगड़ा हत्या तक पहुंच रहा है। ऐसी घटनाएं समाज में बढ़ती असहिष्णुता, गुस्से और संवाद की कमी की गंभीर समस्या को उजागर करती है। आज देशभर में छोटी-छोटी बातों पर हिंसा, मारपीट और हत्याओं की घटनाएं बढ़ती दिखाई दे रही हैं। इसके पीछे घटता धैर्य, बढ़ता तनाव, नशे का दुरुपयोग, सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री और न्याय प्रक्रिया में देरी जैसे कई कारण जिम्मेदार माने जा सकते हैं। हालांकि कानून कमजोर नहीं है। भारतीय न्याय संहिता हत्या, दंगा और हिंसा के लिए कड़े दंड का प्रावधान करती है। चुनौती कानूनों की कमी नहीं, बल्कि उनके प्रति सम्मान और सामाजिक मूल्यों को मजबूत करने की है।

- सुधीर यादव, रायपुर

ट्रेंड

भारत-स्लोवाकिया दोस्ती

प्रधानमंत्री फिको के साथ बहुत अच्छी बैठक हुई। भारत-स्लोवाकिया दोस्ती के लिए यह एक बहुत खास पल है। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

जीवन में ठोस सुधार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में,पिछले 12 वर्षों में टैक्स में राहत, मेट्रो नेटवर्क के विस्तार, आधुनिक कनेक्टिविटी और 'ईज ऑफ लिविंग' (जीवन को आसान बनाने) पर लगातार ध्यान दिए जाने से भारत के मध्यम वर्ग के जीवन में ठोस सुधार आए हैं।

- **रेखा गुप्ता**, सीएम, नई दिल्ली

ईडी पार्टी जिम्मेदार

ईडी पार्टी के अधिकारी खुद पंजाब में ड्रग्स बेचते हुए पकड़े गए। क्या उसके तार ड्रग्स से जुड़े हैं? आज पंजाब में 70% ड्रग्स गुजरात के रास्तों से आ रही है। पंजाब के युवाओं को बर्बाद करने के लिए ईडी पार्टी और 'चिट्टा पार्टी' जिम्मेदार हैं।

-अरविंद केजरीवाल, पूर्व सीएम, नई दिल्ली

मातृभूमि की नई कहानी

नफरत के कांटे बहुत बढ़ गए हैं, अब 'फूलों का मौसम' लाने का समय आ गया है। 'प्यार, करुणा और अपनापन' लेकर हमें हर गांव और गली तक पहुंचना है। मिलकर, हम सभी को अपनी मातृभूमि की एक नई कहानी लिखनी है।

-अखिलेश यादव, सांसद, सपा

करंट अफेयर

पिचाई के भाषण में छात्रों ने लहराए फलस्तीन झंडे

अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में गूगल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सुंदर पिचाई के संबोधन के दौरान फलस्तीन समर्थक कई छात्रों ने बहिर्गमन किया और झंडे लहराए। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से 'मैटीरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग' में मास्टर ऑफ साइंस (एमएस) की डिग्री प्राप्त कर चुके पिचाई रविवार को वर्ष 2026 की कक्षा को संबोधित करने के लिए अपने पूर्व शिक्षण संस्थान लौटे थे। 'स्टैनफोर्ड रिपोर्ट' के अनुसार विश्वविद्यालय के 135वें दीक्षांत समारोह में 3,600 छात्रों सहित 20,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। 'एसएफगेट' की एक खबर में कहा गया है कि पिचाई द्वारा छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और अन्य उपस्थित लोगों को संबोधित किए जाने के दौरान लगभग 200 छात्र समारोह स्थल से बाहर चले गए। खबर के अनुसार, दर्शक दीर्घा में मौजूद कुछ समूहों ने बैनर और फलस्तीनी झंडे लहराए तथा सीटी बजाई। बाद में वे भाषण के बीच में ही बाहर निकल गए। खबर में कहा गया कि फलस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों ने इजराइल सरकार के साथ गूगल के संबंधों, विशेष रूप से वर्ष 2021 में हुए 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर के क्लाउड कंप्यूटिंग समझौते 'प्रोजेक्ट निम्बस' का विरोध किया।

ऑफ बीट

भोजन के साथ आपके संबंध कैसे हैं

क्या आप अपने शरीर के संकेतों को समझते हैं, जिसका अर्थ है कि आपको पता है कि आपको कब भूख लगी है, कब नहीं और कब पेट भरा हुआ महसूस हो रहा है? सभी खाद्य समूहों में नियमित अंतराल पर उचित मात्रा और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खा रहे हैं ताकि आपकी पोषक तत्व, स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी ज़रूरतें पूरी हों? दूसरों के साथ खाना और अकेले खाना भी आरामदायक है? क्या आप भोजन का आनंद लेने में सक्षम हैं, यदि आपको अधिक जवाब हां में नहीं मिले, तो आपको भोजन के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने पर काम करने की आवश्यकता हो सकती है। समस्या यह है कि यह मस्तिष्क के पुरस्कार केंद्र को ट्रिगर करता है, जिसका अर्थ है कि यद्यपि आप बेहतर महसूस करते हैं, यह व्यवहार प्रबल हो जाता है, इसलिए नकारात्मक भावनाओं के जवाब में आपके खाते रहने की संभावना अधिक होती है। भावनात्मक खान-पान और अनियंत्रित खान-पान की प्रवृत्ति खाने के विकार के लक्षणों और खराब गुणवत्ता वाले आहार से जुड़ी होने की अधिक संभावना है, जिसमें सब्जियों का कम सेवन और कम पोषक तत्वों वाले खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन शामिल है।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

केवल वही व्यक्ति उत्तम रूप से कार्य करता है, जो पूर्णतया निस्वार्थी है, जिसे न तो धन की लालसा है और न कीर्ति की।

– स्वामी विवेकानंद

राहत की उम्मीद

अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष को समाप्त करने तथा होर्मुज जलमार्ग को फिर से खोलने पर बनी सहमति भारत समेत दुनिया के कई देशों के लिए संकट से राहत मिलने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। द्विपक्षीय शांति समझौते पर उन्नीस जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाने का प्रस्ताव है। इसके लागू होने से निश्चित तौर पर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला फिर से बहाल हो पाएगी, जिससे खासकर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर दबाव कम होगा और ऊर्जा की पर्याप्त उपलब्धता के साथ-साथ इसकी कीमतों में भी गिरावट आएगी। मगर अमेरिका और ईरान के बीच इस सहमति को अभी उम्मीद के तौर पर ही देखा जा रहा है, क्योंकि पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से दोनों पक्षों के रुख में जिस तरह की अनिश्चतता देखी गई है, उस लिहाज से इस समझौते के सिरे चढ़ने को लेकर अभी पूरी तरह भरोसा करना मुश्किल है। संशय इसलिए भी बना हुआ है, क्योंकि अंतिम समझौते के नियम और शर्तें अभी औपचारिक रूप से सार्वजनिक नहीं की गई हैं और दोनों पक्षों में से कौन इसमें अड़ंगा लगा दे, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता।

गौरतलब है कि अमेरिका और इजराइल ने इस वर्ष 28 फरवरी को ईरान पर संयुक्त रूप से हमला किया था, जिसके बाद ईरान ने भी पलटवार शुरू कर दिया। अप्रैल में अमेरिका की ओर से दो सप्तह के युद्धविराम की घोषणा की गई, जिसे बाद में अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया गया। हालांकि, इस बीच दोनों ओर से छिटपुट हमले होते रहे, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान होर्मुज जलमार्ग को बाधित करने से हुआ, जिससे वैश्विक स्तर पर ऊर्जा का संकट खड़ा हो गया। वैश्विक तेल आपूर्ति के लगभग पांचवें हिस्से का परिवहन इसी मार्ग से होता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे तेल उत्पादक खाड़ी देशों के लिए यही मुख्य निर्यात मार्ग है, जो भारत के प्रमुख ऊर्जा आपूर्तिकर्ता भी हैं। अगर यह मार्ग फिर से बहाल हो जाता है, तो भारत जैसे दुनिया के कच्चे तेल आयातक देशों को बड़ी राहत मिलेगी। इससे तेल आपूर्ति को लेकर चिंताएं कम होंगी, माल ढुलाई लागत घटेगी और महंगाई पर दबाव भी कम होगा।

पश्चिम एशिया में संघर्ष खत्म करने पर बनी सहमति की खबरें आने के बाद से ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल कीमतों में गिरावट का दौर शुरू हो गया। भारत में इसका असर शेयर बाजार में उछाल और डालर के मुकाबले रुपए की मजबूती के रूप में सामने आया। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह समझौता सफलतापूर्वक लागू होता है, तो भारत की अर्थव्यवस्था को कई मोर्चों पर राहत मिलने की उम्मीद है। इससे पश्चिम एशिया को होने वाले भारत के निर्यात में तेजी आएगी, विनिर्माण गतिविधियों को गति मिलेगी और रुपए की स्थिरता को भी बल मिलेगा। ईरान की ओर से होर्मुज जलमार्ग को अवरुद्ध करने के बाद इसके आसपास अमेरिका की नाकेबंदी से स्थिति और जटिल हो गई है। मगर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्विपक्षीय सहमति के एलान के साथ यह स्पष्ट कर दिया है कि इस जलमार्ग के फिर से खुलते ही नाकेबंदी को भी हटा लिया जाएगा। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि अमेरिका और ईरान इस सहमति पर कायम रहेंगे और शांति समझौते को अंतिम मंजूरी देने की दिशा में सकारात्मक रूप से कदम आगे बढ़ाएंगे, ताकि पश्चिम एशिया में फिर से शांति, स्थिरता और साझा समृद्धि का रास्ता खुल सके।

अफवाह की आग

मध्य प्रदेश में मुरैना रेलवे स्टेशन के निकट हुए हादसे में चार यात्रियों की मौत से रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बार-बार होने वाले इस तरह के हादसे रेलवे बोर्ड के उन दावों की सच्चाई को सामने लाते हैं, जिनमें रेलगाड़ी के सफर को पूरी तरह सुरक्षित बनाए जाने की बात कही जाती है। सवाल है कि अगर चलती ट्रेन में किसी तरह की अफवाह से बचने के लिए सुरक्षात्मक उपायों पर ध्यान न दिया जाए, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? गौरतलब है कि रविवार को खजुराहो-उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस के इंजन के पास के एक डिब्बे में आग लगने की अफवाह के बाद कुछ यात्री ट्रेन से उतर कर बगल की पटरियों पर खड़े हो गए। इसी बीच, दूसरी ओर से आ रही एक अन्य ट्रेन की चपेट में आने से चार यात्रियों की मौत हो गई। इससे प्रतीत होता है कि पहले हुए इस तरह के हादसों से कोई सबक नहीं लिया गया।

एक ट्रेन के यात्रियों का दूसरी ट्रेन की चपेट में आने की यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी देश भर में ऐसे कई हादसे हो चुके हैं। सवाल है कि इस तरह की अफवाह के दौरान स्थिति को कैसे संभालना है, क्या रेलवे कर्मियों को इसका प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है? ट्रेन के चालक और अन्य कर्मियों को वहां से गुजरने वाली अन्य रेलगाड़ियों के समय की जानकारी होती है, इसके बावजूद दूसरी पटरी पर खड़े यात्रियों को समय रहते आगाह क्यों नहीं किया गया। उत्तर मध्य रेलवे की ओर से जारी बयान में कहा गया कि घटनास्थल पर तीखा मोड़ है, इसलिए पटरी पर खड़े यात्रियों और दूसरी ओर से आ रही ट्रेन के चालक को एक-दूसरे का पता नहीं चल सका। मगर सवाल यह भी है कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए रेलवे में बचाव का कोई पुख्ता तंत्र विकसित क्यों नहीं किया जाता? रेलवे बोर्ड को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और इस हादसे की गहराई से जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि इस तरह के हादसे की पुनरावृत्ति न हो।

ऊर्जा सुरक्षा में समानता का सवाल

प्रश्न सिर्फ यह नहीं है कि देश में बिजली उत्पादन कितना है, बल्कि यह भी है कि उसका लाभ कितनी समानता के साथ मिल रहा है। ऊर्जा के वितरण में न्याय का होना भी जरूरी है।

विजयशंकर चतुर्वेदी

भारत की ऊर्जा नीति इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां उपलब्धियों के चमकदार आंकड़े और वितरण की जमीनी वास्तविकताएं साथ-साथ दिखाई देती हैं। पिछले एक दशक में देश ने बिजली उत्पादन, ग्रिड विस्तार और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। मगर किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए असली प्रश्न केवल यह नहीं होता कि वह कितनी बिजली पैदा कर रहा है, बल्कि यह भी होता है कि उस बिजली का लाभ किसे और कितनी समानता के साथ मिल रहा है। इसी बिंदु पर उत्पादन और वितरण, उपलब्धि एवं अधिकार और विकास तथा समानता के प्रश्न एक-दूसरे से टकराते हैं। ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में मिली सफलताओं को ऊर्जा न्याय में बदल पाना आज भारतीय ऊर्जा नीति की सबसे बड़ी परीक्षा है।

बिजली उत्पादन के मोर्चे पर उपलब्धियां निर्विवाद हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और विद्युत मंत्रालय के अनुसार, 31 जनवरी 2026 तक देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 5,20,511 मेगावाट तक पहुंच चुकी थी, जो वर्ष 2013-14 के लगभग 224 गीगावाट के स्तर की तुलना में दोगुने से भी अधिक है। कुल स्थापित क्षमता में गैर-जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी 52 फीसद से ऊपर पहुंच चुकी है और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 273 गीगावाट के आस-पास है। पिछले वित्तीय वर्ष के शुरुआती दस महीनों में 52,537 मेगावाट नई क्षमता जोड़ी गई, जिसमें अधिकांश योगदान अक्षय ऊर्जा का रहा। राष्ट्रीय ग्रिड अब 242 गीगावाट की रेकार्ड मांग को संभालने में सक्षम है। इन उपलब्धियों ने भारत को वैश्विक ऊर्जा संक्रमण के अग्रणी देशों में शामिल किया है, लेकिन क्या राष्ट्रीय ग्रिड की यह प्रचुरता हर नागरिक के लिए भी उतनी ही वास्तविक और विश्वसनीय है, जितनी वह सरकारी आंकड़ों में दिखाई देती है?

माना कि देश में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण का लक्ष्य लगभग हासिल किया जा चुका है। मगर बिजली का मीटर लगा देना और गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति एक ही बात नहीं हैं। शहरी क्षेत्रों में औसतन 23 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 21 घंटे बिजली उपलब्ध होने के सरकारी दावों के बावजूद जमीनी वस्तुस्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देश के अनेक सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों, आदिवासी अंचलों और पहाड़ी इलाकों में आज भी मामूली तकनीकी खराबी के बाद बिजली आपूर्ति लंबे समय तक बाधित हो जाती है। शहरों में ट्रांसफार्मर खराब होने पर मरम्मत अपेक्षाकृत तेजी से होती है, जबकि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में यही प्रक्रिया अधिक समय लेती है। कृषि क्षेत्र में बिजली की अनिश्चित उपलब्धता किसानों की उत्पादकता को प्रभावित करती है। अनेक राज्यों में कृषि और घरेलू फीडरों के पृथक्करण का कार्य अभी भी अधूरा है।

ऊर्जा क्षेत्र की यह विषमता वितरण व्यवस्था में और स्पष्ट दिखाई देती है। महानगरों और बड़े औद्योगिक केंद्रों में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता अपेक्षाकृत बेहतर है। निजी वितरण कंपनियों के प्रवेश के बाद कई शहरों

में उपभोक्ता सेवाओं, शिकायत निवारण और बिलिंग व्यवस्था में सुधार हुआ है, लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि ऊर्जा वितरण की चुनौतियां समाप्त हो गई हैं। हाल के वर्षों में बड़े महानगरों ने लागत से अधिक बिल वसूलने, भीषण गर्मी और चरम मौसम की परिस्थितियों में ग्रिड विफलताओं का सामना किया है। इससे स्पष्ट है कि ऊर्जा अवसंरचना को केवल दक्षता के आधार पर नहीं, आपदा-सहिष्णुता के आधार पर भी परखा जाना चाहिए। इस स्थिति को समझने के लिए उन वितरण कंपनियों को भी देखना होगा, जिन पर बिजली को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वर्षों तक घाटे और बढ़ते कर्ज से जूझने के बाद कई सरकारी बिजली कंपनियां अब बेहतर वित्तीय प्रदर्शन कर रही हैं। तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान में कमी आई है। बकाया राशि के प्रबंधन में भी सुधार हुआ है। मगर किसी वितरण कंपनी की सफलता केवल उसके बही-खाते से नहीं आंकी जा सकती। उसकी वास्तविक कसौटी यह है कि वह आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक कितनी गुणवत्तापूर्ण बिजली पहुंचा पा रही है।

> देश की सौर ऊर्जा क्षमता दुनिया के सबसे बड़े अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों में शामिल है, लेकिन यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि हरित ऊर्जा का लाभ केवल बड़े निवेशकों और चुनिंदा क्षेत्रों तक सीमित न रह जाए। यदि इस ऊर्जा का लाभ दूरस्थ क्षेत्रों तक नहीं पहुंचा, तो नई ऊर्जा व्यवस्था भी पुरानी असमानताओं को दोहरा सकती है। यह आशंका भी बनी रहेगी कि जीवाश्म ईंधन आधारित व्यवस्था की खामियों का स्थान हरित ऊर्जा की नई कमियों से न भर दिया जाए। भारत की ऊर्जा यात्रा सुरक्षा से शुरू हुई थी। अब उसकी अगली मंजिल ऊर्जा न्याय होनी चाहिए। ऊर्जा केवल अर्थव्यवस्था का ईंधन नहीं, बल्कि समान अवसर, सामाजिक गरिमा और विकास की आधारशिला भी है।

वित्तीय सुधारों के बावजूद कई राज्यों में सबसिडी भुगतान में देरी, जर्जर स्थानीय अवसंरचना, राजनीतिक हस्तक्षेप और कमजोर वसूली प्रणाली जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। नतीजा यह कि राष्ट्रीय औसत में सुधार के बावजूद अनेक क्षेत्रों में सेवा की गुणवत्ता अब भी असंतोषजनक है। दरअसल, सेवा गुणवत्ता में यही असमानता उस बड़े नीतिगत प्रश्न की ओर संकेत करती है कि आखिर ऊर्जा व्यवस्था का उद्देश्य केवल बिजली बेचना है या उसे एक सार्वजनिक अधिकार के रूप में उपलब्ध कराना भी है? यहीं ऊर्जा न्याय का संवेदनशील प्रश्न सामने आता है। जब बिजली की मांग उपलब्धता के बराबर पहुंचने लगे या आपूर्ति पर दबाव बढ़े, तब प्राथमिकता किसे मिलनी चाहिए? बड़े उद्योगों को, जो आर्थिक विकास और रोजगार का आधार हैं या ग्रामीण अस्पतालों, स्कूलों, सिंचाई प्रणालियों और छोटे कस्बों को, जिनके लिए बिजली विकास ही नहीं बल्कि जीवन और आजीविका की बुनियादी आवश्यकता है?

व्यावहारिक स्तर पर राज्य और उसकी संस्थाएं प्रायः उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देती हैं, जो आर्थिक वृद्धि, औद्योगिक उत्पादन और राजस्व सृजन में अधिक योगदान करते हैं। इसके अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन केवल आर्थिक उत्पादकता के आधार पर ऊर्जा का वितरण सामाजिक न्याय की कसौटी पर हमेशा उचित नहीं ठहराया जा सकता। शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, रोजगार और गरिमापूर्ण जीवन के लिए बिजली एक बुनियादी शर्त है। इसलिए ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा न्याय को एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि परस्पर पूरक लक्ष्यों के रूप में देखना होगा। यदि ऊर्जा व्यवस्था का पूरा ढांचा केवल लाभ, राजस्व और बाजार दक्षता के मानकों से संचालित होगा, तो समाज के वे हिस्से अनिवार्य रूप से पीछे छूट जाएंगे, जिनके लिए बिजली विकास का नहीं, जीवन का प्रश्न है।

भारत की सौर ऊर्जा क्षमता दुनिया के सबसे बड़े अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों में शामिल है, लेकिन यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि हरित ऊर्जा का लाभ केवल बड़े निवेशकों और चुनिंदा क्षेत्रों तक सीमित न रह जाए। यदि इस ऊर्जा का लाभ दूरस्थ क्षेत्रों तक नहीं पहुंचा, तो नई ऊर्जा व्यवस्था भी पुरानी असमानताओं को दोहरा सकती है। यह आशंका भी बनी रहेगी कि जीवाश्म ईंधन आधारित व्यवस्था की खामियों का स्थान हरित ऊर्जा की नई कमियों से न भर दिया जाए। भारत की ऊर्जा यात्रा सुरक्षा से शुरू हुई थी। अब उसकी अगली मंजिल ऊर्जा न्याय होनी चाहिए। ऊर्जा केवल अर्थव्यवस्था का ईंधन नहीं, बल्कि समान अवसर, सामाजिक गरिमा और विकास की आधारशिला भी है।

रिश्तों की डोर

अनुपमा तिवाड़ी

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में वह बहुत सारे रिश्तों के साथ रहता है। हर व्यक्ति का रिश्ता किसी दूसरे के साथ अलग तरह का होता है। समाज में बहुत से रिश्ते हमें विरासत में मिलते हैं, जिन्हें हम कई बार पारिवारिक, तो कभी सामाजिक दबावों की वजह से निभाते हैं। ऐसे रिश्ते धीरे-धीरे मरते जाते हैं और फिर एक समय आता है कि जब वे टूट जाते हैं। पहले ये रिश्ते झगड़ों के बाद भी बने रहते थे, जिसके अनेक कारण थे। मगर अब भौतिक साधनों के चलते परस्पर निर्भरता कम हुई है। कभी-कभी कुछ समय चलने के बाद रिश्तों में एक-दूसरे से कुछ नहीं कह पाने की ऊहापोह अबोलेपन में बदल जाती है और फिर दूरियां बढ़ते-बढ़ते रिश्तों की डोर कब टूट जाती है, पता ही नहीं चलता। किसी भी रिश्ते को खींच-खींचकर लंबे समय तक निभाया नहीं जा सकता है।

सामाजिक रिश्तों में दोस्ती का रिश्ता हम खुद चुनते हैं। एक जैसे आचार-विचार, पसंद-नापसंद और सम्मानजनक व्यवहार करने वाले दो व्यक्ति परिचय से आगे बढ़कर कब हाथ बढ़ाकर दोस्त बन जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। यह दोस्ती एक-दूसरे के लगातार संपर्क से सुकून की तरफ जाने लगती है। दोस्ती का रिश्ता हमें खास महसूस करवाता है, जिसे हमने चुना होता है और जिसमें कोई बाध्यता नहीं, निभाने का कोई दबाव नहीं। 'दोस्ती' एक छोटा-सा शब्द है, लेकिन इसमें पूरी दुनिया समाई होती है। बिना दोस्ती के हमारा जीवन अधूरा-सा महसूस होता है, जहां हम दिल खोलकर बातें करते हैं और जहां मुश्किल समय में हम दोस्त के लिए खड़े रहते हैं।

दोस्ती का रिश्ता अमीरी-गरीबी, अच्छे-बुरे या किसी भी भेदभाव को नहीं देखता। यह सच्चाई और समर्पण पर आधारित होता है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि मजबूत रिश्ते तनाव को कम करते हैं और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। हाल के अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि जिन लोगों के पास अच्छे रिश्ते होते हैं, वे अधिक खुश और स्वस्थ होते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो अपने मित्रों के साथ नियमित रूप से समय बिताता है, वह अधिक संतुष्ट और खुश रहता है।

दो दोस्त बहुत कुछ समानता रखते हुए भी भिन्न होते हैं। इसलिए ''दोस्ती एक कला है'', जिसमें हर व्यक्ति एक-दूसरे की निजता का सम्मान करता है, उसे प्रेरित करता है, उसके सुख-दुख का साथी होता है। मगर बहुत निकटता होने के बावजूद हर व्यक्ति का एक निजी कोना भी होता है, जिसमें प्रवेश करना वर्जित होता है। इसलिए दूसरे को सुनना और समझना बहुत आवश्यक है। दूसरे की निजता का सम्मान करना बहुत जरूरी है। कई बार हम किसी दूसरे के अंदर की आवाज सुने बिना अपनी इच्छाएं उस पर लादने लगते हैं, जिससे व्यावहारिक समस्याएं पैदा होने लगती हैं। मगर रिश्तों की मजबूत डोर तो दिलों से बंधी होती है, जिसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। दोस्ती पर कितने ही गीत बने हैं, फिल्में बनी हैं, जिन्होंने दोस्ती की मिसाल पेश की है, मौन को पढ़ना सिखाया है।

दोस्ती कहने भर का शब्द नहीं, महसूस करने का रिश्ता है। यह एक गंभीर चिंतन का विषय है कि हमें अपने रिश्तों को कैसे सहेजना है? रिश्तों को नियमों में नहीं बांधा जा सकता। दोस्ती करना सिखाया नहीं जा सकता। एक समय के बाद हम कभी-कभी दूसरे दोस्त से पहले जैसे व्यवहार की अपेक्षा करने लगते हैं, जो व्यवहार हमें पहले मिलता था, हमें वही व्यवहार चाहिए होता है। हम यह क्यों भूल जाते हैं कि दोस्त भी एक व्यक्ति है, उसमें भी हर दिन बदलाव हो रहा है- शरीर का, भावनाओं का, उसकी स्थितियों का और आवश्यकताओं का। इसलिए पहले जैसी मांग की अपेक्षा कई बार हमें और दोस्त, दोनों को असमंजस में डाल देती है।

दो मित्रों के बीच संवाद एक-दूसरे को समझने और सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है। फिर भी कई बार जब हम किसी व्यक्ति से किन्हीं कारणों से दूर होना चाहते हैं, उसे भी सहजता से स्वीकार करना चाहिए। इसमें दूसरे की इच्छा सर्वोपरि है, लेकिन ऐसे में कई बार जब हम दूसरे पर अपना हक जताने लगते हैं, तो रिश्ते में दरार पड़ने लगती है और यह स्थिति कई बार इतनी बढ़ जाती है कि दोस्ती, दुश्मनी में बदल जाती है। जो आज हमारे दोस्त हैं, वही कल दुश्मन हो जाता है।

मगर हम यह क्यों यह भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति की मानसिक स्थिति और आवश्यकता हमेशा एक-सी नहीं रहती। आज जो उसकी पसंद है, हो सकता है कल वह न हो। हमें रिश्तों के प्रति सहज रहना चाहिए। आपसी समझ और स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। किसी भी रिश्ते में अगर कोई नहीं रहना चाहता हो, तो उसे सहजता से स्वीकार करना चाहिए। जब चुनने की स्वतंत्रता है, तो अलग होने की क्यों नहीं? बिना किसी को आहत किए हम खुद को उस रिश्ते से बाहर निकाल सकते हैं। यह दोनों के सम्मान को बनाए रखेगा और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देगा।

दुनिया मेरे आगे

> दोस्ती कहने भर का शब्द नहीं, महसूस करने का रिश्ता है। रिश्तों को सहेजने की जरूरत होती है, इन्हें नियमों में नहीं बांधा जा सकता। एक समय के बाद हम दोस्त से पहले जैसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, मगर यह भूल जाते हैं कि वह भी एक व्यक्ति है, उसमें भी हर दिन बदलाव हो रहा है।

लोकतंत्र की शक्ति

इसमें दोराय नहीं कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वह किसी भी दल या नेता को स्थायी सत्ता का अधिकार नहीं देता। जनता जब यह महसूस करने लगती है कि सत्ता जनसेवा के बजाय विशेषाधिकार का माध्यम बन गई है, तब परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होती है। पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक तृणमूल कांग्रेस का वर्चस्व रहा। प्रारंभिक वर्षों में पार्टी ने वाम शासन के विरुद्ध जनता की आकांक्षाओं को स्वर दिया, लेकिन समय बीतने के साथ उस पर कई आरोप लगने लगे। 'कट-मनी', सिंडिकेट संस्कृति, भर्ती घोटालों तथा प्रशासनिक पक्षपात के मुद्दे लगातार चर्चा में रहे। इन आरोपों ने न केवल विपक्ष को सरकार के विरुद्ध माहौल बनाने का अवसर दिया, बल्कि पार्टी के भीतर भी असंतोष को जन्म दिया। बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य में विपक्ष, विशेषकर भाजपा ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी उपस्थिति मजबूत करने का प्रयास किया है। दूसरी ओर, तृणमूल के भीतर उभरते असंतोष ने भी राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित किया। इन दोनों कारकों ने मिल कर राज्य की राजनीति को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है।

– युगल किशोर राही, छपरा

शांति के विरुद्ध

'नमनानी के निशाने' (संपादकीय, 12 जून) पढ़ा। इसमें समकालीन वैश्विक परिस्थितियों पर गंभीर विमर्श किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति की हठधर्मिता और मनमाने निर्णयों के दूरगामी प्रभाव दिख रहे हैं। किसी भी राष्ट्र की एकपक्षीय नीतियां केवल उसके हितों तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि उनका प्रभाव वैश्विक शांति, स्थिरता और मानवीय मूल्यों पर भी पड़ता है। विभिन्न संघर्षों और तनावपूर्ण परिस्थितियों के कारण निर्दोष लोगों की जानें जा रही हैं। इससे अनेक देशों की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। ऐसे समय में वैश्विक स्तर पर पैदा हो रही परिस्थितियों को समझने की जरूरत है। मौजूदा परिदृश्य में भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए संतुलित और दृढ़ भूमिका निभाने का प्रयास किया है। विश्व शांति और मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए सामूहिक उत्तरदायित्व का होना आवश्यक है।

– अशोक, पटना, बिहार

महिलाओं की सुरक्षा

'हिंसा के विरुद्ध' (संपादकीय, 11 जून) पढ़ा। देश में महिलाओं के प्रति बढ़ती यौन हिंसा, दहेज प्रताड़ना और मारपीट किसी भी तरह से सभ्य समाज की निशानी नहीं कहीं जा सकती है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की घटनाएं गांवों में अधिक हैं। जबकि माना यह जाता है कि वे शहर के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित है। हालांकि यह समस्या हर जगह बढ़ती दिखाई दे रही है। इसीलिए इस तरह की हिंसा को रोकने के लिए लड़कियों को पढ़ाना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना बेहद जरूरी है, ताकि उन्हें अपने अधिकार मालूम हो सकें। घर में बेटों को भी उनका सम्मान करना सिखाना होगा। लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। उनके विरुद्ध हिंसा करने वाले दोषियों को तत्काल सजा दिलाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे उनमें कानून का डर कायम हो। महिलाओं की सुरक्षा सरकार के साथ-साथ समाज की भी जिम्मेदारी है।

– भगवानदास छारिया, इंदौर

समुदाय की चिंता

अंडमान और निकोबार प्रशासन की ओर से जनजातीय परिषदों के लिए प्रस्तावित नए चुनावी नियम ने द्वीप समूह के मूल समुदाय में एक गंभीर बहस को जन्म दे दिया है। प्रशासन का तर्क है कि देश के बाकी हिस्सों की तरह यहां भी पांच वर्षीय औपचारिक चुनावी प्रक्रिया, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। पहली नजर में यह आधुनिक लोकतंत्र का स्वागत योग्य कदम लग सकता है, लेकिन इसके पीछे छिपी जमीनी चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। निकोबारी समुदाय सदियों से पारंपरिक स्वशासन प्रणाली के तहत संचालित होता आ रहा है। जनजातीय नेताओं का यह डर स्वाभाविक है कि इस नई व्यवस्था से उनका पारंपरिक ताना-बाना और निर्णय लेने की स्वायत्तता छिन्न-भिन्न हो जाएगी।

– प्रसिद्ध यादव, फुलवारी, पटना

लोकमानस

loksatta@expressindia.com

हे सत्ता आणि संपत्तीचे ऋणानुबंध

‘मूठभरशाही!’ हा अग्रलेख (१५ जून) वाचला. अमेरिकी उद्योगपती इलॉन मस्क हे जागतिक पातळीवर सर्वात श्रीमंत झाले असले तरी, त्यांचे पंख कापण्याचे बळ अमेरिकी कायद्यात आहेत. मायक्रोसॉफ्ट, एटी अँड टी या दूरसंचार कंपनीवर कायदेशीर आळा घालून, त्यांची मक्तेदारी मोडीत काढण्यात अमेरिकेस आलेले यश, हे राजकीय मुत्सद्देगिरीचे वाखाणण्यासारखे उदाहरण म्हणावे लागेल. इलॉन मस्क यांच्यावर मात्र असली बंधने लादून मक्तेदारी मोडीत काढता येणार नाही. कारण त्यांनी अंतराळातील प्रवास, विजेवर चालणाऱ्या मोटारी अशा अशक्य विकासाची धुरा समर्थपणे सार्थकी लावली. आर्थिक दबदबा आणि राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांनी कमालीची पायाभरणी करून ठेवली असली तरी, एखाद्याची मक्तेदारी मोडीत काढणारा कायदादेखील तिथे अस्तित्वात आहे.

नेमकी याउलट परिस्थिती आपल्या देशात आहे. इथे सरकार स्वतःच मक्तेदारीस प्रोत्साहन देताना दिसते, भलेही मग अशा उद्योगपतीला संबंधित क्षेत्रातील ज्ञानाचा, अनुभवाचा गंध असो वा नसो! ‘अदानी’सारख्या अननुभवी उद्योग समूहाला बंदरे, विमानतळे, रेल्वे, नैसर्गिक संपदेचा नाश करून सिमेंटचे जंगल उभारण्यासाठी मुभा देण्यात सरकार स्वतः पुढाकार घेत असेल तर तो आत्मघातकी निर्णयच ठरेल. सत्तेच्या चक्रव्यूहात अडकलेल्या सरकारने देशाच्या संपत्तीचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या ट्रिलियन उड्डाणांचे दावे हास्यास्पद ठरत आहेत. रेवड्यांची उधळपट्टी करून सत्तेचे सिंहासन टिकवून ठेवण्यात, सरकार भलेही तरबेज असो, त्यातून लोकशाही मूल्ये बाधित होत आहेत.

भारतात सत्ता आणि संपत्ती यांच्या ऋणानुबंधाच्या गाठी बांधल्या गेल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. भारतीय जनमानस हे विश्वासाच्या चौकटीत बंदिस्त आहे. त्यामुळे राज्यकर्त्यांना रान मोकळे झाले आहे. संपत्तीच्या विकेंद्रीकरणातूनच तळागाळापर्यंतचे जनजीवन समृद्ध होऊ शकेल.

■ **डॉ. नूतनकुमार पाटणी,** चिकलठाणा (छत्रपती संभाजीनगर)

राहुल गांधींचे मुद्दे कागदावर योग्यच, पण...

‘राहुल गांधींच्या भाषणाचा अर्थ काय?’ हा ‘लाल किल्ला’ सदरातील लेख वाचला. राहुल गांधींना आता वास्तवाचे भान आले आहे असे जाणवते. पण त्यांनीच तृणमूल काँग्रेसवर आतिशय कठोर टीका केली त्याला एक महिनादेखील झालेला नाही. तेच पुढे माकपवरही टीका करतात, मग विरोधी पक्षांची एकजूट होणार तरी कशी?

मुळात सोनिया गांधी यांनी यूपीए जशी साकारली व नेतृत्वगुण दाखवून टिकवून ठेवली, तसे राहुल गांधींना जमलेले नाही. त्यातही यूपीएच्या काळात काँग्रेस सत्तेत होती त्यामुळेही सर्व पक्ष एकत्र येण्यास तयार असत. सत्ता नसेल आणि नजीकच्या काळात ती येण्याची शक्यताही नसेल तर कठीण परिस्थिती आहे हे मात्र खरे. ‘इंडिया’ आघाडी फक्त केंद्रात करायची असे असेल तर आघाडीला फार बिकट अवस्था येणार आहे. प्रत्येक निवडणूक आघाडी एकत्र लढणार असेल तरच बरोबरीची टक्कर होईल. रालोआ सगळीकडे एकत्र लढते. त्यामुळे लढत एकाकी होत आहे. तसेही राहुल छान बोलतात, मुद्देही चांगले असतात, पण त्यांची पुरेशी दखल माध्यमे घेत नाहीत. दोन दिवसांपूर्वी प्रियंका गांधींनी काँग्रेसमध्ये नेता ते कार्यकर्ता अशी पक्षीय रचना अस्तित्वात नाही असे म्हटले होते. हे वास्तव पाहता इतर घटक पक्ष राज्याराज्यांत काँग्रेसला का साथ देतील? बाकी सांविधानिक संस्था नेहमीच सतेच्या बाजूने असतात त्याबद्दल बोलणे व्यर्थच. कागदावर राहुल गांधींचे मुद्दे योग्य आहेत तरीही प्रत्यक्ष निवडणुकीत तसेच होईल याची कमी शक्यता वाटते.

■ **डॉ. मंगेश नागापूरकर,** शिरडशहापूर (हिंगोली)

भ्रष्टाचारमुक्ती केवळ घोषणांतच?

‘ठेकेदारीतील ५६ टक्के रक्कम अधिकारी व आमदारांना’ ही बातमी (लोकसत्ता- १५ जून) वाचली. जीएसटीची रक्कम सोडली तर बाकीचा सरळसरळ भ्रष्टाचारच आहे आणि तो सरकारी स्तरावर सुरू आहे, असेच यावरून दिसते. कामाचा योग्य दर्जा राखला नाही म्हणून कोणत्या तोंडाने सरकार कंत्राटदारांना जाब विचारणार? आणि दंड करणार? तेव्हा ही अत्यंत गंभीर बाब समजून, या अत्यंत गंभीर सरकारी भ्रष्टाचाराप्रकरणी खुद्द पंतप्रधानांनी लक्ष घालून याचा सोक्षमोक्ष लावावा, तरच त्यांच्या भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन आणि सरकारसंदर्भातील घोषणा आणि दाव्यांना अर्थ प्राप्त होईल, अन्यथा त्या केवळ पोकळ घोषणा ठरतील.

■ **मोहन गद्रे,** कांदिवली (मुंबई)

ही टक्केवारी लोकशाहीच्या मुळावर!

‘ठेकेदारीतील ५६ टक्के रक्कम अधिकारी व आमदारांना’ ही बातमी (लोकसत्ता- १५ जून) वाचली. कोल्हापूर येथे महाराष्ट्र राज्य शासकीय ठेकेदार महासंघाच्या अधिवेशनात जाहीरपणे शासकीय कामात कुणाला किती टक्केवारी द्यावी लागते याचे वर्णन झाले. मुदलातच एखाद्या शासकीय कामाचा खर्च भरमसाट वाढवून दाखवलेला असतो, हे काही लपून राहिलेले नाही. त्याला कारण म्हणजे यंत्रणेतील प्रत्येकाचा टक्केवारीनुसार असलेला वाटा! हे यानिमित्ताने ठळकपणे निदर्शनास आले. बऱ्याच दिवसांपासून शासनाने ठेकेदारांमार्फत केलेल्या कामांचे पैसे दिले नसल्याच्या बातम्या वारंवार विविध माध्यमांवर येतात. याचा फटका बसतो तो सामान्य जनतेला. कारण कामाचा दर्जा ‘अर्थपूर्ण’ संबंधांमुळे राखला जात नाही, कामाला विलंब होतो आणि करदात्यांचा पैसा विनाकारण खर्च होतो. हे दीर्घकालीन लोकशाहीसाठी घातक आहे.

■ **अतुल श्रेष्ठ,** छत्रपती संभाजीनगर

पोलिसांची अकार्यक्षमता की संमतीच?

‘गिरगावातही पांढऱ्या पट्ट्यांवरून वाद’ (१५ जून) ही बातमी वाचली. त्यावरून ‘आमचीच खरी’ शिवसेना गप्प कशी?’ हे आणि ‘हे जैन समाजावर व त्यांच्या मुनींवर शिंतोडे उडवणारे’ ही दोन्ही पत्रे वाचली. कोणी तरी हेतुपुरस्सर ही शांत मुंबई पेटवण्याचा पद्धतशीरपणे प्रयत्न करत आहे आणि मुंबई पोलीसही त्यात सामील आहेत, असा संशय येतो.

रातोरात येऊन कोणी तरी चांगली जाडजूड, आकृतिबद्ध आणि अत्यंत व्यवस्थित अशी लांबलचक सफेद पट्टी रस्त्यावर मारून जातो, रात्रभर हा कारनामा रस्त्यावर घडत असतो आणि मुंबई पोलिसांना याची कानोकान खबरही लागू नये हा सारा प्रकारच अतिशय हास्यास्पद वाटतो. ‘मुंबई कधीच झोपत नाही!’, ‘मुंबई पूर्णपणे सुरक्षित आहे!’ हे मुंबई पोलीस मोठ्या अभिमानाने सांगत असतात. मुंबईतील सर्व पोलीस ठाणी हल्ली सीसीटीव्हीच्या निगराणीखाली आहेत असेही सांगितले जाते. असे असताना रातोरात केली जाणारी ही सफेदी एकप्रकारे मुंबई पोलिसांच्या तोंडावर काळे फासल्यासारखीच आहे, याचे भान मुंबई पोलिसांना का नसावे? की हे सर्व पोलिसांच्या संमतीने सुरू आहे? हा गुन्हा प्रत्यक्ष घडत असताना पकडून मुंबई पोलिसांनी आपला खाक्या दाखवला, तर ताबडतोब यामागचा सूत्रधार कोण, हे सहज कळेल आणि हा खेळ बंद होईल.

■ **ॲड. एम. आर. सबनीस,** अंधेरी (मुंबई)

शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणे नित्याचेच

‘शेतीसाठी पाणीपुरवठा बंद, राज्य सरकारचे आदेश’ हे वृत्त (लोकसत्ता- १५ जून) वाचले. सरकारने पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवताना शेतीकडे दुर्लक्ष करणे योग्य वाटत नाही. अशा कृतीमुळे सरकार दुजाभाव करत असल्याचे स्पष्ट होते. पिकांचा पाणीपुरवठाच बंद केला तर जोमदार पिके तरी येणार कशी? व अशा वेळी असहाय शेतकऱ्यांनी दाद कोणाकडे मागायची? या संदर्भात शेतकऱ्यांचे दोन्ही बाजूंनी मरण असते. एक तर पेरणी करून पाऊसच पडला नाही तर शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट ओढवते, अन्यथा पेरणी केल्यानंतर मुसळधार पाऊस पडल्यास बियाणे वाहून जाते. अशा कठीण प्रसंगी सरकारकडून शेतकऱ्यांना वेळेवर आर्थिक मदतसुद्धा केली जात नाही. सरकारचा शेतकऱ्यांबद्दलचा कळवळा किती बेगडी आहे, हे अनेक उदाहरणांवरून दिसून येते. उदा. अजितदादा हयात असताना, त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की, यंदा सरकारची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने, शेतकऱ्यांनो तुम्हीच कर्ज फेडा. तसेच फडणवीस यांनी ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज दोन लाखांपर्यंत आहे अशांचेच कर्ज माफ करण्याची घोषणा करून इतरांच्या तोंडाला पानेच पुसली.

■ **गुरुनाथ मराठे,** बोरिवली (मुंबई)

साखर उद्योग राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा!

साखर कारखाने म्हणजे केवळ उद्योग नाहीत, तर शेतकऱ्यांच्या प्रगतीची, ग्रामीण विकासाची आणि राष्ट्रनिर्मितीची ती प्रभावी केंद्रे आहेत.

दिलीप वळसे पाटील
विधानसभा सदस्य,
उपाध्यक्ष, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट, पुणे
माजी अध्यक्ष, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ, नवी दिल्ली

पहिली बाजू

साखर उद्योग हा महाराष्ट्राच्या सहकार चळवळीचा आधारस्तंभ आहे. हा उद्योग केवळ शेतकरी समृद्धी आणि हरित अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करणारा आणि महाराष्ट्रातील औद्योगिक व्यवसाय नसून राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मजबूत कणा आहे. या उद्योगाशी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे ५० लाख ऊस उत्पादक शेतकरी, १० लाख ऊसतोडणी कामगार आणि सुमारे दीड लाख कायम कर्मचारी जोडलेले आहेत. म्हणजेच ग्रामीण महाराष्ट्रातील लाखो कुटुंबांचे जीवनमान साखर उद्योगावर अवलंबून आहे. राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांनी गेल्या अनेक दशकांत ग्रामीण भागात रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक विकासाला चालना दिली आहे.

शेतकऱ्यांसाठी साखर उद्योग का महत्त्वाचा?

ऊस हे महाराष्ट्रातील सर्वात विश्वासार्ह नगदी पीक मानले जाते. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बाजारातील चढ-उतारांच्या तुलनेने कमी फटका बसतो. कारण केंद्र सरकारकडून एफआरपी (फेअर अँड रेम्युनरेटिव्ह प्राइस) निश्चित केली जाते. २०१८-१९ मध्ये उसाची एफआरपी २,७५० रु. प्रति टन होती. ती वाढून २०२६-२७ मध्ये ३,६५० रु. प्रति टन झाली आहे. म्हणजे आठ वर्षांत सुमारे ३३ टक्के वाढ झाली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात सातत्याने वाढ होत असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत चलनवाढ झाली आहे. ऊस पिकाला हमखास खरेदीदार उपलब्ध असल्याने शेतकऱ्यांना उत्पादन विक्रीची चिंता राहत नाही. कारखान्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना वाहतूक, तांत्रिक मार्गदर्शन, सिंचन व्यवस्थापन आणि आधुनिक शेती पद्धतींचा लाभ मिळतो. याच कारणामुळे महाराष्ट्रातील ऊस पट्ट्यातील अनेक भागांमध्ये आर्थिक स्थैर्य अधिक दिसून येते. नियमित उत्पन्न, कारखान्यांशी थेट संबंध आणि उसाचे निश्चित मूल्य यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक जोखमीत घट होते. ग्रामीण भागांतील रोजगार निर्मितीमुळे कुटुंबांना पर्यायी उत्पन्नाचे स्रोत मिळतात.

रोजगाराचा मोठा स्रोत

साखर उद्योग हा शेतीनंतर ग्रामीण भागातील सर्वात मोठा रोजगारदाता उद्योग आहे. राज्यातील दहा लाख ऊसतोडणी कामगारांना या उद्योगामुळे हंगामी रोजगार मिळतो. याशिवाय दीड लाख कायम कर्मचारी विविध कारखान्यांमध्ये कार्यरत आहेत. ग्रामीण भागात उद्योग निर्माण करणे हे कोणत्याही राज्यासाठी मोठे आव्हान असते. मात्र साखर कारखान्यांनी गावागावांत आर्थिक क्रियाशीलता निर्माण केली आहे. अनेक ठिकाणी साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून रस्ते, शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये आणि सामाजिक सुविधा विकसित झाल्या आहेत. वाहतूक, दुरुस्ती, यंत्रसामग्री, खत-औषध पुरवठा, किरकोळ व्यापार, बँकिंग, शिक्षण आणि सेवा क्षेत्रालाही या उद्योगामुळे चालना मिळते. एका साखर कारखान्याभोवती संपूर्ण ग्रामीण अर्थचक्र निर्माण होते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील स्थलांतर कमी होण्यास या उद्योगाने मोठा हातभार लावला आहे.

महसूल व विकासाचा आधार

महाराष्ट्र शासनाला साखर उद्योगातून दरवर्षी सुमारे आठ हजार कोटी रुपये महसूल प्राप्त होतो. जीएसटी, वीज वापर, वाहतूक, विविध परवाने आणि संबंधित आर्थिक व्यवहारांमधून राज्याच्या तिजोरीत मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न जमा होते. साखर उद्योग मजबूत राहिल्यास राज्य शासनालाही अधिक महसूल मिळतो. हा निधी पायाभूत सुविधा, सिंचन प्रकल्प, रस्ते, शिक्षण, आरोग्य आणि ग्रामीण विकास योजनांसाठी वापरला जाऊ शकतो. त्यामुळे साखर उद्योगाचा विकास म्हणजे राज्याच्या एकूण विकासाला गती मिळणे होय.

इथेनॉल : आत्मनिर्भरतेचा पाया

गेल्या काही वर्षांत इथेनॉल उत्पादनामुळे साखर उद्योगाला नवे आर्थिक बळ मिळाले आहे. केंद्र सरकारच्या ‘बायोफ्युएल पॉलिसी २०१८’ मुळे साखर कारखान्यांनी मोठ्या प्रमाणावर इथेनॉल प्रकल्प उभारले आहेत. महाराष्ट्रात एकूण ४२४ कोटी लिटर इतकी इथेनॉल उत्पादन क्षमता निर्माण करण्यात आली आहे. इथेनॉल हे पेट्रोलमध्ये मिश्रणासाठी वापरले जाणारे स्वदेशी जैवइंधन आहे. त्यामुळे देशाचे परकीय चलन वाचते, पेट्रोलियम आयातीवरील अवलंबित्व कमी होते आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जा उपलब्ध होते.

इथेनॉल उत्पादनामुळे उसाचा अधिक परिणामकारक वापर होतो. साखरेच्या अतिरिक्त उत्पादनाचा प्रश्न कमी होतो आणि कारखान्यांना उत्पन्नाचे अतिरिक्त साधन उपलब्ध होते. याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मिळतो. राष्ट्रीय स्तरावर मका व धान्यआधारित इथेनॉलसाठी ७०० कोटी लिटर तर ऊसआधारित इथेनॉलसाठी ३०० कोटी लिटरचे वाटप करण्यात आले आहे. महाराष्ट्राला एकूण स्थापित ४२४ कोटी लिटर क्षमतेपैकी ११६ कोटी लिटरचे वाटप झाले आहे. यामुळे सध्या सुमारे २६ टक्के क्षमता वापरली जात आहे. भविष्यात क्षमता वापर वाढल्यास राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला आणखी मोठा फायदा होऊ शकतो.

सरकारला होणारे फायदे

इथेनॉल उत्पादन हे देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठीही अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यामुळे पेट्रोल आयात खर्चात बचत, परकीय चलनाची मोठी बचत, कार्बन उत्सर्जनात घट, हरित आणि स्वदेशी इंधनाचा वापर, ग्रामीण भागांत नवीन उद्योगांची निर्मिती, अतिरिक्त रोजगाराच्या संधी, ऊस उत्पादकांना अधिक स्थिर बाजारपेठ, इत्यादी उद्दिष्टे साध्य होऊ शकतात. म्हणूनच इथेनॉल क्षेत्रातील गुंतवणूक ही देशाच्या दीर्घकालीन ऊर्जा धोरणाचा महत्त्वाचा भाग बनली आहे.

आव्हाने व शासनाचा दृष्टिकोन

साखरेच्या उत्पादनाचा खर्च वाढला असला तरी केंद्र आणि राज्य शासन या उद्योगाच्या बळकटीकरणासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार ११ सप्टेंबर २०२५च्या पत्रानुसार साखरेचा उत्पादन खर्च ४,०२९ रु. प्रति क्विंटल आहे. यामध्ये ऊस एफआरपीचा खर्च ३,४६३ रु. प्रति क्विंटल आहे. प्रक्रियेदरम्यान लागणारी रसायने, इंधन आणि इतर खर्चांतही वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर उद्योगाने काही मागण्या मांडल्या आहेत. त्यामध्ये साखरेचा किमान आधारभूत दर ४,१०० रु. प्रति क्विंटल करण्याची मागणी, रस/सिरप आधारित इथेनॉलसाठी ७२ रु. प्रति लिटर आणि बी-हेवी मोलॅसेस आधारित इथेनॉलसाठी ६७ रु. प्रति लिटर दर निश्चित करण्याची मागणी समाविष्ट आहे. तसेच ३१ मार्च २०२६ पर्यंतची थकीत कर्जे पुनर्गठित करून दोन वर्षांचा स्थगिती कालावधी आणि १०-१२ वर्षांचा परतफेड कालावधी देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. SEFASU 2014, Soft Loan 2015 आणि Soft Loan 2019 प्रमाणे व्याज अनुदानाची अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे. याशिवाय इथेनॉल प्रकल्पांसाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याज अनुदानापोटी २१ कारखान्यांचे ६९ कोटी रुपये प्रलंबित असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

ग्रामीण विकासाचा नमुना

महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखाने हे ग्रामीण विकासाचे प्रभावी मॉडेल मानले जातात. शेतकरी, कामगार, कारखाने आणि शासन यांच्यातील परस्परसहकार्यामुळे राज्यात आर्थिक क्रियाशीलता निर्माण झाली आहे. साखर उद्योगामुळे लाखो शेतकरी कुटुंबांना स्थैर्य मिळाले, रोजगार निर्माण झाला आणि ग्रामीण भागात विकासाची गती वाढली. आज ५० लाख शेतकरी, १० लाख ऊसतोडणी कामगार आणि दीड लाख कर्मचारी यांचे जीवन या उद्योगाशी जोडलेले आहे. ५५-६० हजार कोटींची उलाढाल आणि आठ हजार कोटी रुपये महसूल निर्माण करणारा हा उद्योग महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा एक भक्कम आधारस्तंभ आहे. इथेनॉलसारख्या हरित ऊर्जेच्या नव्या संधी, केंद्र व राज्य शासनाचे सहकार्य, सहकार क्षेत्राची मजबूत परंपरा आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची मेहनत यांच्या बळावर महाराष्ट्राचा साखर उद्योग आगामी काळात अधिक सक्षम, आधुनिक आणि आत्मनिर्भर भारताच्या निर्मितीत अग्रणी भूमिका बजावेल. ग्रामीण समृद्धी, शेतकरी कल्याण, रोजगार निर्मिती आणि ऊर्जा स्वावलंबन या सर्व उद्दिष्टांना गती देणारा साखर उद्योग हा महाराष्ट्राच्या विकासाचे खरे इंजिन ठरत आहे.

एकंदर, महाराष्ट्रातील साखर उद्योग हा शेतकरी, कामगार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि शासन यांच्यातील यशस्वी भागीदारीचे उत्तम उदाहरण आहे. लाखो शेतकऱ्यांना स्थिर उत्पन्न, ग्रामीण भागात रोजगार, सरकारला महसूल, देशाला स्वच्छ ऊर्जा आणि अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचे काम या उद्योगाने केले आहे. विशेषतः ऊस उत्पादक भागांमध्ये निर्माण झालेली आर्थिक स्थिरता, सहकार चळवळीची मजबूत परंपरा आणि ग्रामीण विकासाची प्रक्रिया यामुळे साखर उद्योगाचे महत्त्व अधिक अधोरेखित होते. इथेनॉलसारख्या नव्या संधींमुळे हा उद्योग आता केवळ साखरेपुरता मर्यादित राहिलेला नसून भारताच्या ऊर्जा स्वावलंबनाचा आणि ग्रामीण समृद्धीचा एक प्रमुख आधारस्तंभ बनला आहे. आजच्या घडीला साखर कारखाने म्हणजे केवळ उद्योग नाहीत, तर शेतकऱ्यांच्या प्रगतीचे, ग्रामीण विकासाचे आणि राष्ट्रनिर्मितीचे प्रभावी केंद्र आहेत. योग्य धोरणात्मक पाठबळ आणि तांत्रिक आधुनिकीकरणाच्या जोरावर हा उद्योग भविष्यातही महाराष्ट्र आणि देशाच्या विकासात अधिक मोठे योगदान देईल. त्यासाठी या उद्योगाकडे राजकीय नजरेतून न पाहता शाश्वत विकासाचा मूलभूत घटक म्हणून संरक्षित करणे ही काळाची गरज आहे.

कुतूहल

साखर की गूळ?

साखर आणि गूळ हे दोन्ही उसाच्या रसापासून मिळणारे पदार्थ आहेत. तरीही वारंवार असं म्हटलं जातं की आहारात साखरेचा वापर कमी करा आणि त्याऐवजी गूळ वापरा! ‘साखरेपेक्षा गूळ चांगला’ या विधानात कितपत तथ्य आहे हे कळण्यासाठी, मुळात उसाच्या रसापासून साखर आणि गूळ मिळवण्याच्या प्रक्रिया आणि या प्रक्रियांमुळे त्यांच्या पोषणमूल्यांमध्ये पडणारा फरक आपण समजून घेऊ या.

साखर तयार करताना सर्वप्रथम ऊस धुऊन घेतात. नंतर त्यातला रस काढण्यासाठी तो चिरून रोलर्समधून फिरवला जातो. या कच्च्या रसात चुन्याचं पाणी मिसळून त्याला उष्णता देतात. या प्रक्रियेमुळे रसातला मळ आणि तंतू वेगळे होऊन स्वच्छ, पातळ रस मिळतो. हा स्वच्छ, पातळ रस मोठ्या भांड्यांमध्ये उकळून दाट करतात. उसाचा हा दाट पाक म्हणजेच ‘काकवी’. ती थंड करताना त्यात साखरेचे स्फटिक तयार होतात. नंतर मिश्रण एका मोठ्या यंत्रात फिरवून साखरेचे स्फटिक काकवीपासून वेगळे केले जातात. तयार झालेले ओलसर साखरेचे स्फटिक वाळवल्यानंतर पांढरी दाणेदार साखर मिळते. या संपूर्ण प्रक्रियेत साखरेतली बहुतांश खनिजं आणि जीवनसत्त्वं नष्ट होतात.

गूळ तयार करताना उसापासून काढलेला रस प्रथम स्वच्छ कापड किंवा गाळणीने गाळून घेतला जातो. हा गाळलेला रस एका जाड बुडाच्या कढईत टाकून भट्टीत घट्ट, चिकट होईपर्यंत उकळला जातो. घट्ट झालेला गरम रस साच्यामध्ये किंवा ट्रेमध्ये ओतून थंड करतात. थंड झालेल्या गुळाला साच्याचा आकार येत तो घट्ट होतो. या साऱ्या प्रक्रियेत गुळातली लोह, कॅल्शियम, पोटॅशियम, मॅग्नेशियम, फॉस्फरस यासारखी पोषक द्रव्यं नष्ट होत नाहीत.

गुळामध्ये उसाच्या रसातली टिकून असलेली पोषक द्रव्यं शरीराला ऊर्जा देतात आणि रक्त शुद्ध करतात. यातल्या लोहामुळे रक्तातलं हिमोग्लोबिन वाढायला मदत होते व रक्तक्षय टाळणं शक्य होतं. गुळातली पोषक द्रव्यं शरीर सशक्त आणि निरोगी राखण्यासाठी मदत करतात.

परंतु हे जरी खरं असलं तरी, गुळाचा ‘ग्लायसेमिक इंडेक्स’ हा साखरेपेक्षा जास्त आहे. एखादा पदार्थ खाल्ल्यावर रक्तातली साखरेची पातळी किती वेगाने वाढते, हे मोजण्याचं एक मापक म्हणजे ग्लायसेमिक इंडेक्स म्हणजेच जीआय! गुळाचा जीआय हा ८४ ते ९६ आहे तर साखरेचा साधारणपणे ६५!

याचाच अर्थ साखरेऐवजी गूळ खाण्यामुळे रक्तातली साखरेची पातळी जास्त वेगाने वाढते. म्हणूनच मधुमेहासारख्या व्याधी असणाऱ्या किंवा साखर टाळणाऱ्या मंडळींनी आपल्या आहारात गुळाचा वापर डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच करावा आणि एरवीही गूळ आणि साखर यांचे गुणदोष लक्षात घेऊनच विचारपूर्वक आपला रोजचा आहार घ्यावा.

– प्रज्ञा नाडकर्णी
मराठी विज्ञान परिषद
ईमेल : office@mavipa.org
संकेतस्थळ : www.mavipa.org

उलटा चष्मा

भाषणे कमी टोमणेच जास्त!

__एकमेकांना मारलेल्या__ टोमण्यांमुळे गाजलेला राष्ट्रवादीचा मेळावा यथासांग पार पडल्यावर सर्व नेते आपापल्या निवासस्थानाकडे निघाले. घरी थोडा निवांतपणा लाभल्यावर त्यांचे विचारचक्र सुरू झाले.

__सुनील तटकरे__ – येता जाता यांना माझ्याच कुटुंबाचा उत्कर्ष दिसतो. इतके दिवस सोबत ठेवूनही स्वतःचा पुतण्या मागे का राहिला यावर हे कधी गंभीरपणे विचार करणार की नाही? अरे कबड्डी हा मैदानी खेळ तर बुद्धिबळ बैठा. राजकारणात बुद्धिबळाच्याच चाली महत्त्वाच्या असतात. नुसते कबड्डी कबड्डी म्हणून चालत नाही. कसलाही आवाज न करता संधी साधावी लागते. हे महाशय नुसता आवाज करतात. यांचा प्रत्येक गोष्टीत खळखळाटच फार. सेनेपासूनची सवय गेलीच नाही अजून. आम्ही लहानाचे मोठे झालो ते साहेबांच्या तालमीत. आवाज न करता एकाच दगडात अनेक पक्षी कसे मारायचे याची कला आहे अवगत आम्हाला. यांना जमत नसेल त्याला मी काय करणार? म्हणे, मला मुख्यमंत्रीपदाची ऑफर होती. मग घेतली का नाही? आता संतापून काय फायदा?

__धनंजय मुंडे__ – मी स्वतः पुतण्या असल्यामुळे त्याच्या वेदना काय असतात हे समजतो, पण किती काळ हे साहेब तेच चंदन उगाळणार? एकदाचे हे राज्यसभेवर गेले असते तर मला संधी मिळाली असती ना! स्वतःचा नाही तर मानलेला पुतण्याच सही असे म्हणत मन मोठे केले असते तर काय बिघडले असते? संधीचे सोने नाही तर माती केली असे मला म्हणाले. हो, आमच्या बीडच्या मातीचा गुणच आहे तो. निष्पन्न तर काहीच झाले नाही. उगीच ज्येष्ठत्वाची टिमकी वाजवत राहतात. तरुणांना कधी संधी मिळणार? एक पद सोडले की लगेच दुसरे हवे. अरे काही काळ कळ सोसा ना! आम्हीही सोसलीच की! या सगळ्या काका लोकांचा हाच प्रॉब्लेम आहे. प्रत्येक वेळी नडतात. त्यात नुकसान होते ते आमच्यासारख्या नव्या ‘दमाच्या’ नेत्यांचे.

__छगन भुजबळ__ – आज चांगलीच झडती घेतली सगळ्यांची. हो, आहे मी मैदानातला खेळाडू. दबक्या पावलांचे राजकारण कधी जमलेच नाही आपल्याला. पुतण्या मागे राहिला तो त्यामुळेच. एक हात ईडीखाली दबून आहे म्हणून, अन्यथा एकाच चालीत प्रतिस्पर्ध्यांचे अनेक खेळाडू गारद करण्याची धमक अजूनही आहे माझ्यात. म्हातारा झालो असे कुणी समजू नये. विशेषतः त्या कोकणवाल्यांनी. मराठ्यांच्या पक्षात असलेला एकमेव ओबीसी म्हणून माझी गळचेपी करता काय? माझे बाहू एकदा स्फुरले की कुणालाच ऐकत नाही मी. ज्येष्ठांचा सन्मान राखावा हेही या नेत्यांना समजत नसेल तर काय कामाचा असा पक्ष? राज्यातून मला बाद करायला निघाली होती ही चौकडी. जास्त कराल तर पक्ष कसा फोडायचा हे चांगले ठाऊक आहे मला. ‘तो छगन करी तुज टाटा’ ही सुरेश भटांची गाजलेली ओळ पुन्हा म्हणण्याची पाळी आणू शकतो सर्वांवर.

__सुनेत्रा पवार__ – काय भांडतात हे नेते म्हणवणारे लोक? दादांनी कसे सांभाळले असेल या सर्वांना. शेवटी म्हणावेच लागले- अनावश्यक हस्तक्षेप खपवून घेणार नाही म्हणून. अरे किमान अधिवेशनात तरी पक्ष कसा वाढवायचा यावर बोला ना! मला तर आताच हे सारे नकोसे झाले आहे. मात्र, बारामतीच्या रक्तातच राजकारण आहे हे ठाऊक नाही यातल्या अनेकांना. दबावाचे राजकारण सहन करणार नाही म्हणजे नाही. भविष्यात हे असेच सुरू राहिले तर थेट पार्थच्या हाती पक्षाची सूत्रे सोपवून मोकळी होईन. अभिषेक बॅनर्जीपेक्षा तो कणभरही कमी नाही. मग बसा म्हणावं बोंबलत!

राजवाडे विचारविश्व

फारशी-मराठी सान्निध्याचे गुणविशेष

‘इ.स. १३१८ मध्ये मुसुलमान राज्याधिकारी झाले व त्यांची भाषा फारशी होती, तेव्हा व्यवहार चालवण्याकरता तिचा उपयोग दरबारात होऊ लागला. पहिली पाचपन्नास वर्षे कोण्याही मराठ्याने वा ब्राह्मणाने वा कुणब्याने मुसुलमान अधिकाऱ्याची खासगी किंवा सरकारी नोकरी केली नाही. याचमुळे वेठीची जुलमी पद्धत अमलात आली. वाटेल ते सार्वजनिक काम पाहिजे तेव्हा हव्या त्या माणसांकडून जुलमाने करून घ्यावयाचे, हा वेठ या शब्दाचा अर्थ आहे. ही वेठ जेव्हा सुरू झाली, तेव्हा मात्र ब्राह्मण व मराठे कालांतराने व निरुपायाने सरकारी नोकरी करू लागले, अर्थात फारशी शब्दांची ओळखही करून घेऊ लागले...’ हे दोन लोकसमूहांच्या भाषिक देवघेवीच्या प्रारंभाचे एक कारण म्हणून ऐतिहासिक विवेचन राजवाड्यांनी केले आणि नंतर लगेच वाढत्या संपर्काचे स्पष्टीकरण देताना त्यांनी लिहिले, ‘त्यावेळी महाराष्ट्रात जे मुसुलमान आले, ते येथे कायमचे राहिले. शंभरदीडशे वर्षांत पुढे त्यांनी बरेच लोक बाटवून मुसुलमान केले.... मुसुलमान अधिकाऱ्यांच्या व फकिरांच्या तोंडून निघालेले फारशी शब्द महाराष्ट्रातील सर्व लहानमोठ्या जातींतील लोकांच्या कानांवरून हमेश जाऊ लागले व व्यवहारात जिकडेतिकडे फारशी शब्दांचा सुळसुळाट झाला.’

‘फारशी बोलणाऱ्या मुसुलमानांचे राज्य महाराष्ट्रावर ३५० वर्षे होते, त्याअर्थी मराठीत फारशी शब्द यावेत, ही साहजिक गोष्ट आहे. या दोन भाषांच्या सान्निध्यात विशेष आहे, तो निराळाच आहे’, असे सांगून राजवाड्यांनी पुढे केलेले दीर्घ सोदाहरण विवेचन म्हणजे त्यांच्या भाषाशास्त्रीय पांडित्याचा एक छोटासा नमुना होता. त्यांनी लिहिले, ‘तो विशेष म्हणजे मराठीत बरेच विशिष्ट प्रयोग फारशीवरून आलेले आहेत. शफथ खाणे असा प्रयोग मराठीत करतात. शफथ घेणे असा मूळचा मराठी प्रयोग पूर्वी होता व सध्याही चालू आहे. परंतु खाणे या क्रियापदाचा शफथेशी जोड देण्याची कल्पना फारशी प्रयोगावरून मराठीत आली आहे. फारशीत कसम् खुर्दन् असा प्रयोग असतो. कसम म्हणजे शफथ; खुर्दन म्हणजे खाणे... हाक मारणे असा आणखी एक मराठी प्रयोग आहे. जुन्या मराठीत बोलावणे व संस्कृतात निमंत्र असे शब्द आहेत. परंतु निमंत्रणं मारयति असा प्रयोग संस्कृतात नाही. बांग जदन् म्हणून फारशीत प्रयोग आहे, त्यावरून मराठीत हाक मारणे असा प्रयोग घेतलेला आहे. बांग म्हणजे हाक किंवा आरोळी; जदन् म्हणजे मारणे... तसेच याद राखणे असे मराठी संयुक्त क्रियापद आहे. ते याद दाष्तन् या फारशी प्रयोगापासून घेतले आहे. याद म्हणजे आठवण आणि दाष्तन् म्हणजे राखणे. असे शेकडो प्रयोग फारशीवरून मराठीत घेतलेले आहेत.’

नंतर मराठी-फारशी सान्निध्याचा दुसरा विशेष त्यांनी सांगितला. ‘तो हा की, कित्येक उद्गारवाचक शब्द उभयान्वयी अव्यये, शब्दयोगी अव्यये, क्रियाविशेषणे व सर्वनामे मराठीने फारशीतून घेतलेली आहेत.’ उदाहरणांचीही लगेच जोड दिली.

या परदेशी भाषेतील प्रयोगांच्या ग्रहणामुळे मराठी भाषेच्या रूपात झालेल्या फरकांची दखल तर आपण घेतलीच पाहिजे, पण मुख्य फरक कल्पनेच्या प्रांतात होतो. तो कसा, हे समजावून सांगताना राजवाड्यांनी लिहिले, ‘उदाहरणार्थ, उडी मारणे हा प्रयोग घेऊ. जुन्या मराठीत उड्डाण करतो असा प्रयोग आहे. उडी घेणे असाहि मराठीत एक प्रयोग आहे. परंतु उडी मारणे हा प्रयोग फारशीचे मराठीला सान्निध्य होईतोपर्यंत माहीत नव्हता. उडी म्हणजे उड्डाण या कर्माचा मारणे म्हणजे प्रहार करणे या क्रियेशी संबंध जोडण्याचा प्रघात फारशी प्रयोगांशी परिचय होईतोपर्यंत मराठीत नव्हता. तो फारशीवरून आपण घेतला आहे.’ राजवाड्यांची सूक्ष्म शोधक दृष्टी या विवेचनातून स्पष्ट होत होती.

– आनंद हर्डीकर
anand47.hardikar@gmail.com

ऐंशीतील ऐशीतैशी

पश्चिम आशियात इराणला केंद्रस्थानी ठेवून मंजूर झालेली शांतता इस्रायलला मान्य नसते आणि नसणार. पण नेतान्याहूंना वेसण घालण्याची कुवत ट्रम्प यांच्यात आहे?

इराण-अमेरिका यांच्यात शांतता करारावर मतैक्य झाल्याचे आणि येत्या शुक्रवारी जीनिव्हात त्यावर शिक्कामोर्तब होणार असल्याचे शुभवर्तमान अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रविवारी रात्री उशिरा जाहीर केले. हा दिवस/ती वेळ दोन्ही महत्त्वाचे. कारण सोमवारी जगभरातील भांडवली बाजार उघडतील तेव्हा तेथे उसळी दिसलीच पाहिजे अशी ट्रम्प यांची प्रामाणिक भावना. भारतासह बहुतेक देशांतील बाजारांनी त्यांना सुरुवातीस मानवंदना दिलीच. त्यांच्या अलीकडच्या काळातील घोषणांचे चक्र यापेक्षा वेगळे काय दर्शवते? कारण त्यांच्या घोषणेपश्चात ब्रेंट वायदेबाजारातील कच्च्या तेलाचे दर ८३.३३ डॉलर प्रति बॅरलवर स्थिरावले. हे दर गेल्या आठवड्यापर्यंत १०० डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास हेलकावत होते. त्याहीआधीच्या आठवड्यात तर शंभरीपार पोहोचले होते. त्या उसळीसाठी कारणीभूत असलेली होर्मुझ सामुद्रधुनीची नाकेबंदी आता त्वरित उठवली जाईल. पर्शियन आखाताला ओमानच्या आखाताशी जोडणारा हा चिंचोळा जलमार्ग जागतिक तेलकारणासाठी अत्यंत मोक्याचा. कारण एकूण जागतिक उलाढालीतील जवळपास २० टक्के खनिज तेलाची आवक-जावक येथूनच होते. इराणची नाविक नाकेबंदी करणार नाही अशी हमी अमेरिकेने दिलेली आहे. त्यामुळे इराणनेही करारासंबंधी सामंजस्य मसुद्याला होकार कळवल्याचे ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतर काही तासांनी जाहीर झाले. त्यामुळे गेले अनेक दिवस 'यांनी एक सांगायचे नि त्यांनी ते नाकारायचे' या फेऱ्यातून दोन्ही देश बाहेर पडल्याचे दिसून आले. अनिश्चिततेतून काही तरी निश्चित हाती लागले त्याचे स्वागतच. इंधनटंचाईमुळे पोळून निघालेल्या देशांनी याबद्दल सुटकेचा निःश्वास टाकला हेही स्वाभाविक.

इस्रायलच्या दुराग्रहामुळे फेब्रुवारी सरत असताना इराणवर अमेरिकेचे भीषण हल्ले सुरू झाले, तेव्हापासून संपूर्ण जग नव्याने अनिश्चिततेच्या गर्तेत ढकलले गेले. अमेरिकेने पहिल्याच प्रहारात इराणचे धार्मिक नेते अयातोल्ला खामेनी यांना संपवले. लष्करी नेतृत्वाची शीर्षस्थ फळीच कापून काढली. पण इराणचा प्रतिकार सुरूच राहिला असे नव्हे, तर तो विध्वंसकही ठरू लागला. अमेरिकेपेक्षाही या प्रतिकाराचा फटका पश्चिम आशियातील अमेरिकेच्या दोस्त अरब देशांना बसला. आजही बसतो आहे. सौदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब अमिराती, बहारिन, कुवेत या तेलसमृद्ध देशांची दुसरी ओळख अमेरिकेचे मित्र अशी होती. ती येथून पुढे वागवणे कसे जड जाणार याची वेदनादायी जाणीव इराणने त्यांना करून दिली. यांतील प्रत्येक देश इराणच्या विध्वंसक क्षेपणास्त्रांच्या टप्प्यात येतो आणि इराणने ठरवले तर त्यांचा मारा थोपवण्याची क्षमता किंवा इच्छाशक्ती विद्यमान अमेरिकी नेतृत्वाकडे नाही. गेलाबाजार ओमान आणि जॉर्डन या तुलनेने नेमस्त देशांच्या बाबतीतही हे सत्य. यांतील कोणत्याही देशाकडे होर्मुझसारख्या जलमार्गाची नाकेबंदी उठवण्याची ताकद नाही. म्हणूनच या अरब मंडळींसाठी इराणचा त्रस्त समंध शांत होणे सर्वाधिक गरजेचे होते. अमेरिकेने पुन्हा इराणची कळ काढण्याचे ठरवले तर त्याचा सर्वाधिक फटका आपल्याला बसणार याची जाणीव अरबांना झालेली आहे. त्यामुळेच इस्रायलचे नरसंहारी पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांच्याप्रमाणेच कधी काळी 'इराणला अद्दल घडवण्या'विषयी आग्रही असलेले सौदी शासक मोहम्मद बिन सलमान यांची भाषा आता बदलली. तशात अब्राहम कराराची नवी 'ट्रम्पेट' वाजवण्यास ट्रम्प यांनी सुरुवात केल्याने समस्त अरब शेख शिरोमणी सावध झाले आहेत. त्याविषयी फेरचर्चा न होताच शांतता पदरात पडत असेल तर फारच छान अशी त्यांची भावना.

शांतता करारात किंवा त्याबाबतच्या मसुद्यात दोन कळीच्या दुखण्यांचा अंतर्भाव नाही - इराणचा अण्वस्त्र विकास कार्यक्रम आणि गोठवलेल्या इराणी मालमत्तांची सोडवणूक. येत्या ६० दिवसांचा शस्त्रविराम नव्याने घोषित झाला असून त्यात या दोन मुद्द्यांवर चर्चा अपेक्षित आहे. याआधीही एप्रिल आणि मेच्या सुरुवातीस शस्त्रविरामाच्या

...नरसंहारी नेतान्याहू पुढे काय करतात किंवा त्यांना तसे करू दिले जाते यावर शांततेची शाश्वतता आणि संभाव्य संहाराची दिशा ठरेल...

घोषणा झाल्या. त्या व्यवस्थेस किती झपाट्याने तडे जाऊ शकतात हे फार मागे नाही तर गेल्याच आठवड्यात दिसून आले. अगदी ज्या रविवारी स्वतःच्या ८०व्या वाढदिवसाच्या भव्यदिव्य क्षणी ट्रम्प करार जाहीर करण्याच्या तयारीत होते, तेथे त्यांच्या सजवलेल्या ताटात इस्रायलच्या लेबनॉनवरील हल्ल्यांनी मक्षिकापात झालाच. त्यामुळे कोपित ट्रम्प यांनी मित्र नरसंहारी नेतान्याहूंना शेलक्या शिव्यांची लाखोली वाहिली. पण याचा अर्थ ते गप्प बसतील असा नव्हे. आताही इस्रायलने आपण या इराण-अमेरिका करारास बांधील नाही, अशी भूमिका घेतलेली आहे. मागील किमान दोन वेळा शांतता चर्चा अंतिम टप्प्यात असताना नेतान्याहूंनी हेझबोलावर कारवाईचे निमित्त करून लेबनॉनवर आग ओकली. त्यामुळे इराणने वाटाघाटी तात्काळ थांबवल्या. पश्चिम आशियात इराणला केंद्रस्थानी ठेवून मंजूर झालेली शाश्वत शांतता इस्रायलला मान्य नसते आणि नसणार. तेव्हा येत्या ६० दिवसांमध्ये नेतान्याहू गप्प बसतील ही शक्यता कमीच. ट्रम्प अलीकडे नेतान्याहूंवर वारंवार जाहीरपणे वैतागतात; पण नेतान्याहूंना वेसण घालण्याची त्यांची कुवत राहिलेली नाही, हा या संपूर्ण प्रक्रियेतील पुढील संभाव्य धोका. नेतान्याहूंचे राजकीय अस्तित्व पणाला लागले आहे. ट्रम्प यांच्यासाठीही पुढील काळातील राजकीय लढाई महत्त्वाची असली तरी त्यांच्या सिंहासनास तूर्त धोका नाही. कधी गाझा, तर कधी इराणनिमित्ताने नरसंहारी नेतान्याहू मतदारांना भुलवत, झुलवत राहिले. आता हे रणकंदन थंडावत असेल तर तो नरसंहारी नेतान्याहूंसाठी अस्तित्वाचा मुद्दा ठरतो. त्यामुळे वेडसर इराणी नेतृत्व आणि किंबहुना त्यापेक्षा अधिक खुळचट अमेरिकी नेतृत्व यांच्यापेक्षाही, खुनशी नि अप्पलपोटे नरसंहारी पुढे काय करतात किंवा त्यांना तसे करू दिले जाते यावर शाश्वत शांततेची किंवा संभाव्य संहाराची दिशा ठरेल.

युद्धात किंवा शांतता प्रक्रियेत सहभागी न होताही ज्या एका देशाची या काळातील अग्निवर्षावात लक्षणीय मनुष्यहानी झाली तो देश म्हणजे भारत. आपली इराणशी घनिष्ठ मैत्री, अमेरिकेशीही शत्रुत्व नाही आणि आखाती देशांशी तर आर्थिक-सांस्कृतिक मैत्रीबंध वर्षानुवर्षे घट्ट बनलेले. यांतील कोणत्याही देशाने भारतीय जीविताची हमी दिली नाही किंवा मनुष्यहानीविषयी माफी मागितली नाही. आपणही पोकळ निषेध खलिते धाडणे वा प्रसारित करण्यापलीकडे आपली वेदना दर्शवू शकलो नाही. कालपरवा अमेरिकेच्या बिनचेहऱ्याच्या कोणा मुत्सद्द्यास 'पाचारण' करून आपण निषेध व्यक्त केला. चीन किंवा युरोपीय देश अशा प्रकारे व्यक्त झाले असते? इराण, इस्रायल, अमेरिका यांच्याशी मैत्री असूनही आणि ताज्या युद्धाच्या तीव्र झळा आपल्याला पोहोचत असूनही जागतिक व्यासपीठावर आपण लेचेपेचे नाही तरी बोटचेपे तरी का राहतो? पाकिस्तानसारखे विस्कळीत देशही योग्य वेळी योग्य प्रकारची चलाखी दाखवून अशी संधी सोडत नाहीत. भारतासारख्या उभरत्या, अजस्र, आयातावलंबी, उत्पादन- बाल्यावस्थेतील देशास जागतिक शांतता, सागरी मार्गांची निर्वेधता हे सारे इंधन- खते- उद्योगमालाचे अभिसरण, कृषीमालासाठी बाजारपेठांची उपलब्धता यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. या शृंखलेत खंड पडतो तेव्हा येथे हजारो सर्वसामान्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान होते. उभे संसार देशोधडीला लागतात. त्यांच्या उत्थानासाठी नव्याने कोट्यवधी ओतावे लागतात. तेव्हा अशा संघर्षांविषयी आपण सजग आणि सव्यक्त असलेच पाहिजे. त्याऐवजी आपण व्यग्र वर्षपूर्ती कार्यक्रमांत नाही तर राजकीय काटाकाटीत!

साजरेकरणाचा आपल्याइतकाच सोस असलेल्या ट्रम्प यांनी रविवारी ऐंशीव्या वर्षात पदार्पण केले. याच शुभमुहूर्तावर त्यांना इराण युद्धामध्ये शांतता घडवून आणायची होती. इराणने त्या बेतास चकवा दिला आणि काही तास उलटल्यानंतर स्वतःच्या मर्जीने कराराच्या मसुद्यास मान्यता दिली. या युद्धाने कोणी काय मिळवले, काय गमावले, कोणी यशस्वी मध्यस्थी केली, कोण केवळ बघे ठरले इत्यादी प्रश्नांची उत्तरे लपवण्याचा प्रयत्न होईलही; पण या युद्धाने अनेकांच्या शहाणपणाची कशी ऐशी-तैशी केली ते लपवता येणे अवघड.

पाकिस्तानच्या नैतिक पराभवाची खूण!

लेख

जतिन देसाई
ज्येष्ठ पत्रकार आणि मानवाधिकारांचे अभ्यासक
jatindesai123@gmail.com

पाकव्याप्त काश्मीर हा धड पाकिस्तानचा प्रांतसुद्धा नाही- त्या भागाला पाकिस्तान 'आझाद काश्मीर' म्हणतो; पण न्याय मागणाऱ्या इथल्या जनसंघटनांवर बंदी घालणे, आंदोलन चिरडणे, लोकशाहीचा देखावा हे सारे पाकिस्तानातून केले जाते....

पाकिस्तान व्याप्त काश्मिरातील (पीओके) परिस्थिती गेल्या दोन आठवड्यांपासून पुन्हा एकदा, अतिशय स्फोटक झाली आहे. तिथल्या महत्त्वाच्या शहरांतील बाजारपेठा बंद ठेवून लोक विरोध व्यक्त करत आहेत. इथल्या लोकांच्या योग्य मागण्या चिरडून टाकण्यासाठी पाकिस्तानकडून नेहमीच पोलीस आणि लष्कराच्या पाशवी बळाचा वापर करण्यात येतो. आतादेखील पोलिसांच्या गोळीबारात व हिंसाचारात ३० जण मृत्युमुखी पडले असल्याचे म्हटले जाते. या बळींमध्ये काही मुले आणि गर्भवती महिलांचादेखील समावेश आहे. पण 'जॉइंट अवामी ॲक्शन कमिटी' या जनसंघटनेवर बंदी घालण्याचा ५ जून रोजीचा निर्णय हा ताज्या आंदोलनाचे कारण ठरला.

या पाकव्याप्त काश्मीरचे विधिमंडळ मुळात नावापुरतेच- त्याला अधिकार अत्यंत कमी. या विधिमंडळाची निवडणूक २७ जुलै रोजी आहे. 'या निवडणुकीत तरी १२ राखीव जागा रद्द करा' ही इथल्या आंदोलकांची मागणी जुनीच आहे. पण ती न्यायालयामार्फत फेटाळण्यापूर्वी पाकिस्तानच्या केंद्रीय सरकारने पाकव्याप्त काश्मीरमधल्या लोकांची संघटनाही बेकायदा ठरवली. याचे तपशील पुढे पाहू. प्रथम थोडी पार्श्वभूमी.

या पाकव्याप्त काश्मीरला पाकिस्तानात कागदोपत्री 'आझाद जम्मू-काश्मीर' म्हटले जाते. मात्र कोणत्याही अर्थाने या भागातले लोक स्वतंत्र नाहीत. या लोकांकडे- आणि लोकप्रतिनिधींकडेही- राजकीय, सामाजिक आर्थिक अधिकार नाहीत. नावासाठी तिथे पंतप्रधान आहेत पण पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबाद येथील वरिष्ठ सचिवाकडे असतात तेवढेही अधिकार 'आझाद काश्मीरच्या पंतप्रधानां'ना नाहीत. याउलट, पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांकडे देशाच्या चार प्रांतांबाबत जेवढे अधिकार आहेत त्यापेक्षा जास्त अधिकार तथाकथित 'आझाद' काश्मीरवर आहेत. इस्लामाबादेत बसून पंतप्रधान ठरवणार आणि मग या कथित 'आझाद' काश्मीरमधील सूत्रे हलणार, अशी गत. अशीच मुस्कटदाबी पाकव्याप्त काश्मीरलगतच्या गिलगिट-बाल्टिस्तान या भागाचीही होते आहे. या गिलगिट-बाल्टिस्तान भागातील निवडणूक अलीकडेच, ७ जून रोजी पार पडली. तिथे एकूण ३३ जागा असल्या तरी केवळ २४ मतदारसंघांतच सरळ मतदान होते. यापैकी १० जागांवर पीपीपीचा विजय झाला आहे. पीएमएल पक्षाला सहा तर पीटीआय समर्थकांचा दोन ठिकाणी विजय झाला आहे. अपक्ष म्हणून निवडून आलेल्या पाच जणांना महत्त्व मिळाले आहे.

गिलगिट-बाल्टिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीर हे दोन्ही भूभाग भारताचा अविभाज्य भाग असल्याची भारताची सुरुवातीपासून भूमिका राहिली आहे. गिलगिट-बाल्टिस्तान हा भाग चीन, अफगाणिस्तानला लागून असल्याने त्याला सामरिक महत्त्व आहे. या भागातून दुर्मीळ खनिजे मोठ्या प्रमाणात मिळू शकतात, म्हणून चीनची नजर त्यावर आहे. 'चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोर' इथूनच जातो. मात्र पाकव्याप्त काश्मीर हा पाकिस्तानलगत असल्यामुळे भारतात घुसखोरी करण्यासाठी सोपा. हे दोन्ही भूभाग जम्मू-काश्मीरचे महाराजा हरिसिंग यांच्या साम्राज्याचादेखील भाग होते. दोन्ही ठिकाणी पाकिस्तानने निवडणुका घेण्यास सुरुवात केली तेव्हापासून, इस्लामाबाद येथे ज्या पक्षाची सत्ता असते त्याच पक्षाचा तिथे विजय होत असतो. साहजिकच सत्ता आणि लष्कराचा वापर करून तिथल्या निवडणुका जिंकल्या जातात. भारताने सातत्याने गिलगिट-बाल्टिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीर भागात घेण्यात येणाऱ्या निवडणुकांचा विरोध केला आहे. भारताकडून बळकावलेल्या भूभागावर निवडणुका घेण्याचा किंवा त्यात काही बदल करण्याचा पाकिस्तानला अधिकार नाही, असे भारताने अनेकदा सांगितले आहे. या भागांचे शोषण पाकिस्तान करत असल्याचा आरोप वारंवार झाला आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधील लोक अनेकदा अत्याचारी पाकिस्तान सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतात. ब्रिटनच्या ५० हून अधिक खासदारांनी ब्रिटनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांना पत्र लिहून, पाकिस्तानच्या सैन्याकडून पाकव्याप्त काश्मिरात होणाऱ्या मानवाधिकाराच्या उल्लंघनाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.

पाकव्याप्त काश्मिरात विधानसभेच्या एकूण ५३ जागा आहेत. त्यापैकी ४५ जागांवर सरळ मतदान होते. उरलेल्या १२ जागा 'निर्वासितांसाठी' राखीव आहेत. भारताच्या जम्मू-काश्मीरमधून पाकिस्तानात आलेल्या लोकांसाठी या जागा (जम्मूसाठी सहा, काश्मीर खोऱ्यासाठी सहा) राखीव आहेत. मात्र या जागा खुद्द पाकव्याप्त काश्मिरात नाहीत. पाकिस्तानच्या अन्य चार प्रांतांत राहणाऱ्या भारतीय काश्मिरी निर्वासितांसाठी त्या राखीव आहेत. तेच या मतदारसंघातून निवडणूक लढू शकतात. याखेरीज उर्वरित आठ जागा महिला, टेक्नोक्रॅट व उलेमांसाठी राखीव असतात, म्हणजेच त्या आठही जागा इस्लामाबादेतील सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीने भरल्या जातात. पीओके येथील स्थानिक लोकांचा निर्वासितांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या जागांनाही विरोध आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की या भागात जे राहात नाहीत, त्यांच्यासाठी तब्बल १२ जागा राखीव ठेवणे स्थानिक लोकांवर अन्यायकारक आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये राहणाऱ्या लोकांसाठीच विधिमंडळात सगळ्या जागा असाव्यात, अशी त्यांची भूमिका आहे. इथे ४५ पैकी १२ जागा म्हणजे जवळपास २५ टक्के लोकप्रतिनिधी बिगर-स्थानिक असतात. त्यातील बहुतेक पाकिस्तानच्या सर्वात प्रभावी असलेल्या पंजाब प्रांतातून येतात. पाकिस्तानच्या राजकारणात आणि समाजकारणात पंजाबी लोकांची सर्वात महत्त्वाची भूमिका असते. निर्वासितांसाठी राखीव असलेल्या मतदारसंघातून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींवर त्यांचा दबाव असतो आणि त्यांच्या सांगण्याप्रमाणे ते वागतात, असे स्थानिक लोकांचे म्हणणे आहे. या बाहेरच्या लोकांना स्थानिक प्रश्नांची फारशी माहिती नसते. त्यामुळे स्थानिक लोकांना अधिकार मिळाले पाहिजे, ही त्यांची भूमिका आहे. 'बिगरस्थानिकांच्या राखीव जागा रद्द करा' या मागणीला ७ जून रोजीच मोठी कलाटणी मिळाली. पाकव्याप्त काश्मीरच्या सर्वोच्च न्यायालयाने, 'घटना दुरुस्ती केल्याशिवाय राखीव जागा रद्द करता येणार नाही,' असा निर्वाळा ७ जून रोजी दिला.

त्याआधी, ५ जून रोजी 'जॉइंट अवामी ॲक्शन कमिटी' वर सरकारने बंदी घातली. पाकव्याप्त काश्मिरातले स्थानिक लोक गेली कैक वर्षे विजेचा दर कमी करण्यासाठी आणि गहू स्वस्त मिळावेत यासाठी आंदोलन करत आहेत. यासाठी वेगवेगळ्या सामाजिक-राजकीय संघटना, व्यापाऱ्यांच्या व वकिलांच्या संघटना व विद्यार्थ्यांनी मिळून २०२३ मध्ये ही 'जॉइंट अवामी ॲक्शन कमिटी' स्थापन केली. तेव्हापासून या संघटनेच्या नेतृत्वाखाली लोक आंदोलन करत आहेत. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या आंदोलनात सहा रहिवासी आणि तीन पोलीस कर्मचारी असे एकंदर नऊ जण मारले गेले होते. तेव्हा पाकिस्तान सरकारने पाकव्याप्त काश्मीरच्या राजधानीत- मुझफ्फराबाद येथे एक शिष्टमंडळ पाठवून ॲक्शन कमिटीच्या प्रतिनिधींशी शांततेसाठी चर्चा केली होती. म्हणजे ज्यांच्याशी पाकिस्तान सरकार शांततेसाठी चर्चा करत होते त्याच संघटनेवर अचानक ही बंदी. या बंदीचा मानवाधिकारांसाठी काम करणाऱ्या संघटनांनी निषेध केला. निषेध करणाऱ्यांत 'ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल'चाही सहभाग आहे. याच ॲक्शन कमिटीचे एक नेते अमजद अली खान यांना गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात आरोपांची पूर्वकल्पना न देता अटक करण्यात आली होती. वकिलांच्या संघटनेने वारंवार मागणी केली असूनही, त्यांना अद्याप सोडण्यात आलेले नाही. पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मिरात अनेकदा वकील आणि त्यांच्या संघटना आंदोलनाचे नेतृत्व करत असल्याचा इतिहास आहे. अगदी २००८ च्या जून महिन्यात तेव्हाचे राष्ट्राध्यक्ष परवेझ मुशर्रफ यांच्या विरोधातला संतापही वकिलांनी ऐतिहासिक 'लाँग मार्च' काढून व्यक्त केला होता. या कमिटीचे नेते शौकत नवाब मीर, उमर नाझिर काश्मिरी, मेहरान अर्शद ख्वाजा आणि सरदार अमन हे सध्या भूमिगत आहेत... पण पाकव्याप्त काश्मीरचे सध्याचे पंतप्रधान फैसल राठोड मुमताज यांनी, या नेत्यांची माहिती देणाऱ्यांना एक कोटी पाकिस्तानी रुपयाचे (जवळपास ३६,००० अमेरिकन डॉलर) बक्षीस देण्याचे जाहीर केले आहे. ॲक्शन कमिटीची स्थापना मुळात आर्थिक संकटाच्या विरोधातून झाली होती, परंतु आता पुढच्या महिन्यात निवडणुका असल्यामुळे निर्वासितांचा मुद्दा केंद्रस्थानी आला आहे.

गिलगिट-बाल्टिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीर हे कायदेशीरपणे 'पाकिस्तानचे प्रांत' नाहीत. सरकार, विधिमंडळ हा डोलारा तिथे पाकिस्तानने उभा केला असला तरी, पाकिस्तानचे प्रांत चारच (पंजाब, सिंध, खैबर-पख्तुनख्वा आणि बलुचिस्तान). गिलगिट-बाल्टिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीर हे खरे तर व्याप्त भाग आहेत. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये अध्यक्ष, पंतप्रधान, सर्वोच्च न्यायालय इत्यादी पाकिस्तानने ताब्यात ठेवले आहे. संपूर्ण जम्मू-काश्मीरचे पाकिस्तानात विलीनीकरण हवे, असे निवेदन करणाऱ्या व्यक्ती व पक्षालाच तिथे निवडणुकीत उभे राहण्याचा अधिकार आहे. काश्मिरी स्वातंत्र्याच्या समर्थकांना तिथे निवडणुकीत उभे राहण्याचा अधिकारच नाकारण्यात येतो. पाकव्याप्त काश्मीरची खरी सत्ता इस्लामाबाद येथे असलेल्या 'काश्मीर परिषदे'कडे आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधानच या परिषदेचे प्रमुख असतात. विधिमंडळाने मंजूर केलेला कायदा नाकारण्याचा अधिकार पाकिस्तान सरकारकडे आहे. अशात, 'निर्वासितांसाठी राखीव ठेवलेल्या १२ जागांना राज्यघटनेचे संरक्षण आहे,' असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या जागा रद्द करण्याचा वा कमी करण्याचा निर्णय पाकिस्तानी घटनेत दुरुस्ती करूनच घेतला जाऊ शकतो, पंतप्रधानांना आदेशाने तो रद्द करता येत नाही असा या 'आझाद काश्मीर'मधल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अर्थ. शिवाय निवडणूक घेणे घटनात्मक आवश्यक आहे आणि आंदोलन किंवा इतर कारणांमुळे निवडणूक पुढे ढकलता येत नाही, असेही हा निकाल बजावतो.

या निकालामुळे पाकव्याप्त काश्मीरमधील आंदोलनाला धक्का बसला आहे. आंदोलनाचे केंद्र रावळकोट आहे. मिरपूर, कोटली, भिमरसारखी शहरे आंदोलनात सक्रिय आहेत. हे आंदोलन चिरडले जाण्याची प्रशासकीय तयारी संघटनेवरील बंदी आणि न्यायालयीन आदेशामुळे झालेली आहे, त्यामुळे यापुढे या आंदोलनाचे काय होते, याकडे मानवी हक्कांच्या दृष्टीनेही लक्ष ठेवावे लागेल. अमेरिका-इराण युद्धबंदी जणू आपल्यामुळेच घडल्याचे समाधान पाकिस्तानी सत्ताधारी सध्या मिळवत आहेत; पण पाकव्याप्त काश्मीर ही त्यांच्या नैतिक पराभवाची खूण ठरते आहे.

अन्वयार्थ

'हाडामांसाच्या रोबों'ना (अखेरचा) निरोप!

'संगणक अभियांत्रिकी आणि व्यवस्थापनशास्त्र- एमबीए- अभ्यासक्रमांचे युग आता संपले' हे निरीक्षण देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी एका मुलाखतीत नोंदवले. या विधानाला पुष्टी देणारे काही मुद्देही त्यांनी पुढे मांडले. भारताने जागतिकीकरण स्वीकारल्यानंतर ज्या दोन पदव्यांची आताआतापर्यंत चलती होती, त्यांचे युग संपले, असे खुद्द देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणत असल्याने त्याची दखल घेणे क्रमप्राप्त. ते असे का म्हणताहेत? या दोन अभ्यासक्रमांचे अस्तित्वच पूर्ण संपून जाणार आहे का?

संगणकशास्त्र, सॉफ्टवेअर अभियांत्रिकी, एमबीए हे अभ्यासक्रम केले की आयुष्य स्थिरावले, असा समज विशेषतः मध्यमवर्गीयांनी बाळगला होता, आहे. नागेश्वरन यांचे वक्तव्य या समजाला मोठा तडा देणारे आहेच आणि तो तडा जाणेसुद्धा आवश्यकच आहे. याचे सर्वांत महत्त्वाचे कारण म्हणजे कृत्रिम प्रज्ञा (एआय). मुळात संगणकशास्त्राशी संबंधित एखादा अभ्यासक्रम करून ज्या कामासाठी सॉफ्टवेअर अभियांत्रिकी क्षेत्रात प्रवेश मिळायचा, ते कामच 'एआय' करू लागला आहे. त्यामुळे त्यासाठी मनुष्यबळ नेमण्याची गरजच कंपन्यांना नाही. 'एमबीए'बाबतही तेच. एखाद्या कामाचे प्राथमिक विश्लेषण, विपणन यासाठी एखादे 'एआय' साधन पुरेसे असल्याने एमबीए पदवीधरांची फौज नेमण्यात हशीलच उरलेले नाही. या अर्थाने नागेश्वरन म्हणतात त्याप्रमाणे या दोन पदव्यांचे युग संपले आहे. नागेश्वरन जे म्हणत आहेत, त्याची चाहूल काही काळात लागली होती. अलीकडेच 'टीसीएस' या सॉफ्टवेअर क्षेत्रात सर्वाधिक नोकऱ्या देणाऱ्या कंपनीने म्हटले की, येत्या तीन वर्षांत कंपनीत जितके मनुष्यबळ काम करील, तेवढ्याच संख्येने त्यांच्याबरोबर 'एआय एजंट' काम करतील. याचा अर्थ सध्याच्या मनुष्यबळालाही एआय एजंटबरोबर काम करायला शिकावे लागेल. अन्यही बड्या सॉफ्टवेअर कंपन्या याच मार्गाने जायचे म्हणत आहेत. खुद्द 'अँथ्रोपिक'चा रडार चार्ट - जो कोणकोणत्या क्षेत्रात 'एआय'चा शिरकाव होऊन त्या नोकऱ्याच संपून जातील, असे दर्शवतो - त्यातही नागेश्वरन यांनी सांगितलेल्या दोन क्षेत्रांनाच सर्वाधिक धोका असल्याचे दिसते. आता दुसरा प्रश्न या दोन पदव्यांच्या अस्तित्वाचा. तर, त्याचे उत्तर 'बदल' हेच आहे. या अभ्यासक्रमांत, त्यांच्या उपयोजनांत आणि त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या रोजगारक्षमतांत वाढ करणारे बदल होत नाहीत, तोवर ते कालसुसंगत नसतील. उदा.- संगणकशास्त्र अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्यांना सध्या भरती करताना नुसता सॉफ्टवेअर डेव्हलपर चालत नाही, तर एआय असिस्टेड सॉफ्टवेअर डेव्हलपर लागतो. थोडक्यात, 'एआय' फक्त वापरता येणारे नाही, तर त्याच्याबरोबर काम करता येणारे मनुष्यबळ निर्माण करावे लागेल. पुन्हा पुढे जाऊन सगळेच काम 'एआय' करू लागल्याने ही नोकरीसुद्धा संपून जाऊ शकण्याचा धोका आहेच. म्हणूनच नागेश्वरन या मुलाखतीत पुढे जे म्हणतात की, बेरोजगारी आणि रोजगार अक्षमता या दोन्ही प्रश्नांना एकत्र भिडायची गरज आहे, तेही महत्त्वाचे.

भांडवलप्रधान उद्योग नोकऱ्यांची गरज पूर्ण करू शकणार नाहीत. वर म्हटल्याप्रमाणे या उद्योगांत 'एआय' जवळपास सर्व कामे करेल. अशा वेळी भारतात रोजगार निर्माण करू शकणारे उद्योगच वाढण्याची गरज आहे. म्हणून नागेश्वरन यांनी इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग, पाककला, रुग्णालये वा वृद्धांसाठीचे काळजीवाहक, क्रीडा शिक्षण अशा क्षेत्रांचा उल्लेख केला. या क्षेत्रांत एआय नव्हे, तर जिवंत माणसेच उपयोगी पडणार आहेत आणि याची केवळ भारताला नव्हे, तर साऱ्या जगाला गरज आहे.

नागेश्वरन यांची खंत अशी, की मानवी कौशल्ये आणि शारीरिक कष्टावर आधारित कामांचा आपण उचित आदर करत नाही. ती बरोबरच. तो आदर न रुजण्याला जातिव्यवस्थेपासून वर्गव्यवस्थेपर्यंतची सामाजिक कारणे आहेत. त्यासाठी मूठभरांनी आर्थिक सुबत्तेच्या जोरावर बहुसंख्यांना सामाजिक उणावलेपण कसे आणले, याच्या विश्लेषणात जावे लागेल. आता 'एआय' ही व्यवस्था नष्ट करील की आणखी दृढ करील, हे येणारा काळ ठरवील. पण नागेश्वरन यांच्या मुलाखतीच्या निमित्ताने इतके तरी स्पष्ट आहे की, सध्या 'एमबीए' किंवा 'सॉफ्टवेअर इंजिनीअर' होऊन नोकऱ्या मिळवणे- या नोकऱ्यांआधारे जीवनशैली बदलणे आणि मग त्या जीवनशैलीच्याच अधीन होऊन जगणे अशा यंत्रवत चक्रात अडकलेल्या 'हाडामांसाच्या रोबों'ना अखेर निरोप मिळणार आहे!

एअर इंडिया दुर्घटनेमागील कारणांचा शोध वर्षपूर्तीनंतरही अपूर्ण कसा?

विश्लेषण

सिद्धार्थ खांडेकर
siddharth.khandekar@expressindia.com

बोइंग ७८७-८ ड्रीमलायनर प्रकारातील या विमानाचे इंजिन जीई एरोस्पेस या कंपनीने बनवले होते. या कंपनीकडूनही इंजिनातील संभाव्य दोषांचा तपास सुरू आहे. निष्कर्षास विलंब लागत असल्याचे सांगितले जाते.

अंतिम अहवालाची प्रतीक्षाच?

एअर इंडियाच्या अहमदाबाद - लंडन विमानाला (उड्डाण क्र. एआय - १७१) गतवर्षी १२ जून रोजी अहमदाबादेत झालेल्या दुर्घटनेस नुकतेच एक वर्ष पूर्ण झाले. मात्र या दुर्घटनेमागील कारणांचा तपशील अजूनही जाहीर झालेला नाही. गतवर्षी प्रसृत झालेल्या प्राथमिक अहवालात दोन वैमानिकांमधील संभाषणाचा उल्लेख होता. त्यात एका वैमानिकाने इंजिनाला इंधनपुरवठा करणारा फ्युएल स्विच बंद केल्याचा उल्लेख होता. मात्र हा स्विच वैमानिकाने जाणूनबुजून किंवा चुकून बंद केला नसावा यावर अनेक आजी-माजी वैमानिक आणि काही विश्लेषक ठाम आहेत. उपकरणात वा इंजिनला इंधनपुरवठा करणाऱ्या यंत्रणेत दोष निर्माण झाला असावा, असा या मंडळींचा दावा आहे.

प्राथमिक अहवालात काय?

अपघातामागील कारणांचा प्राथमिक अहवाल भारताच्या एअर ॲक्सिडेंट इन्व्हेस्टिगेशन ब्यूरोने (एएआयबी) गतवर्षी ११ जुलैच्या मध्यरात्री प्रसिद्ध केला. यात दोन्ही इंजिनांचा इंधनपुरवठा अचानक खंडित झाल्यामुळे ती बंद पडली. त्यामुळे उड्डाण घेत असताना आवश्यक ती ताकद विमानाला मिळाली नाही आणि मिनिटभरातच ते कोसळले, असे नमूद आहे. पण हा अहवाल अपुरा असून तो घाईने लिहिल्याची टीका झाली. दुर्घटनेनंतर ३० दिवसांच्या आत प्राथमिक अहवाल आणि एका वर्षाच्या आत अंतिम अहवाल सादर करणे बंधनकारक असते. त्यानुसार ११ जुलैच्या मध्यरात्री, घटनेस ३० दिवसांची मुदत संपण्याच्या वेळी प्राथमिक अहवाल जाहीर झाला. त्यातील वैमानिकांविषयीच्या उल्लेखामुळे त्यांच्या क्षमतेविषयीच नव्हे, तर हेतूंविषयीही प्रश्न उपस्थित होऊ लागले.

वैमानिकांत अखेरच्या क्षणी काय संभाषण?

वैमानिक कॅप्टन सुमित सभरवाल (८६०० तासांचा उड्डाण अनुभव) आणि सहवैमानिक क्लाइव्ह कुंदर (११०० तासांचा उड्डाण अनुभव) हे अनुभवी वैमानिक हे विमान उडवत होते. सहवैमानिक कुंदर यांच्याकडे विमानाचे सारथ्य (कमांड) होते. कॅप्टन सभरवाल यांच्याकडे निरीक्षण आणि संज्ञापनाची (कम्युनिकेशन) जबाबदारी होती. जमिनीवरून उड्डाण घेतल्याक्षणी दोन्ही इंजिनच्या फ्युएल स्विचमध्ये 'रन' (इंधनपुरवठा सुरू) स्थितीमधून 'कट-ऑफ' (इंधनपुरवठा बंद) असा अनाकलनीय बदल झाला. सहसा असे होत नाही. मुद्दामहून दोन्ही इंजिन बंद केल्याखेरीज असे शक्य नाही. 'इंधनपुरवठा बंद का केलास?' असा प्रश्न एका वैमानिकाने दुसऱ्या वैमानिकास विचारल्याचे कॉकपिट व्हॉइस रेकॉर्डरमधील संभाषणातून स्पष्ट झाले. आपण असे काही केले नसल्याचे दुसरा वैमानिक उत्तरला. नंतर त्वरित इंधन 'स्विच ऑन' करण्यात आले. पण तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता. त्यामुळेच एका वैमानिकाने 'मे-डे' असा निर्वाणीचा इशारा दिला. पण विमान लगेच कोसळले.

दुर्मीळात दुर्मीळ घटना?

वैमानिकांच्या मूलभूत आज्ञावलीमध्ये टेक-ऑफच्या वेळी दोन्ही फ्युएल स्विचेस 'रन' पोझिशनमध्ये आणणे ही प्रक्रिया अंतर्भूत असते. लँडिंगनंतर ते ईप्सित बे मध्ये किंवा गेटसमोर स्थिरावल्यानंतरच इंधनपुरवठा खंडित करणारा कट-ऑफ स्विच दाबला जातो. ऐन उड्डाणाच्या प्रक्रियेच्या वेळी हे कधीही होत नाही. 'ऑन' व 'ऑफ' करण्याच्या प्रक्रियेत 'लॉक' ही स्थिती असते. त्यामुळे चुकून हात लागून इंजिन स्विच-ऑन किंवा स्विच-ऑफ (विमानांच्या परिभाषेत रन किंवा कट-ऑफ) होणे संभवत नाही.

दोष इंजिनातच?

'एएआयबी'चे अधिकारी गेल्या काही महिन्यांमध्ये अमेरिका आणि फ्रान्स येथे जाऊन आले. या दौऱ्यांत त्यांनी अधिक सखोल तपास केला. बोइंग ७८७-८ ड्रीमलायनर प्रकारातील या विमानाचे इंजिन जीई एरोस्पेस या कंपनीने बनवले होते. या कंपनीकडूनही इंजिनातील संभाव्य दोषाविषयी तपास सुरू आहे. त्यामुळे वर्षपूर्तीनंतरही अंतरिम स्वरूपाचे निवेदनच जारी करण्यात आले. जीईकडून इंजिनाविषयी तपास आणखी काही आठवडे सुरू राहील, असे वृत्त रॉयटर्स वृत्तसंस्थेने दिले आहे.

दैनिक जागरण

विवाद में संवाद ही सेतु बनता है

समझौता कितना टिकाऊ

अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को लेकर सहमति बनना पश्चिम एशिया के साथ-साथ पूरी दुनिया के लिए राहतकारी तो है, लेकिन जब तक इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हो जाते और यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि दोनों पक्षों में वस्तुतः किन-किन बिंदुओं पर सहमति बनी है, तब तक स्थायी शांति की आशा नहीं की जा सकती। समझौते के बिंदुओं को लेकर ईरानी मीडिया जो दावे कर रहा है, वे अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों से मेल नहीं खाते। ट्रंप कह रहे हैं कि होर्मुज समुद्री मार्ग जल्द खुल जाएगा और ईरान को वहां से निकलने वाले जहाजों से टैक्स वसूलने का अधिकार नहीं होगा, लेकिन ईरान कह रहा है कि यह समुद्री मार्ग उसकी व्यवस्थाओं के तहत खुलेगा। एक तो इसका आशय स्पष्ट होना आवश्यक है और दूसरे, करीब सौ दिन पहले अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमले करने वाले इजरायल का संतुष्ट होना भी। यह ध्यान रहे कि इजरायल कह रहा है कि वह लेबनान के उन क्षेत्रों से पीछे नहीं हटेगा, जो उसने अपने अधिकार में ले लिए हैं। उसने यह भी चेतावनी दी है कि यदि लेबनान की धरती से उस पर हमला हुआ तो ईरान समर्थित हिजबुल्ला को वह हर हाल में निशाना बनाएगा।

ईरान की ओर से भी यह रेखांकित किया जा रहा है कि अंतिम वार्ता तब तक शुरू नहीं होगी, जब तक उसकी फ्रीज संपत्तियों का कम से कम आधा हिस्सा जारी नहीं कर दिया जाता और उसके तेल पर लगे प्रतिबंध निलंबित नहीं कर दिए जाते। ऐसे में आगामी शुक्रवार तक प्रतीक्षा करनी होगी, जब जिनेवा में इस समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद अगले 60 दिन तक ईरान के साथ उसके परमाणु कार्यक्रमों और अन्य विषयों पर वार्ता होगी। स्पष्ट है कि यह भी देखना होगा कि इस वार्ता का नतीजा क्या रहता है? यदि ईरान इजरायल के लिए खतरा बने हिजबुल्ला, हमास और हाऊती जैसे संगठनों को उसके खिलाफ उकसाता रहता है तो पश्चिम एशिया कभी भी सुलग सकता है। ईरान के साथ समझौते को लेकर ट्रंप यह प्रकट कर रहे हैं कि उनके मन-मुताबिक समझौता हुआ, लेकिन सच तो यह है कि फिलहाल ईरान का पलड़ा भारी दिख रहा है और इसके लिए वही अधिक जिम्मेदार हैं। जो भी हो, होर्मुज समुद्री मार्ग के पहले की तरह खुलने एवं वहां से नौवहन में कोई बाधा न खड़ी होने से ही दुनिया की चिंताएं खत्म होंगी और तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष जो गंभीर संकट पैदा हुआ, वह दूर होगा। इसमें भी समय लगेगा, क्योंकि होर्मुज से बारूदी सुरंगों को हटाने का काम करना होगा। एक तथ्य यह भी है कि ईरान ने खाड़ी के देशों में तेल और गैस संयंत्रों पर जो हमले किए, उनके चलते वे क्षतिग्रस्त हो गए हैं और उनका उत्पादन प्रभावित हुआ है।

सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास

देहरादून में विकासनगर क्षेत्र के बैरागीवाला में पानी को लेकर हुआ विवाद दो समुदायों के बीच संघर्ष में बदल गया। दो पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई और फिर कुछ व्यक्तियों ने घेरकर एक परिवार के सदस्यों पर जानलेवा हमला कर दिया। इसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि परिवार के अन्य दो सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना को बिल्कुल भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। इस प्रकार की घटनाओं को हतोत्साहित करना बेहद जरूरी है। इस तरह की घटना न केवल आपसी सौहार्द को बिगाड़ती है, बल्कि सांप्रदायिक वातावरण को बिगाड़ने में भूमिका निभाती हैं। इसका परिणाम कानून-व्यवस्था की बदहाली के रूप में सामने आता है। ऐसी घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की शांति और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की इस घटना पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यह उचित ही है। उत्तराखंड में इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न करने के पीछे क्या कारण हैं, इसकी तह में जाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के क्रम में पुलिस आपरेशन प्रहार चला रही है। इसमें संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। विशेष रूप से प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन्हीं क्षेत्रों में हिंसा की घटनाएं भी बढ़ रही है। विकासनगर में बसने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। इस पर नजर रखी जानी आवश्यक है।

सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के प्रयासों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। इस मामले में उत्तराखंड सरकार ने सख्ती अपनाकर संदेश दिया है

फ्रांस में नई करवट लेंगे भारत-अमेरिका संबंध

डा. मनिष दाभाडे

जी-7 के दौरान मोदी को अमेरिका के समक्ष भारतीय नाविकों की मौत पर जवाबदेही की मांग के साथ ही व्यापार समझौते पर भी बात आगे बढ़ानी होगी

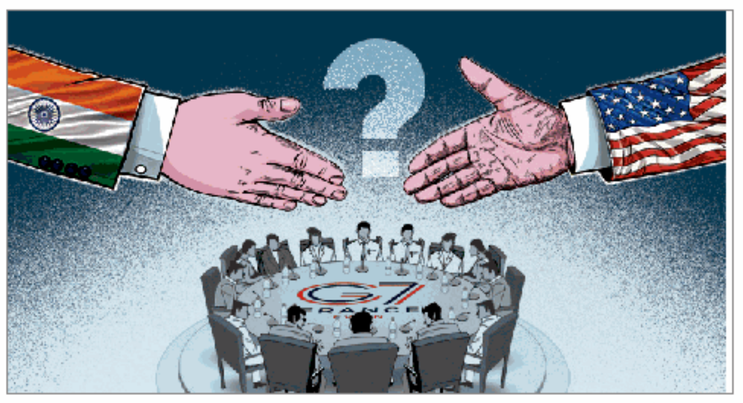

अवधेश राजपूत

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जी-7 में साझेदार देश के रूप में बुलाना भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रमाण है। जब मोदी फ्रांस के एवियां-ले-बैंस में जी-7 शिखर सम्मेलन में पहुंचेंगे, उससे ठीक पहले दुनिया एक बड़े कूटनीतिक उलटफेर की गवाह बनी है। अमेरिका और ईरान के बीच 14 जून को एक युद्धविराम समझौते पर सहमति बनी है, जिस पर 19 जून को हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस समझौते के तहत होर्मुज जलमार्ग निर्बाध रूप से खुलेगा, अमेरिकी नाकेबंदी हटेगी और परमाणु वार्ता के लिए साठ दिन का ढांचा तैयार होगा। इस समझौते ने मोदी-ट्रंप की संभावित मुलाकात का पूरा संदर्भ ही बदल दिया है और संभव है कि इसमें भारत के तीखे सवाल गौण होकर रह जाएं। ऐसा ही एक सवाल तीन नाविकों की मौत से जुड़ा है। ये अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी में मारे गए। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में अमेरिकी राजनयिक को तलब किया। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो से कहा कि यह हमला 'न्यायसंगत नहीं था।' यह विरोध सही था, लेकिन यहां एक अलग ही उलटबांसी है। वह यह कि जिस सैन्य अभियान में ये जानें गईं, उसे अमेरिका ने खुद कूटनीति से वापस खींच लिया। ये मौतें अमेरिका के उस दांव के कारण हुईं, जिसे बाद में पलट दिया गया। एवियां में मोदी को बिना किसी राजनयिक लाग-लपेगट के इन मौतों पर जवाबदेही की मांग करनी होगी।

अगर अमेरिका-ईरान समझौते पर दृष्टि डालें तो यह भारत के लिए बहुत बड़ी राहत है। होर्मुज जलमार्ग का भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्व है। भारत के कच्चे तेल आयात का लगभग चालीस प्रतिशत इसी रास्ते से आता है। गैस की आपूर्ति भी एक बड़ी हद तक इसी मार्ग के जरिये होती है। नाकेबंदी के कारण न केवल आपूर्ति बाधित थी, बल्कि ढुलाई लागत भी बढ़ गई थी। आपूर्ति श्रृंखला में गतिरोध से महंगाई का दबाव बढ़ने लगा। स्वाभाविक है कि इस जलमार्ग का खुलना भारत के लिए अच्छी खबर है। हालांकि इस खुशखबरी के बीच नाविकों की मौत के मुद्दे को अनदेखा नहीं किया जा सकता। एक परिपक्व विदेश नीति यही करती है कि समझौते के स्वागत के साथ ही नाविकों के मुद्दे पर जवाबदेही की मांग करो।

एवियां में मोदी-ट्रंप संभावित मुलाकात की बात करें तो यह पिछले वर्ष व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद दोनों की पहली द्विपक्षीय भेंट होगी। मोदी का वह अमेरिकी दौरा ठोस नतीजों का निमित्त बना था। उसमें सैन्य साझेदारी, तकनीकी हस्तांतरण और वाणिज्य के स्तर पर संयुक्त पहल शुरू हुई। सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-एआइ, क्वांटम कंप्यूटिंग और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोग का ढांचा बना, 500 अरब डालर के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य तय हुआ और मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण हुआ। इसके बावजूद व्यापार के मोर्चे पर तस्वीर जटिल बनी हुई है। फरवरी में अंतरिम समझौते की रूपरेखा तो बनी और टैरिफ 25 से 18 प्रतिशत हुआ, लेकिन आखिरी मंजिल अभी दूर है। नए श्रम-उल्लंघन शुल्क की सुनवाई जुलाई में होगी। भारतीय टेक्नोलाजी पेशेवरों के लिए एच-1बी वीजा का संकट जारी है। इसकी वजह से आठ लाख भारतीय पेशेवर प्रभावित हैं। अच्छी बात है कि जयशंकर ने यह मुद्दा सीधे उठाया है और उठाते रहना भी चाहिए।

व्यापक संबंधों की दशा-दिशा को देखें तो मई में नई दिल्ली में हुई क्वाड बैठक में हिंद-प्रशांत समुद्री निगरानी का नया ढांचा बना, महत्वपूर्ण खनिजों पर द्विपक्षीय समझौता हुआ और बीस अरब डालर की सप्लाई चेन मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई गई, जो चीन के दुर्लभ खनिजों पर वर्चस्व का जवाब है। रक्षा सहयोग अब खरीदार-विक्रेता के पुराने ढांचे से निकलकर सह-विकास और सह-उत्पादन की दिशा में बढ़ रहा है। ईरान समझौते के बाद खाड़ी क्षेत्र में स्थिरता आने से अमेरिकी रणनीतिक ध्यान हिंद-प्रशांत की ओर और मुड़ेगा और वहां भारत की केंद्रीयता बढ़ेगी ही। चीन की आक्रामकता हिमालय से लेकर दक्षिण चीन सागर तक कम नहीं हुई है और यही वह मूल कारण है, जो इस साझेदारी को अपरिहार्य बनाता है। इसके साथ ही हमें एक कड़वी सच्चाई पर भी गौर करना होगा और वह यह कि वर्ष 2047 तक तक विकसित भारत का संकल्प रणनीतिक एकाकीपन से पूरा नहीं हो पाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा वेंचर कैपिटल बाजार, सबसे उन्नत टेक इकोसिस्टम, सबसे गहन रक्षा प्रौद्योगिक आधार और भारतीय वस्तुओं के लिए सबसे विशाल बाजार, ये सब अमेरिका में ही हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में कहा भी कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता विकसित भारत की यात्रा को गति देगा। यही इस रिश्ते की असली धुरी है।

ट्रंप का दूसरा कार्यकाल अब तक भारी अनिश्चितताओं से भरा रहा है, जिसमें मोदी की नीति-संयम, स्पष्टता और टकराव से परहेज वाली रही है। यह दूरदृष्टि का ही परिचायक है। जब भारत पर टैरिफ लगे, तो जवाबी कारवाई नहीं हुई। जब दूसरे देशों ने अमेरिका-विरोधी गठबंधन का प्रलोभन दिया तो भी भारत ने जल्दबाजी नहीं दिखाई। इस संदर्भ में जयशंकर का यह कथन उल्लेखनीय रहा, 'रिश्तों में मुद्दे और मतभेद हमेशा रहेंगे, जहां मायने यह रखता है कि उनसे निपट आगे बढ़ने की क्षमता हो।' ईरान समझौता खुद इसी सबक की पुष्टि करता है कि उग्र से उग्र टकराव भी धैर्यपूर्ण कूटनीति से सुलझाए जा सकते हैं।

एवियां में मोदी को तीन काम एक साथ करने हैं। नाविकों की मौत पर ठोस जवाबदेही और भविष्य में व्यावसायिक जहाजों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्धता लेनी है, खासकर तब जब होर्मुज अमेरिका की सहमति से खुल रहा है। व्यापार समझौते के अटके अंतिम हिस्से को पूरा कराने के लिए दबाव बनाना है और दोनों देशों के बीच बनी रणनीतिक संरचना को उस नींव के रूप में पुष्ट करना है, जो किसी भी राजनीतिक तूफान से परे है। भारत-अमेरिका संबंध आज जितने गहरे हैं और जितने जरूरी हैं, इतिहास में पहले कभी नहीं थे। एवियां में संबंधों को सही दिशा में बढ़ाना होगा।

(लेखक जेएनयू में एसोसिएट प्रोफेसर और 'द इंडियन फ्यूचर्स' के संस्थापक हैं)

response@jagran.com

भविष्य की दिशा में बढ़ती भारतीय रेल

रमेश कुमार दुबे

तेज गति के साथ विद्युतीकरण के जरिये रेलवे डीजल पर निर्भरता घटाकर स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बढ़ा रहा है

स्वयं को समय के अनुरूप ढालने में जुटा रेलवे। फाइल

पिछले दिनों पश्चिम एशिया संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल-डीजल का सीमित और समझदारी से इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा दें और जहां निजी वाहन की जरूरत हो वहां कारपूलिंग अपनाई जाए। उन्होंने कहा कि हमें विदेशी मुद्रा बचानी होगी। प्रधानमंत्री की अपील का जनता पर कितना असर पड़ा यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन भारतीय रेल द्वारा विद्युतीकरण मुहिम के जरिये डीजल की बचत की जा रही है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय रेल ने विद्युतीकरण के जरिये 185 करोड़ किलो लीटर डीजल बचाया। यह मात्रा देश की कुल चार दिन की डीजल की मांग के बराबर है। सबसे बड़ी बात यह है कि विद्युत कर्षण (रेल के पहियों को खींचने में लगने वाली ऊर्जा) पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ डीजल ट्रैक्शन की तुलना में 70 प्रतिशत किफायती भी है।

उल्लेखनीय है कि 2014 से पहले देश में मात्र 21,801 किलोमीटर रेल लाइनों का विद्युतीकरण हुआ था। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने रेल विद्युतीकरण को प्राथमिकता दी। तत्कालीन रेल मंत्री के निर्देशन में रेल विद्युतीकरण मिशन शुरू किया गया। इस मिशन का लक्ष्य रेलवे के पूरे नेटवर्क का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण करना है। रेलवे ने यह मिशन डीजल इंजनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने और ट्रेनों की सामान्य गति को बढ़ाने के लिए तैयार की है। डीजल इंजनों की कार्यक्षमता काफी कम होती है और इन्हें चलाने में बहुत लागत आती है। मार्च 2026 तक रेलवे के कुल 70,175 किलोमीटर ब्राडगेज नेटवर्क में 69,906 किलोमीटर नेटवर्क का विद्युतीकरण किया जा चुका है। अर्थात कुल ब्राडगेज नेटवर्क का 99.6 प्रतिशत विद्युतीकृत किया जा चुका है। अब मात्र 269 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क ऐसा है, जिसका विद्युतीकरण किया जाना बाकी है। जिन राज्यों में रेल विद्युतीकरण अभी लंबित है, उनमें गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम और राजस्थान शामिल हैं। वर्ष 2014 से पहले देश में प्रतिदिन औसत 1.42 किलोमीटर रेल लाइनों का विद्युतीकरण हुआ। वहीं रेल विद्युतीकरण मिशन शुरू होने के बाद 2019-2025 में प्रतिदिन औसतन 15 किलोमीटर रेललाइनों का विद्युतीकरण किया गया। 2023-24 में रेल विद्युतीकरण का रिकार्ड बना जब प्रतिदिन औसतन 19.7 किलोमीटर रेल लाइनों का विद्युतीकरण हुआ। यह परिवर्तन भारतीय रेल को अधिक तेज, स्वच्छ और आत्मनिर्भर बनाते हुए नए भारत की विकास रीढ़ को और मजबूत कर रहा है।

स्पष्ट है कि 1925 में बांबे वीटी (वर्तमान छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस) और कुर्ला के बीच हार्बर लाइन पर चली पहली बिजली चालित रेलगाड़ी के 100 वर्ष बाद भारतीय रेल ने शत प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। रेल विद्युतीकरण के मामले में भारत दुनिया की कई अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ चुका है। जहां भारत में 96.6 प्रतिशत रेल लाइनों का विद्युतीकरण हो चुका है वहीं ब्रिटेन में 39 प्रतिशत, रूस में 52 प्रतिशत और चीन में 82 प्रतिशत रेलमार्गों का ही विद्युतीकरण हो पाया है। रेल विद्युतीकरण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि रेलवे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों क इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहा है। नवंबर 2025 तक रेलवे अपने कुल परिचालन में 898 मेगावाट सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा था। 2014 में मात्र 3.68 मेगावाट सौर ऊर्जा का इस्तेमाल रेलवे कर रहा था। 898 मेगावाट में से 629 मेगावाट का उपयोग रेलगाड़ियों को चलाने के लिए किया जा रहा है, जबकि 269 मेगावाट अन्य जरूरतों को पूरा करने में। इनमें स्टेशन की लाइटिंग, वर्कशाप, सर्विस बिल्डिंग और रेलवे क्वार्टर शामिल हैं।

वर्तमान में 2,626 रेलवे स्टेशन सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। इस तरह के उपाय 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारतीय रेल की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। भारत ने हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन के तहत 2030 तक प्रतिवर्ष 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन तथा 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। रेलवे ने हरित ऊर्जा स्रोतों को विविधीकरण करते हुए हरियाणा कजींद-सोनीपत रूट पर देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली 10 कोच वाली ट्रेन को मंजूरी दे दी है। इससे प्रदूषण काफी कम होगा। रेलवे अपने ऊर्जा स्रोतों को विविधीकृत कर रहा है। वर्तमान में रेलवे ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए 4,260 मेगावाट सौर और 3,427 मेगावाट पवन ऊर्जा के लिए समझौता किया है। इसके अलावा भी रेलवे ने 1,500 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अनुबंध किया है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर लिमिटेड अपने सोलर पार्क से भारतीय रेलवे को सौर ऊर्जा की आपूर्ति कर रही है। 2025-26 में रेलवे ने 81 लाख पौधे लगाए, 185 जल पुनर्चक्रण संयंत्र एवं 8,313 वर्षा जल संचयन संरचनाएं भी स्थापित किए। भारतीय रेल पर्यावरण संरक्षण में मौन क्रांति ला रहा है।

(लेखक केंद्रीय सचिवालय सेवा में अधिकारी हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

सच्चिदानंद का सामर्थ्य

यद्यपि विश्व की कोई भी भाषा जगतपति के स्वरूप तथा सामर्थ्य का वर्णन यथार्थरूप में नहीं कर सकती है, तथापि इनके नाम का पर्याय स्वरूप जो सच्चिदानंद शब्द है, वह अपने गंभीर भाव से ईश्वर की अनंत शक्ति का उद्बोधक हो जाता है। इस शब्द का पदच्छेद करने पर इसमें सत्, चित् और आनंद शब्दों का समाहन दिखता है। इनमें से सत् का अर्थ है सदा एक जैसा बना रहने वाला तथा जिसका कोई आदि, मध्य तथा अंत का पता न हो। शास्त्र कहते हैं कि यह सृष्टि पंच भौतिक तत्वों से बनी है और इसका आदि, मध्य तथा अंत सदा प्रत्यक्ष होता है। जबकि इनके अतिरिक्त कोई भी ऐसा नहीं है, जो नित्य रूप से यहां रहता हो। श्रीमद्भगवद्गीता में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि जिसने यहां जन्म लिया, उसका मरण निश्चित है, क्योंकि वह संसार अनित्य है।

यही स्थिति 'चित्' अर्थात चेतना की भी है। पूरे संसार में जो व्यक्ति अपनी चेतना का दंभ भरकर घूमता-फिरता है और अपने आपको संपूर्ण भूमि का भू-स्वामी मान कर आनंदित होता है, उसकी चेतना और आनंद कब तक रहेगा, किसी को पता नहीं, क्योंकि उसका यह चैतन्य उसका अपना नहीं है। इसीलिए उसकी नित्यता का कोई ठिकाना नहीं है।

ऐसी ही अनित्यता सांसारिक आनंद की भी है। इस धरती पर कोई भी ऐसा व्यक्ति या पदार्थ नहीं है, जो शाश्वत रूप से आपको आनंद से भर सके, जिसके बाद आपको कुछ भी पाने की इच्छा न रहे। और यदि कुछ ऐसा आपको मिल ही गया तो आपके जैसा वह भी क्षणिक और अनित्य ही है। इसीलिए शास्त्र तथा आचार्य कहते हैं कि ईश्वर का सच्चिदानंद स्वरूप ही ऐसा है जिसमें सत्, चित् एवं आनंद की पूर्णता है और सच्चिदानंद का स्मरण ही आनंद की प्राप्ति का हेतु है। व्यक्ति को इसी आनंद की प्राप्ति के लिए ही प्रयासरत रहना चाहिए।

डा. गदाधर त्रिपाठी

महिला कर्मचारियों के अधिकार का सवाल

सुनीता मिश्रा

चाइल्ड केयर लीव कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं, बल्कि कामकाजी महिलाओं की एक वास्तविक आवश्यकता है

दिल्ली हाई कोर्ट ने कामकाजी महिलाओं के हक में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि निजी स्कूलों में कार्यरत महिला शिक्षिकाओं को भी अपने बच्चों की देखभाल के लिए चाइल्ड केयर लीव (सीसीएल) पाने का अधिकार है। अदालत ने एक निजी विद्यालय की शिक्षिका की याचिका पर एकल पीठ के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें महिला को चाइल्ड केयर लीव अधिकार के रूप में देने से इन्कार कर दिया गया था। यह निर्णय केवल एक शिक्षिका को राहत देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के बीच मौजूद अधिकारों की असमानता पर भी गंभीर प्रश्न खड़ा करता है।

हाल के वर्षों में भारत में महिला कार्यबल की भागीदारी दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार, महिला श्रम बल भागीदारी दर वर्ष 2017-18 के 23.3 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 40 प्रतिशत तक पहुंच गई। यह परिवर्तन भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज दोनों के लिए सकारात्मक संकेत है। कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी न केवल समग्र उत्पादकता बढ़ाती है, बल्कि नवाचार को प्रोत्साहित करती है, परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है और देश की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को भी बढ़ाती है। इसके बावजूद परिवार और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी का बड़ा हिस्सा आज भी महिलाओं के कंधों पर ही रहता है। एक ओर उन्हें विद्यार्थियों के भविष्य का निर्माण करना होता है, तो दूसरी ओर अपने बच्चों के पालन-पोषण, स्वास्थ्य आदि का भी ध्यान रखना पड़ता है।

ऐसे में चाइल्ड केयर लीव कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं, बल्कि कामकाजी महिलाओं की एक वास्तविक और मानवीय आवश्यकता है। संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए मौलिक अधिकार के तहत प्रत्येक कर्मचारी को अपने बच्चे की देखभाल के लिए इस अवकाश को लेने का अधिकार है, जिसे संस्थान द्वारा खारिज नहीं किया जा सकता। सरकार और शिक्षा नियामक संस्थाओं को इस विषय में स्पष्ट दिशानिर्देश तैयार करने की आवश्यकता है। इनमें अवकाश की अवधि, पात्रता की शर्तें, आवेदन की प्रक्रिया एवं वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में संतुलित प्रविधान किए जा सकते हैं।

श्रम कानूनों और कार्यस्थल की नीतियों का उद्देश्य केवल उत्पादकता बढ़ाना या आर्थिक लाभ अर्जित करना नहीं है। उनका मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रत्येक कर्मचारी मानवीय अधिकारों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके। दिल्ली हाई कोर्ट का यह निर्णय इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जरूरत इस बात की है कि इसे व्यापक नीति का स्वरूप दिया जाए, ताकि निजी और सरकारी क्षेत्र की महिला कर्मचारियों के बीच अधिकारों की खाई कम हो सके।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

राम भक्तों की श्रद्धा पर आघात

'चढ़ावे की चोरी' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय पढ़ा। अयोध्या के श्रीराममंदिर के पावन परिसर से आई चढ़ावे की खबरों ने देश के करोड़ों श्रद्धालुओं को मर्मांतक वेदना से भर दिया है। हमारा यह आराध्य मंदिर सदियों के धैर्य और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जीवंत प्रतीक है। दर्शन को आए रामभक्तों द्वारा दानपात्रों में अर्पण की जाने वाली धनराशि की चोरी होना अत्यंत लज्जास्पद और पीड़ादायक है। दानपात्रों में गिरने वाली वह राशि मात्र मुद्रा नहीं, बल्कि कतारों में लगे दरिद्र नारायण की अगाध श्रद्धा और अंतर्मन के आंसुओं का अर्घ्य थी। प्रभु की सेवा के पुनीत दायित्व के बीच ऐसा घृणित कृत्य करोड़ों भक्तों के निश्छल विश्वास के कत्ल जैसा है। जहां दूर-दूर से आए श्रद्धालु भाव-विभोर होकर शीश नवा रहे थे, वहीं उत्तरदायी पदों पर बैठे कुछ लोगों द्वारा उस समर्पण को अपवित्र करना अक्षम्य है। यद्यपि शासन द्वारा विशेष जांच दल का गठन और शीर्ष स्तर पर त्वरित हस्तक्षेप एक आवश्यक कदम है, किंतु इस कृत्य से श्रद्धालुओं के आस्थावान अंतःकरण पर जो गहरा आघात लगा है, उसकी पूर्ति केवल जांच से संभव नहीं है। इस अपराध के दोषियों को कानून के दायरे में कठोर दंड दिया जाए।

प्रमोद कुमार गोयल, मेरठ

भगवान के घर में चोरी

कभी-कभी ऐसी खबरें सुर्खियां बनती हैं, जो देश की सभ्यता, संस्कृति, ईमानदारी और मानवता की छवि को गहरा आघात पहुंचाती हैं। इन दिनों यह खबर चर्चा में है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के अयोध्या मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान में कुछ लोगों ने गड़बड़ी की है। जो लोग ऐसी हरकतों को अंजाम देते हैं, उनके बारे में यही कहा जा सकता है कि जो भगवान के घर में ही बेईमानी करने का प्रयास करते हैं और भगवान से भी नहीं डरते, वे अन्य मामलों में क्या-क्या नहीं कर सकते। अयोध्या के राम मंदिर में जो कुछ भी हुआ, उसकी जितनी निंदा की जाए, कम है। हालांकि सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की है और जांच की जिम्मेदारी विशेष जांच दल (एसआइटी) को सौंपी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कुछ सिक्कों या थोड़े से लाभ के लिए लोग अपना ईमान तक बेच देते हैं? ऐसी बेईमानी करने वालों को न तो परमात्मा का भय होता है और न ही कानून का। अपार धन-दौलत, सोना-चांदी केवल मंदिरों में ही नहीं, बल्कि विभिन्न धर्मों के अनेक धार्मिक स्थलों में भी जमा है। इस संपदा का उपयोग मानव कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। इस धन-संपदा पर सवाल खड़े करना या उसे राजनीति का विषय बनाना उचित नहीं है।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

मेलबाक्स

पुरुषों को भी समझें

यह सच है कि पुरुषों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को हमारे समाज में गंभीरता से नहीं लिया जाता। पुरुषों पर पूरे परिवार को चलाने के लिए जीविका अर्जन, उनकी जरूरतों को पूरा करने का वित्तीय भार होता है। उन पर वित्तीय दायितव को लेकर सदैव एक मानसिक दबाव रहता है। हमारे समाज में बचपन से पुरुषों को रोना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना कमजोरी की निशानियां बता एक ऐसी परवरिश दी जाती है कि वे न चाहते हुए भी स्वयं को मजबूत और "सब ठीक है" दिखाते हैं। खुल कर अपने मन की बात न कहना, अपना दर्द किसी से साझा न करना और अपनी समस्या घरवालों से न बांटना, यह सब उन्हें भावनात्मक और मानसिक रूप से तोड़ देता है। उन्हें केवल परिवार के मुखिया और संरक्षक के रूप में देखा जाता है। बदलते परिवेश में विवाह के बाद अब पुरुष भी हिंसा, मानसिक और भावनातमक प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में यह आवश्यक हो गया है कि परिवार उन्हें समझे, उनकी बात सुनें और उनसे खुलकर संवाद किया जाए ताकि वे अपने मन के भाव, विचारों की अभिव्यक्ति और दर्द को व्यक्त कर सकें। पुरुषों को अपने शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर भी जागरूकता की आवश्यकता है।

अभिलाषा गुप्ता, मोहाली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:

दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,

डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा

ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी* दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

21 प्रतिशत ही थी उपस्थिति मिमी चक्रवर्ती की लोकसभा में, जब वह वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अगले पांच वर्षों तक तृणमूल कांग्रेस से सांसद रही थीं। अपने पूरे कार्यकाल में उन्होंने सदन में केवल सात बार ही अपनी बात रखी थी।

कैलाश विश्नोई
उच्च शिक्षा मामलों के जानकार

आजकल

प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न

नीट परीक्षा को लेकर हाल के वर्षों में सामने आए विवादों ने परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। इसी संदर्भ में संसदीय समिति ने अमेरिका के सैट और चीन के गाओकाओ जैसे वैश्विक माडलों से सीख लेने की संस्तुति की है। वर्ष में दो से तीन अवसर, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, मजबूत सुरक्षा तंत्र और क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्धता जैसे सुझाव केवल परीक्षा आयोजन की पद्धति बदलने का प्रयास नहीं हैं। वस्तुत: इनका लक्ष्य ऐसी मूल्यांकन व्यवस्था विकसित करना है जो सुरक्षा, समावेशन और विश्वसनीयता के नए मानक स्थापित कर सके

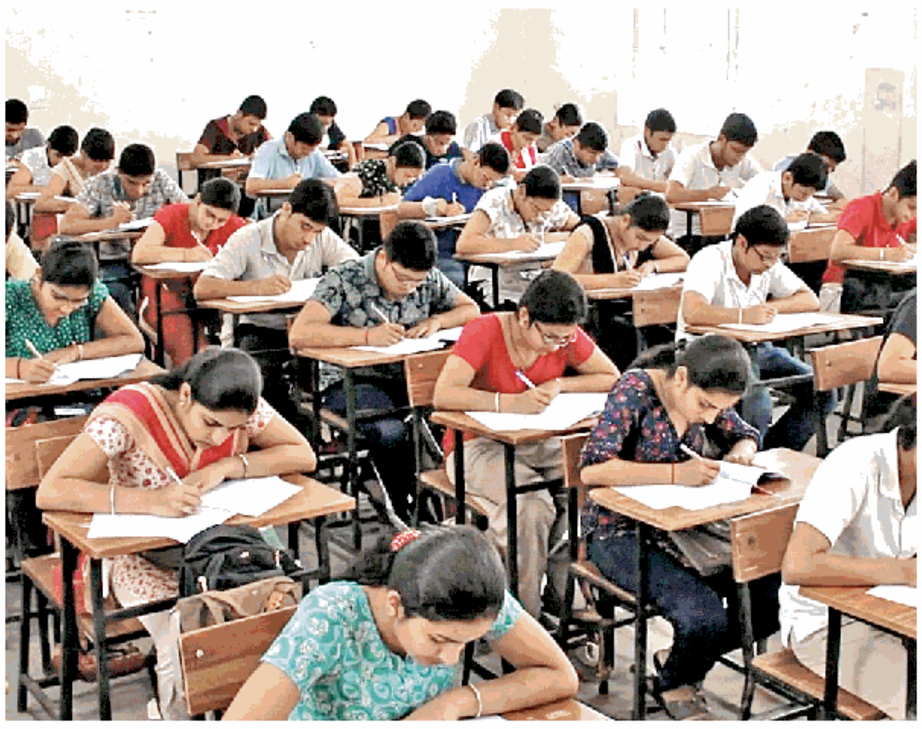

प्रतियोगी परीक्षाओं की पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता होने से उसकी विश्वसनीयता कायम रहती है। फाइल

भारत में प्रतियोगी परीक्षाएं केवल चयन का माध्यम नहीं हैं, वे करोड़ों युवाओं की आकांक्षाओं, परिवारों के सपनों और राष्ट्र की मानव संसाधन निर्माण प्रक्रिया का आधार भी हैं। विशेष रूप से राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) अब केवल एक परीक्षा नहीं रह गई है, यह देश के चिकित्सा शिक्षा तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश-द्वार व्यवस्था बन चुकी है। ऐसे में जब इस परीक्षा की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगते हैं, तब केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था की विश्वसनीयता कठघरे में खड़ी दिखाई देती है।

इसी संदर्भ में संसदीय समितियों द्वारा प्रस्तुत हालिया सिफारिशें महज प्रशासनिक सुधारों का दस्तावेज नहीं हैं, बल्कि वे भारत की परीक्षा प्रणाली के व्यापक पुनर्गठन की दिशा में एक गंभीर विमर्श का संकेत भी देती हैं। इन सुझावों के केंद्र में परीक्षा की सुरक्षा, अभ्यर्थियों का मनोवैज्ञानिक कल्याण, संस्थागत जवाबदेही व तकनीकी आधुनिकीकरण जैसे अनेक आयाम निहित हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव वर्ष में दो या तीन बार नीट आयोजित करने का है। यह विचार केवल परीक्षा की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मूल्यांकन दर्शन (असेसमेंट फिलासफी) में एक मौलिक परिवर्तन का संकेत देता है। वर्तमान व्यवस्था में एक ही दिन और कुछ घंटों का प्रदर्शन किसी विद्यार्थी के वर्षों के परिश्रम का निर्णायक आधार बन जाता है। ऐसी संरचना स्वाभाविक रूप से अत्यधिक तनाव, अनिश्चितता और मनोवैज्ञानिक दबाव उत्पन्न करती है।

अमेरिका में स्कालास्टिक असेसमेंट टेस्ट तथा अमेरिकन कालेज टेस्टिंग जैसी परीक्षाओं का बहु-अवसर माडल इसी कारण विकसित हुआ था कि किसी एक दिन की असफलता किसी छात्र के पूरे भविष्य का निर्धारण न कर दे। यदि भारत भी इसी दिशा में आगे बढ़ता है तो यह विद्यार्थियों के लिए अधिक मानवीय, समावेशी और लचीली परीक्षा व्यवस्था का निर्माण कर सकता है। साथ ही, यदि किसी परीक्षा में तकनीकी अथवा प्रशासनिक गड़बड़ी हो जाए तो इस कारण लाखों छात्रों का एक पूरा शैक्षणिक वर्ष दांव पर नहीं लगेगा, हालांकि यह प्रस्ताव जितना आकर्षक प्रतीत होता है, उतना ही जटिल भी है। बहु-स्तरीय परीक्षा प्रणाली का अर्थ है अधिक प्रश्नपत्र निर्माण, विस्तृत सुरक्षा प्रबंधन, अनेक मूल्यांकन चक्र, स्कोर सामान्यीकरण तथा परिणामों की तुलनीयता सुनिश्चित करना। भारत जैसे देश में यह कार्य केवल प्रशासनिक इच्छाशक्ति से नहीं, बल्कि परिष्कृत संस्थागत क्षमता से संभव होगा।

कंप्यूटर आधारित परीक्षा/ सीबीटी की दिशा में बढ़ने का विचार इसी व्यापक परिवर्तन का हिस्सा है। वस्तुतः प्रश्नपत्र लीक की अधिकांश घटनाएं छपाई, पैकेजिंग, परिवहन तथा भंडारण की पारंपरिक प्रक्रिया से जुड़ी रही हैं। यदि प्रश्नपत्र डिजिटल एन्क्रिप्शन के माध्यम से परीक्षा प्रारंभ होने के कुछ मिनट पूर्व ही केंद्रों तक पहुंचें और निर्धारित समय पर विशेष कोड द्वारा खुलें, तो सुरक्षा जोखिमों में कमी लाई जा सकती है।

परंतु समझना होगा कि टेक्नोलाजी स्वयं कोई जादुई समाधान नहीं है। तकनीकी व्यवस्था उतनी ही विश्वसनीय होती है जितनी उसकी संरचना, निगरानी और रखरखाव व्यवस्था। ग्रामीण भारत के अनेक क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, बिजली आपूर्ति तथा डिजिटल अवसंरचना अभी भी समान स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं। यदि तकनीकी संक्रमण सामाजिक और भौगोलिक असमानताओं को बढ़ा देता है, तो सुधार का उद्देश्य ही प्रभावित हो सकता है। यही वजह है कि किसी भी सीबीटी माडल को चरणबद्ध, परीक्षण-आधारित तथा समावेशी दृष्टिकोण के साथ लागू करना होगा।

ऐसे में बायोमेट्रिक सत्यापन और चेहरे की पहचान प्रणाली की सिफारिश भी समयोचित प्रतीत होती है। डमी उम्मीदवार, साल्वर गैंग और प्रतिरूपण की घटनाएं केवल परीक्षा सुरक्षा को नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की अवधारणा को भी आघात पहुंचाती हैं। जब कोई अयोग्य व्यक्ति छलपूर्वक अवसर प्राप्त करता है, तब वास्तव में किसी योग्य विद्यार्थी का अधिकार छिनता है। फिर भी यहां गोपनीयता, डाटा सुरक्षा तथा डिजिटल राइट्स के प्रश्नों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

इस पूरी बहस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की संस्थागत स्थिति से जुड़ा हुआ है। संसदीय पैनल ने जिस प्रकार यूपीएससी और सीबीएसई का उदाहरण देते हुए एनटीए की कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठाए हैं, वह केवल आलोचना नहीं, बल्कि एक गहरी संस्थागत समीक्षा की मांग है। यूपीएससी की विश्वसनीयता किसी एक नियम या तकनीक से नहीं बनी। वह दशकों की संस्थागत संस्कृति, स्वायत्तता, पेशेवर दक्षता और उत्तरदायित्व का परिणाम है। यदि एनटीए को वास्तव में राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली का केंद्रीय स्तंभ बनना है, तो उसे भी वैधानिक दर्जा, स्पष्ट जवाबदेही संरचना तथा दीर्घकालिक संस्थागत स्वायत्तता प्रदान करनी होगी।

नीट विवाद ने देश को असहज प्रश्नों के सामने लाकर खड़ा किया है। यदि संसदीय समितियों की संस्तुतियों को दूरदर्शिता, संतुलन और दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ लागू किया गया, तो संभव है कि आने वाले वर्षों में भारत केवल विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा प्रणाली का ही नहीं, बल्कि सबसे विश्वसनीय प्रणाली का भी उदाहरण बन सके। जब व्यवस्था यह भरोसा दिला सके कि अवसर समान हैं, प्रक्रिया निष्पक्ष है और परिणाम योग्यता आधारित हैं, तभी शिक्षा व्यवस्था अपने वास्तविक लोकतांत्रिक उद्देश्य को प्राप्त कर सकेगी।

सामाजिक न्याय और अवसर की समानता का सिद्धांत

प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और भर्ती घोटालों की घटनाएं अब अलग-अलग मामलों की सूची भर नहीं रह गई हैं। वे भारतीय परीक्षा प्रणाली के समक्ष खड़े एक गहरे संस्थागत संकट का संकेत बन चुकी हैं। वर्ष 2021 की यूपीटीईटी परीक्षा हो, राजस्थान की रीट भर्ती, बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, तेलंगाना लोक सेवा आयोग का भर्ती घोटाला, 2024 का नीट और यूजीसी-नेट विवाद अथवा 2024 की उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा, हर घटना एक ही प्रश्न पूछती दिखाई देती है कि क्या देश की चयन और मूल्यांकन व्यवस्था अपनी विश्वसनीयता बचा पाने की स्थिति में है। दुखद तथ्य यह है कि प्रत्येक विवाद के बाद जांच बैठती है, गिरफ्तारियां होती हैं, समितियां गठित होती हैं, किंतु कुछ समय बाद वही प्रश्न किसी नई परीक्षा के साथ पुनः खड़ा हो जाता है। समस्या अब किसी एक परीक्षा या एक एजेंसी की नहीं रह गई है। यह शैक्षिक प्रशासन, परीक्षा प्रबंधन और सार्वजनिक संस्थाओं में घटते विश्वास का प्रश्न बन चुकी है।

इस संकट की जड़ को केवल तकनीकी कमजोरी या सुरक्षा चूक के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसके पीछे एक व्यापक परीक्षा उद्योग विकसित हो चुका है, जिसमें राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक शिथिलता, शिक्षा माफिया, तकनीकी एजेंसियां और कुछ मामलों में कोचिंग नेटवर्क तक की संदिग्ध भूमिका की चर्चा बार-बार सामने आती रही है। इस समस्या का एक सामाजिक और आर्थिक पक्ष भी है, जिस पर गंभीरता से चर्चा नहीं होती। भारत में सरकारी क्षेत्र में रोजगार केवल नौकरी नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक प्रतिष्ठा का माध्यम माना जाता है। यही कारण है कि एक-एक परीक्षा में लाखों अभ्यर्थी शामिल होते हैं। सीमित अवसर और विशाल प्रतिस्पर्धा का यह अंतर कुछ लोगों को अनैतिक रास्तों की ओर धकेलता है। जिनके पास आर्थिक संसाधन और प्रभाव है, वे परीक्षा प्रणाली में सेंध लगाने का प्रयास करते हैं, जबकि परिश्रम और योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने वाला सामान्य अभ्यर्थी स्वयं को असहाय महसूस करता है। परिणामस्वरूप चयन प्रक्रिया की मेरिटोक्रेटिक प्रकृति प्रभावित होती है। इससे केवल योग्य युवाओं का अवसर नहीं छिनता, बल्कि सार्वजनिक संस्थानों में दक्ष मानव संसाधन के स्थान पर संदिग्ध योग्यता वाले व्यक्तियों के प्रवेश का खतरा भी बढ़ जाता है। किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए इससे अधिक चिंताजनक स्थिति नहीं हो सकती।

स्थिति को और गंभीर बनाने वाला पहलू न्यायिक और प्रशासनिक विलंब है। अक्सर पेपर लीक या भर्ती अनियमितता के मामले वर्षों तक जांच और मुकदमों में उलझे रहते हैं। इस दौरान हजारों अभ्यर्थियों की आयु सीमा समाप्त हो जाती है, कैरियर योजनाएं प्रभावित होती हैं और मानसिक तनाव असाधारण स्तर तक पहुंच जाता है। कई बार परीक्षाएं रद होती हैं, फिर पुनर्परीक्षा आयोजित होती है, उसके बाद परिणाम न्यायालय में चुनौती का विषय बन जाते हैं। ऐसे वातावरण में युवाओं के भीतर संस्थागत अविश्वास पनपना स्वाभाविक है। किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी उसका युवा वर्ग होता है। यदि वही वर्ग यह महसूस करने लगे कि परिश्रम से अधिक प्रभाव और धन निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं, तो यह केवल परीक्षा प्रणाली की समस्या नहीं रह जाती, बल्कि सामाजिक न्याय और अवसर की समानता के सिद्धांत पर भी प्रश्नचिह्न लग जाता है।

स्पष्ट है कि अब आंशिक सुधारों से काम नहीं चलेगा। आवश्यकता चयन और भर्ती प्रक्रिया में संरचनागत बदलाव की है। रीक्षा केवल चयन की प्रक्रिया नहीं होती, वह समाज में अवसर की समानता और योग्यता आधारित प्रगति के विश्वास की आधारशिला भी होती है। इसलिए पेपर लीक को एक अपराध नहीं, बल्कि राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास के विरुद्ध गंभीर चुनौती के रूप में देखने की आवश्यकता है। (कैलाश बिश्नोई)

खरी-खरी

मुद्दों से भटकाव

राजेंद्र कुमार सिंह

यदि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपके पैर खींचने और मीनमेख निकालने वालों की कमी नहीं होगी। यह परंपरा नई नहीं है, सदियों पुरानी है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम तक इससे अछूते नहीं रहे। उनके जीवन और निर्णयों पर भी प्रश्न उठाए गए। आलोचना का दंश उन्होंने भी झेला। किंतु समय की कसौटी पर उनके व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा बनी रही और वे आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्मरण किए जाते हैं।

आज के दौर में भी तस्वीर बहुत अलग नहीं है। जो व्यक्ति, संस्था या विचार आगे बढ़ता दिखाई देता है, उसके प्रति कुछ लोगों के भीतर ईर्ष्या का अंकुर फूटने लगता है। हमारे देश में एक दिलचस्प परंपरा और भी है। जब कोई ऐसा मुद्दा उभरता है जिससे सत्ता, व्यवस्था या प्रभावशाली लोगों की असहजता बढ़ सकती है, तब अचानक कोई दूसरा विवाद सुर्खियों में आ जाता है। ऐसा लगता है मानो असली मुद्दे पर पर्दा डालने के लिए नया मंचन शुरू कर दिया गया हो।

हाल के दिनों में पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता का प्रश्न देशभर में चर्चा का विषय बना। यह केवल एक प्रशासनिक गड़बड़ी नहीं थी, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनके सपनों से जुड़ा मामला था। स्वाभाविक रूप से इस पर गंभीर बहस होनी चाहिए थी। लेकिन तभी समानांतर विवादों की एक नई फसल उगती दिखाई दी। मूल मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए बहस का केंद्र बदलने लगा। परिणाम यह हुआ कि असली प्रश्न पीछे छूटता गया और कृत्रिम विवाद आगे निकलते गए।

सएक ही दिशा में चलने वाले लोग आपस में उलझ पड़े। बहस मुद्दे पर कम और व्यक्तियों पर अधिक होने लगी। जनता पहले जैसी भोली नहीं रही। वह समझने लगी है कि जब भी कोई ऐसा मुद्दा सामने आता है जो सत्ता या व्यवस्था को असहज कर सकता है, तब अक्सर बहस की दिशा बदलने की कोशिशें तेज हो जाती हैं। नया विवाद पैदा कर पुरानी परेशानी को ढंकने का प्रयास किया जाता है। लेकिन हर बार यह रणनीति सफल हो जाए, ऐसा भी नहीं है। कभी-कभी जनता मुद्दे और भटकाव के बीच का अंतर पहचान लेती है। तब सारा तिलिस्म टूटने लगता है।

पोस्ट

भारत में अब एक ऐसी पार्टी भी होगी, जिसे बिना चुनाव लड़े ही रातोंरात 20 लोकसभा सदस्य मिल गए।
साहिल जोशी@sahiljoshii

जेवर की माटी से विमान की पहली उड़ान ने आसमान चूमा, तो हर उत्तर प्रदेश वासी का मन गर्व से झूम उठा है। यह देखना सबसे सुखद रहा कि इस ऐतिहासिक उड़ान के यात्री वे 172 किसान भाई-बहन बने, जिन्होंने विकास के लिए अपनी जमीन सहर्ष अर्पण की थी। उनका लखनऊ पधारना एक गौरवशाली क्षण रहा।
मालिनी अवस्थी@maliniawasthi

दुनिया अब एक सप्ताह का भी और युद्ध बर्दाश्त नहीं कर सकती। यदि अमेरिका और ईरान वास्तव में किसी समझौते पर पहुंच गए हैं तो यह निश्चित ही स्वागतयोग्य है। हालांकि असली चुनौती अब शुरू होगी, जिसमें होर्मुज जलमार्ग को खुला और शुल्क-मुक्त रखने के साथ ही ऊर्जा एवं व्यापार के प्रवाह को सामान्य बनाए रखना होगा। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को बहुत क्षति पहुंचा ली, अब परस्पर लाभ सुनिश्चित करने वाली शांति के लिए साझा प्रयास करें।
मिलिंद देवरा@milinddeora

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या भारत वैश्विक झटकों को सहन करने के लिहाज से बेहतर स्थिति में है?

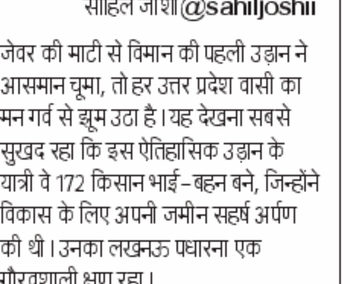

सभी आंकड़े प्रतिशत में

आज का सवाल

क्या ईरान-अमेरिका के बीच समझौते से दोनों के बीच स्थायी शांति संभव दिख रही है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है

जनपथ

खैर मनाओ हो गया बड़े युद्ध का अंत,
ट्रंप-मोजतबा बन गए सीधे-सादे संत।
सीधे-सादे संत किया आखिर समझौता,
हो करके बर्बाद शांति को भेजा न्यौता।
नेता का शव शांति पूर्वक अब दफनाओ,
पुन: न बिगड़े मूड ट्रंप का खैर मनाओ!
-ओम प्रकाश तिवारी

जयकृष्ण वाजपेयी
राज्य ब्यूरो प्रमुख, बंगाल

बंगाल डायरी

ग्लैमर की सियासत, खोखली विरासत

तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद व अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती (बाएं) और नुसरत जहां (दाएं)। फाइल

भारतीय राजनीति और सिनेमा का रिश्ता बहुत पुराना है। दक्षिण भारत में एमजी रामचंद्रन या एनटी रामाराव ने जब रुपहले पर्दे से निकलकर सत्ता के शीर्ष को छुआ, तो वह केवल एक चुनावी समझौता नहीं था। वह विचारधारा और संगठन के धरातल पर बुनी गई एक मजबूत राजनीतिक जमीन थी। राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस ने अमिताभ बच्चन या सुनील दत्त के जरिये इस ग्लैमर को भुनाया, तो भाजपा ने 'रामायण' और 'महाभारत' के दौर में अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को इसके जरिये नई धार दी। लेकिन बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी ने साल 2009 से मनोरंजन जगत के सितारों पर जिस तरह की 'संस्थागत निर्भरता' दिखाई, उसने राजनीति के स्थापित व्याकरण को ही बदल कर रख दिया। दीदी स्वयं इस रंगमंच की सबसे बड़ी निर्माता और निर्देशक बनकर उभरीं। उन्होंने टालीवुड की चमक को चुनावी नैया पार लगाने का 'शार्टकट' तो बनाया, लेकिन समय के क्रूर पहिए ने आज यह साबित कर दिया है कि यह 'स्टार-मोह' न तो राज्य के हित में रहा और न ही स्वयं उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता के पक्ष में।

साल 2026 के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने इस ग्लैमरस तिलिस्म को पूरी तरह तोड़ दिया है। तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे कई सितारे परास्त हो चुके हैं, तो वहीं 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने वाली फिल्मी हस्तियां जैसे शताब्दी राय और सायोनी घोष बागी हो चुकी हैं। यह सांगठनिक बिखराव साफ बता रहा है कि बंगाल में ग्लैमर की सियासत अंततः एक खोखली विरासत ही साबित हुई है। यही कारण है कि सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की नई कैबिनेट के 41 मंत्रियों की सूची में टालीवुड का एक भी चेहरा शामिल नहीं है।

अब टालीवुड के भीतर से ही 'राजनीति मुक्त फिल्म उद्योग' की आवाजें मुखर होने लगी हैं। सुप्रसिद्ध अभिनेत्री-निर्माता ऋतुपर्णा सेनगुप्ता जहां नए मंत्रियों से जनता की बुनियादी जरूरतें पूरी करने और कलाकारों के लिए एक सुरक्षित कार्यक्षेत्र की गुहार लगा रही हैं, वहीं सिनेमा हाल के मालिक अरिजीत दत्त जैसे लोग बेबाकी से पूछ रहे हैं कि चाहे संसद हो या विधानसभा, इन सितारों ने अपनी कला और फिल्म उद्योग के पुनरुद्धार के लिए आखिरकार किया ही क्या है?

दीदी की इस 'स्टार ब्रिगेड' की सबसे बड़ी विफलता यह रही कि इनमें से अधिकांश चेहरे सालभर की मैदानी और सांगठनिक राजनीति के लिए कभी बने ही नहीं थे। इनका चरित्र किसी गंभीर राजनेता का नहीं, बल्कि 'सभा-शिल्पी' जैसा था, जिनका काम केवल रैलियों में मंच की शोभा बढ़ाना था।

लेकिन इस ग्लैमरस सिक्के का दूसरा पहलू जनता के साथ एक बड़ा लोकतांत्रिक धोखा था। राजनीति में आने की कोई वैचारिक प्रतिबद्धता न होने का खामियाजा अंततः आम मतदाता और संसदीय मर्यादाओं को भुगतना पड़ा। उदाहरण के तौर पर, जाधवपुर जैसी प्रतिष्ठित सीट से महज 30 साल की उम्र में सांसद बनीं मिमी चक्रवर्ती की पांच साल में संसद में उपस्थिति केवल 21 प्रतिशत थी और उन्होंने पूरे कार्यकाल में सिर्फ सात बार अपनी बात रखी। तीन बार के सांसद देव (दीपक अधिकारी) का रिकार्ड तो और भी निराशाजनक रहा, अपने तीसरे कार्यकाल में उनकी उपस्थिति घटकर महज आठ प्रतिशत रह गई और उन्होंने एक बार भी सदन में जनहित की आवाज नहीं उठाई। मुनमुन सेन, संध्या राय और नुसरत जहां का भी कमोबेश यही हाल रहा।

जब भाजपा ने राज्य में अपनी जमीन मजबूत करनी शुरू की, तो उसने भी कुछ हद तक इसी राह पर चलते हुए रूपा गांगुली, बाबूल सुप्रियो, रुद्रनील घोष और लाकेट चटर्जी जैसे चेहरों को आगे किया। लेकिन हालिया चुनावों ने साफ कर दिया कि जनता अब जागरूक हो चुकी है। इस बार का चुनाव व्यक्तियों के ग्लैमर पर नहीं, बल्कि 'प्रतीकों', जन-सरोकारों और काम के मुद्दों पर लड़ा गया, जहां तृणमूल के सितारे धराशायी हो गए और केवल सक्रिय चेहरे ही टिक पाए।

ममता बनर्जी ने जिस राजनीतिक थियेटर का निर्माण किया था, उसमें स्टार वैल्यू तो भरपूर थी, लेकिन 'कंटेंट' पूरी तरह गायब था। नतीजतन, आज वह रंगमंच बिखर चुका है। इस पूरे घटनाक्रम से भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ा सबक निकलता है- राजनीति में लोकप्रियता किराए पर ली जा सकती है, लेकिन जन-आकांक्षाओं के प्रति जवाबदेही और सांगठनिक निष्ठा का कोई विकल्प नहीं हो सकता। यदि राजनीति की जमीन को बचाना है, तो रैलियों के 'सभा-शिल्पियों' को छोड़कर

मंथन

नए भारत के निर्माण की राह

तमाम सामाजिक चुनौतियों के बीच आज सबसे बड़ी चुनौती प्रतिबद्धता का संकट है। ऐसे में यदि कोई संस्था पिछले सौ वर्षों से राष्ट्र निर्माण में निरंतर सक्रिय है तो उसका योगदान अतुलनीय है

डा. सुकांशिका वत्स
असिस्टेंट प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय

अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों के आपसी मेलजोल से निकलती है एकता की राह। फाइल

आधुनिक भारत की सबसे बड़ी सामाजिक चुनौती के रूप में बेरोजगारी, शिक्षा, तकनीक, सामाजिक विषमता जैसे अनेक मुद्दे हैं। किंतु इन सबके बीच एक संकट ऐसा भी है जिसकी चर्चा अपेक्षाकृत कम होती है। यह है प्रतिबद्धता का संकट। वस्तुतः हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां विकल्प तो बहुत हैं, लेकिन निष्ठाएं कम होती जा रही हैं। लोग संस्थाओं से जुड़ते हैं, पर लंबे समय तक नहीं। किसी संगठन के साथ कुछ वर्षों तक चलना कठिन हो गया है। ऐसे समय में यदि कोई संस्था एक शताब्दी तक स्वयं को बनाए रखती है, और कार्यकर्ताओं की नई पीढ़ियां तैयार करती है, तो वह भी अध्ययन का विषय बन जाती है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसी ही एक संस्था है। संघ के बारे में मतभेद हो सकते हैं और होने भी चाहिए। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में यह स्वाभाविक है। किंतु मतभेदों से परे एक प्रश्न ऐसा है जो गंभीरता से पूछे जाने योग्य है। आखिर वह कौन-सी शक्ति है जो व्यक्ति को केवल समर्थक नहीं, आजीवन कार्यकर्ता बना देती है? संघ को समझने की सबसे बड़ी भूल शायद यह है कि उसे केवल राजनीति के दायरे में समझा जाए। राजनीति उसके प्रभाव का एक आयाम हो सकती है, किंतु उसकी संपूर्ण व्याख्या नहीं।

जो संस्थाएं केवल परिणामों के आधार पर अपने कार्य का मूल्यांकन करती हैं, वे परिस्थितियों के साथ बदल जाती हैं। किंतु जो संस्थाएं अपने कार्य को एक सतत साधना के रूप में देखती हैं, वे समय के साथ गहरी जड़ें विकसित करती हैं। संघ के संदर्भ में यह बात उसके प्रचारकों और पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं के जीवन में सबसे अधिक दिखाई देती है। भारत को केवल मानचित्र पर नहीं समझा जा सकता। उसे लोगों, भाषाओं, परिवारों, त्योहारों और स्मृतियों के माध्यम से समझा जाता है। संभवतः यही कारण है कि संघ की संगठनात्मक यात्रा केवल विचारों के प्रसार की यात्रा नहीं रही, बल्कि संबंधों के निर्माण की यात्रा भी रही है। एक मराठी भाषी स्वयंसेवक असम में काम करता है, एक उत्तर भारतीय दक्षिण भारत में, एक दक्षिण भारतीय पंजाब में।

भाषाई अस्मिता के बीच संतुलन : भारत की भाषाई विविधता उसकी सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है, किंतु यही विविधता समय-समय पर सार्वजनिक बहस का विषय भी रही है। कौन-सी भाषा पढ़ाई जाए, किस भाषा को कितना महत्व दिया जाए, राष्ट्रीय एकता और भाषाई अस्मिता के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाए, जैसे प्रश्न स्वतंत्रता के बाद से ही भारतीय सार्वजनिक जीवन में उपस्थित रहे हैं। इसीलिए नई शिक्षा नीति के अंतर्गत त्रिभाषा सूत्र पर जोर दिया गया है। वस्तुतः भारत में भाषाई विविधता केवल सांस्कृतिक विशेषता नहीं, बल्कि सामाजिक वास्तविकता है। यह प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या भारत की अगली पीढ़ी केवल भाषाई सीमाओं के भीतर विकसित होगी, या वह देश की सांस्कृतिक विविधता से भी परिचित होगी?

त्रिभाषा सूत्र का महत्व केवल भाषाई दक्षता तक सीमित नहीं है। उसका गहरा संबंध राष्ट्रीय एकात्मता से है। जब उत्तर भारत का एक विद्यार्थी दक्षिण भारत की किसी भाषा से परिचित होता है, या दक्षिण भारत का कोई विद्यार्थी हिंदी अथवा किसी अन्य भारतीय भाषा के माध्यम से देश के व्यापक सामाजिक अनुभव को समझने का प्रयास करता है, तब भाषा केवल संचार का साधन नहीं रहती। वह भारत को समझने का माध्यम बन जाती है। वस्तुतः स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यह थी कि विविधताओं से भरे इस देश में एकता की ऐसी भावना कैसे विकसित की जाए जो राजनीतिक सीमाओं से आगे बढ़कर सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी अनुभव की जा सके।

आज जब डिजिटल माध्यमों ने लोगों को विश्व से जोड़ दिया है, तब यह सुनिश्चित करना और भी आवश्यक हो गया है कि भारत का युवा भारत से भी जुड़ा रहे। वह केवल वैश्विक नागरिक न बने, बल्कि भारतीय समाज की बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक और बहुस्तरीय वास्तविकताओं को भी समझे।

संघ के बारे में सहमति व असहमति दोनों रहेंगी। यह स्वाभाविक भी है। किंतु एक तथ्य अपनी जगह बना रहता है। लगभग एक शताब्दी तक किसी संस्था का बने रहना, बदलती परिस्थितियों के बीच स्वयं को पुनर्गठित करते रहना और नई पीढ़ियों को जोड़ते रहना एक असाधारण सामाजिक घटना है। शायद इसी कारण संघ को समझने के लिए केवल उसकी विचारधारा को पढ़ना पर्याप्त नहीं है। उसके समय-बोध को भी समझना होगा। क्या आज के भारत में ऐसी अन्य संस्थाएं भी हैं जो कई पीढ़ियों के क्षितिज पर सोचती हैं? यदि नहीं, तो शायद हमें केवल संघ को नहीं, बल्कि अपने समय को भी समझने की आवश्यकता है।

बिजनेस

मई में यात्री वाहनों की थोक बिक्री 27 प्रतिशत बढ़ी

नई दिल्ली: मई 2026 में यात्री वाहनों की थोक बिक्री 27.3 प्रतिशत बढ़कर 4,38,854 इकाई रही है। वाहन निर्माताओं के संगठन सियाम के अनुसार, इसमें जीएसटी दरों में कमी और आसान फाइनेंसिंग का प्रमुख योगदान रहा है। मई 2025 में यात्री वाहनों की थोक बिक्री 3,44,656 इकाई रही थी। डाटा के अनुसार, पिछले महीने दोपहिया की थोक बिक्री 14.8 प्रतिशत बढ़कर 19,02,209 इकाई रही है, जो पिछले वर्ष समान महीने में 16,57,116 इकाई रही थी। (प्रेट्र)

भारतीय शेयर बाजार को वैश्विक व घरेलू घटनाक्रमों के कारण निकट भविष्य में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अंतत : ये नई सर्वकालिक ऊंचाइयों को छुएंगे।

– नीलेश शाह, प्रबंध निदेशक, कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी

सेंसेक्स	76,264.33 ▲ 736.38	निफ्टी	23,853.90 ▲ 231	सोना प्रति दस ग्राम	₹ 1,59,400 ▲ ₹ 2,500	चांदी प्रति किलो ग्राम	₹ 2,60,700 ▲ ₹ 5,000	$ डालर	₹ 94.58 ▼ ₹ 0.60	कूड प्रति बैरल	$ 82.90

एक नजर में

एचसीएलटेक सर्वम एआइ में 10.46% हिस्सा खरीदेगी

नई दिल्ली: आइटी कंपनी एचसीएल टेक सरकार के समर्थन वाले सावरेन एआइ माडल डेवलपर सर्वम एआइ में 1,427 करोड़ रुपये में 10.46 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की योजना बना रही है। कंपनी ने रेग्युलेटरी फाइलिंग में बताया कि सर्वम एआइ का मूल्य 1.5 अरब डालर आंका गया है और उम्मीद है कि समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद दो सप्ताह में यह सौदा पूरा हो जाएगा। एचसीएल टेक ने फाइलिंग में कहा है कि इस लेन-देन के लिए किसी रेग्युलेटरी मंजूरी की जरूरत नहीं है। (प्रेट्र)

रेजरपे ने जमा किए आइपीओ दस्तावेज

नई दिल्ली: फिनटेक फर्म रेजरपे ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ) लाने के लिए गोपनीय रूट के जरिये सेबी के पास मसौदा दस्तावेज जमा किए हैं। सूत्रों के अनुसार, इस आइपीओ का आकार 5-6 हजार करोड़ रुपये हो सकता है। हालांकि, कंपनी ने आइपीओ के आकार की जानकारी नहीं दी है। रेजरपे पेमेंट स्वीकार करने, बैंकिंग, पेआउट, पेरोल, लेंडिंग और दूसरी वित्तीय सेवाएं देती है। वहीं, एडविट ज्वेल्स ने अपने 165 करोड़ रुपये के आइपीओ का प्राइस बैंड 130-138 रुपये प्रति शेयर तय किया है। (प्रेट्र)

18 जून को एक्सचेंज से हट जाएंगे जेएएल के शेयर

नई दिल्ली: जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) के शेयर 18 जून को दोनों प्रमुख एक्सचेंजों बीएसई और एनएसई से हट जाएंगे। कंपनी ने रेग्युलेटरी फाइलिंग में बताया कि उसे शेयरों को हटाने के लिए बीएसई और एनएसई से मंजूरी मिल गई है। जेएएल को दिवालिया प्रक्रिया के जरिये अदाणी एंटरप्राइजेज ने खरीद लिया है। नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की इलाहाबाद पीठ की ओर से मंजूर की गई समाधान योजना के अनुसार जेएएल के शेयरों को दोनों स्टाक एक्सचेंज से हटाया जा रहा है। (प्रेट्र)

पीएम की अपील के बाद भी सोना आयात बढ़ा

मई में 3.4 अरब डालर पर रहा पीली धातु का आयात, यह पिछले वर्ष के समान महीने से 34% ज्यादा

- पश्चिम एशिया संकट के बावजूद मई में निर्यात 18 प्रतिशत बढ़कर 45.20 अरब डालर रहा
- मई में 73.41 अरब डालर का आयात भी किया गया, व्यापार घाटा 28 अरब डालर का रहा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : पश्चिम एशिया संकट के बीच सोने के आयात को रोकने के उपायों का असर नहीं दिख रहा है। गत 10 मई को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से सोने की खरीदारी एक साल के लिए टालने की अपील की थी। साथ ही सोने के आयात शुल्क को बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया। फिर भी गत मई माह में सोने का आयात पिछले साल मई के मुकाबले 34 प्रतिशत बढ़कर 3.4 अरब डालर रहा। पिछले साल की समान अवधि में सोने का आयात 2.5 अरब डालर था।

चालू वित्त वर्ष के पहले दो महीनों अप्रैल व मई को मिलाकर सोने के आयात में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 66 प्रतिशत का इजाफा रहा। हालांकि, पिछले महीने चांदी का आयात 86.65 प्रतिशत घटकर 7.55 करोड़ डालर रहा है। मई 2025 में 56.62 करोड़ डालर की चांदी का आयात किया गया था।

वहीं पश्चिम एशिया संकट व अन्य वैश्विक अस्थिरता के बावजूद चालू वित्त वर्ष 2026-27 में निर्यात में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। सोमवार को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक मई में वस्तु निर्यात में पिछले साल मई के मुकाबले 18 प्रतिशत का इजाफा रहा। इस साल अप्रैल में वस्तु निर्यात में 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। मई में 45.20 अरब डालर का वस्तु निर्यात रहा जो किसी महीने में होने वाला अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। हालांकि मई में 73.41 अरब डालर का आयात भी किया गया, इसलिए व्यापार घाटा भी 28 अरब डालर का रहा।

पश्चिम एशियाई देशों को होने वाले निर्यात में भी दिखी वृद्धि

मई में मुख्य रूप से पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रानिक्स गुड्स, फार्मा, केमिकल्स, जेम्स व ज्वेलरी जैसे आइटम के बेहतर निर्यात प्रदर्शन से कुल निर्यात का अच्छा प्रदर्शन रहा। अब पश्चिम एशिया देशों में होने वाले निर्यात में भी गत मार्च व अप्रैल के मुकाबले बढ़ोतरी दिख रही है। इसके अलावा, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, वियतनाम जैसे देश निर्यात के नए बाजार के रूप में उभर रहे हैं। मई में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले निर्यात में तो 116 प्रतिशत तो तंजानिया में 196 प्रतिशत का इजाफा रहा।

> ईरान व अमेरिका के बीच युद्ध को लेकर होने वाली डील टिकाऊ रही तो इससे हमारी कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पश्चिम एशिया के देशों में अप्रैल में 4.2 अरब डालर का निर्यात किया गया था। मई में यह निर्यात बढ़कर 5.3 अरब डालर का हो गया।
>
> **-राजेश अग्रवाल**, वाणिज्य सचिव

विदेशी मुद्रा भंडार हो रहा था प्रभावित

पश्चिम एशिया संकट शुरू होने के बाद महंगे पेट्रोलियम पदार्थों से देश का विदेशी मुद्रा भंडार प्रभावित होने लगा और कुल आयात में कमी लाने के उद्देश्य से ही प्रधानमंत्री ने लोगों से सोने की खरीदारी को टालने की अपील की थी। ताकि विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाया जा सके। वित्त मंत्रालय के सूत्रों का भी मानना है कि भारत में सोना लोगों की भावना से जुड़ा है और एक सीमा से अधिक इसकी खरीदारी को हतोत्साहित करना संभव नहीं है।

खाद्य पदार्थों में तेजी से मई में थोक महंगाई 9.68% रही

नई दिल्ली, प्रेट्र: ईंधन-बिजली, मैन्यूफैक्चरिंग और खाने की चीजों की कीमतों में तेज वृद्धि से मई में थोक महंगाई बढ़कर 9.68 प्रतिशत हो गइ। अप्रैल में यह आंकड़ा 8.26% था। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने सोमवार को थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआइ) पर आधारित महंगाई का आंकड़ा जारी किया, जिसमें आधार वर्ष को 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया गया।

मई में ईंधन और बिजली की थोक महंगाई दर बढ़कर 30.33 प्रतिशत हो गई जबकि अप्रैल में यह 24.89 प्रतिशत थी। कच्चे पेट्रोलियम उत्पादों की महंगाई दर 61.51 प्रतिशत थी जबकि पिछले महीने यह 56.31 प्रतिशत थी। थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर में तेज वृद्धि में तेज वृद्धि पश्चिम एशिया संकट और होर्मुज स्ट्रेट में चल रही नाकाबंदी के असर को दिखाती है। इस रास्ते से ही ज्यादातर कच्चा तेल भारत में आयात किया जाता है और इसका असर खाने की चीजों की कीमतों पर दिखता है। खाद्य पदार्थों की महंगाई मई में 3.60 प्रतिशत रही जबकि अप्रैल में यह 2.43 प्रतिशत थी। आंकड़ों से पता चलता है कि मैन्यूफैक्चरिंग उत्पादों की महंगाई दर मई में बढ़कर 7.48 प्रतिशत हो गई जो अप्रैल में 6.68 प्रतिशत थी। खुदरा या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ) पर आधारित महंगाई भी मई में बढ़कर 16 महीने के सबसे ऊंचे स्तर 3.93 प्रतिशत पर पहुंच गई है जबकि अप्रैल में यह 3.48 प्रतिशत थी।

- सरकार ने जारी किए आंकड़े, आधार वर्ष को 2011-12 से बदलकर 2022-23 किया गया
- ईंधन-बिजली की थोक महंगाई बढ़कर 30.33% हुई, पेट्रोलियम उत्पादों की 61.51% रही

पहली बार जारी हुआ उत्पादन मूल्य सूचकांक, डब्ल्यूपीआइ की जगह लेगा

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने महंगाई मापने के ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआइ) को नए उत्पादक मूल्य सूचकांक (पीपीआइ) से बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगले पांच वर्षों तक दोनों सूचकांक समानांतर रूप से जारी किए जाएंगे और इसके बाद डब्ल्यूपीआइ को जारी करना बंद कर दिया जाएगा। मई, 2026 के लिए सभी कमोडिटीज के लिए आल इंडिया आउटपुट पीपीआइ 109.6 है, जबकि अप्रैल 2026 में यह 108.6 था। डब्ल्यूपीआइ और पीपीआइ दोनों के आंकड़ों के लिए संशोधित आधार वर्ष 2022-23 है और इसमें 957 उत्पाद शामिल हैं।

वित्तीय उत्पादों की गलत बिक्री पर रोक के लिए नए नियम जारी

- डिजिटल इंटरफेस में डार्क पैटर्न के उपयोग पर लगाया प्रतिबंध
- एक जनवरी 2027 से लागू होंगे केंद्रीय बैंक के नए नियम

मुंबई, रायटर: आरबीआइ ने सोमवार को वित्तीय उत्पादों की गलत बिक्री पर रोक लगाने के लिए नए नियम जारी किए। इनमें धोखाधड़ीपूर्ण बिक्री टेक्नोलाजी पर प्रतिबंध और ग्राहक की सहमति तथा बिक्री के संबंध में मानकों को कड़ा किया गया है।

केंद्रीय बैंक ने डिजिटल इंटरफेस में ''डार्क पैटर्न'' के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया है, जो ग्राहकों को भ्रमित करते हैं। आरबीआइ ने कहा कि बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान और उनके एजेंट अब वेबसाइटों, मोबाइल एप व अन्य बिक्री चैनलों पर डार्क पैटर्न का उपयोग नहीं कर सकेंगे। यह निर्देश फरवरी में केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा में गवर्नर की घोषणाओं के बाद आए हैं।

नए नियमों के अनुसार, बैंकों व वित्तीय संस्थानों को अपने इंटरफेस का समय-समय पर आडिट कराना होगा ताकि वे अनुचित विशेषताओं की पहचान कर सकें और उन्हें हटा सकें। यह नियम आरबीआइ जिम्मेदार व्यापार आचरण दिशानिर्देशों में संशोधनों का हिस्सा हैं और एक जनवरी, 2027 से लागू होंगे। केंद्रीय बैंक ने गलत बिक्री की एक व्यापक परिभाषा भी प्रस्तुत की है, जिसमें ग्राहकों के लिए अनुपयुक्त उत्पादों की पेशकश, भ्रामक जानकारी प्रदान करना, ग्राहक से स्पष्ट सहमति प्राप्त किए बिना उत्पाद बेचना और अनिवार्य रूप से उत्पादों को एक साथ बेचना शामिल है। यदि किसी वित्तीय उत्पाद या सेवा की गलत बिक्री स्थापित होती है, तो बैंक को पूरी राशि वापस करनी होगी और ग्राहक को बिक्री रद करने की सूचना देनी होगी।

मई में बेरोजगारी दर घटकर 5.5% रही

नई दिल्ली, प्रेट्र : मई में 15 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए कुल बेरोजगारी दर थोड़ी कम होकर 5.5 प्रतिशत हो गई है, जबकि एक साल पहले यह 5.6 प्रतिशत थी। मई, 2026 के आवधिक श्रम बल सर्वे (पीएलएफएस) अनुसार, इस साल अप्रैल में 15 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए कुल बेरोजगारी दर 5.2 प्रतिशत थी। मई, 2026 में ग्रामीण बेरोजगारी दर अप्रैल के 4.6 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर 5.1 प्रतिशत हो गई जबकि शहरी बेरोजगारी दर अप्रैल के 6.6 प्रतिशत से कम होकर मई में 6.4 प्रतिशत हो गई। मई, 2025 की तुलना में शहरी बेरोजगारी दर 6.9 प्रतिशत से घटकर 6.4 प्रतिशत हो गई। शहरी बेरोजगारी दर मई, 2025 के बाद सबसे कम रही। 15 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) मई, 2026 में 54.4 प्रतिशत रहा जबकि अप्रैल, 2026 में यह 55.0 प्रतिशत था।

वेदांता समूह से अलग हुईं चारों कंपनियां शेयर बाजार में सूचीबद्ध

दिनभर कारोबार के बाद चारों कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए, बीएसई और एनएसई पर उपलब्ध हैं शेयर

नई दिल्ली, प्रेट्र: वेदांता समूह से अलग हुईं चारों कंपनियों वेदांता एल्युमिनियम मेटल, वेदांता पावर, वेदांता आयल एंड गैस और वेदांता आयरन एंड स्टील सोमवार को शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो गईं।

वेदांता एल्युमिनियम मेटल के शेयर बीएसई पर 527 रुपये पर सूचीबद्ध हुए और बाद में पांच प्रतिशत गिरकर 500.65 की निचली सर्किट सीमा पर पहुंच गए। वेदांता पावर 41.30 पर लिस्ट हुआ, लेकिन 0.84 प्रतिशत गिरकर 40.95 पर बंद हुआ। इंट्रा-डे में यह 4.96 प्रतिशत बढ़कर 43.35 रुपये पर पहुंच गया था। वेदांता आयल एंड गैस के शेयर 39 पर लिस्ट हुए और पांच प्रतिशत नीचे 37.05 रुपये के निचले सर्किट स्तर पर पहुंच गया। वेदांता आयरन एंड स्टील के शेयर 22.25 रुपये पर सूचीबद्ध हुए और 5.39 प्रतिशत गिरकर 21.05 पर बंद हुए। चारों कंपनियां एनएसई पर भी सूचीबद्ध हुईं।

वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा, 'उस दिन हमने जो बीज बोया था, वह एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ बन गया है। उसके नीचे उगाए गए पौधे अब खास सेक्टर में बड़ी कंपनियां बनने और तेज ग्रोथ में अहम योगदान देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की इकोनमी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) और ऊर्जा बदलाव सबसे आगे होंगे वह बहुत ज्यादा खनिज, धातु और ऊर्जा पर आधारित होगी।

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

अप्रैल में 4.7 अरब डालर सरप्लस रहा चालू खाता

मुंबई, प्रेट्र: इस वर्ष अप्रैल में भारत का चालू खाता 4.7 अरब डालर सरप्लस रहा है। आरबीआइ के अनुसार, यह वृद्धि उच्च सेवा निर्यात और शुद्ध हस्तांतरण प्राप्तियों के कारण हुई है। पिछले वर्ष समान महीने में 4.8 अरब डालर का घाटा हुआ था। आरबीआइ डाटा के अनुसार, अप्रैल में आयात बिल 72.5 अरब डालर रहा, जो पिछले वर्ष के 65.8 अरब डालर से अधिक है। इसी तरह, निर्यात 44.6 अरब डालर रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 38.7 अरब डालर की तुलना में अधिक है। भुगतान संतुलन (बीओपी) के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, वस्त्र व्यापार घाटा अप्रैल 2026 में 27.9 अरब डालर रहा, जो अप्रैल 2025 के 27.1 अरब डालर से थोड़ा अधिक है। अप्रैल 2025 में शुद्ध सेवा प्राप्तियां 18.6 अरब डालर रही।

अंतरराष्ट्रीय

रूस के हमले में यूक्रेन का एक हजार वर्ष पुराना कैथेड्रल बर्बाद

यूक्रेन के पेचेर्स्क लावरा स्थित डोर्मिशन कैथेड्रल में रूसी ड्रोन हमले के बाद लगी आग बुझाने में जुटे दमकल वाहन और उठते धुएं का हवाई दृश्य। रायटर

- यूनेस्को के विश्वदाय स्थलों की सूची में है शामिल
- रूसी हमलों में 9 लोग मारे गए, 39 घायल हुए

कीव, रायटर : रूस के बड़े हवाई हमले में सोमवार को यूक्रेन की राजधानी कीव में स्थित एक हजार वर्ष पुराना यूनेस्को के विश्वदाय भवनों की सूची में शामिल कैथेड्रल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस मठ का यूक्रेन की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में बड़ा महत्व है। रूस के ताजा हमलों में सबसे ज्यादा पांच लोग यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्कीव में मारे गए और पांच घायल हुए जबकि कीव में चार लोग मारे गए और 34 घायल हुए हैं। एक व्यक्ति अन्य स्थान पर मारा गया है।

जेलेंस्की ने क्षतिग्रस्त कैथेड्रल का दौरा करने के बाद एक्स पर पोस्ट अपने बयान में कहा, 11 वीं सदी में निर्मित कैथेड्रल और चर्च पेचेर्स्क लावरा पर हमला कर रूस ने यूक्रेन के इतिहास पर चोट की है। यह ईसाई संस्कृति के खिलाफ रूस सबसे बड़ा अपराध है। उन्होंने देश को आश्वस्त किया कि हमले से हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। जबकि रूस ने कैथेड्रल पर हमले से इन्कार किया है। कहा है कि ऐतिहासिक-धार्मिक भवन पर गिरी मिसाइल अमेरिका की पैट्रियट डिफेंस मिसाइल थी जो अनियंत्रित होकर कैथेड्रल पर जा गिरी। इस मिसाइल को यूक्रेन की सेना ने दागा था। जबकि फ्रांस ने इस हमले की तुलना पेरिस के नोट्रे डाम कैथेड्रल पर द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान बमबारी से की है। उल्लेखनीय है कि रूस ने यूक्रेन पर ताजा हमले में 70 मिसाइलों और 611 ड्रोन का इस्तेमाल किया था। रविवार को यूक्रेन ने भी रूस के तुला शहर के औद्योगिक क्षेत्र पर ड्रोन हमला किया। इस हमले में एक वर्ष के एक बच्चे समेत तीन लोग मारे गए और कई घायल हुए हैं।

यूक्रेन पर यह हमला रविवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर वार्ता के बाद हुआ। इस वार्ता में जेलेंस्की ने चार वर्ष से जारी यूक्रेन युद्ध के खत्म होने की इच्छा जताई थी। इस वार्ता के बाद रविवार को ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी ट्रंप से बात की थी। रूस ने कहा है कि वह यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता को स्वीकार करेगा लेकिन पुतिन की जेलेंस्की से मुलाकात पर रूस ने कुछ नहीं कहा है।

ब्रिटेन ने रूसी शैडो फ्लीट पर छापेमारी कर एक भारतीय को गिरफ्तार किया

लंदन, प्रेट्र : रूस पर पश्चिमी देशों की पाबंदियों के कथित उल्लंघन के मामले में ब्रिटेन के अधिकारियों ने एक भारतीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी एक आपरेशन के दौरान की गई, जिसका मकसद इंग्लिश चैनल में रूस के शैडो फ्लीट (गुप्त बेड़े) के एक आयल टैंकर को रोकना था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीएर स्टार्मर ने रविवार को पुष्टि की रायल मरीन कमांडो और नेशनल क्राइम एजेंसी (एनसीए) के खास तौर पर ट्रेंड कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने 'स्मर्टोस' जहाज पर चढ़कर कार्रवाई की। एनसीए के मुताबिक, जहाज पर 24 भारतीय और जार्जियाई क्रू सदस्य मौजूद हैं और वे जांच में मदद कर रहे हैं। एनसीए के प्रवक्ता ने कहा, 14 जून की सुबह रूस के शैडो फ्लीट के जहाज को रोके जाने के बाद अधिकारियों ने पाबंदियों के उल्लंघन के शक में 38 वर्षीय भारतीय नागरिक को गिरफ्तार किया। हालांकि, उन खास अपराधों के बारे में साफ तौर पर नहीं बताया गया, जिनके लिए गिरफ्तारी हुई।

ब्रिटेन में भी 16 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया एप्स के उपयोग पर प्रतिबंध

- ब्रिटेन के पीएम स्टार्मर ने की घोषणा, कहा- किशोरों की 'खुशी और सुरक्षा' के लिए फैसला
- टिक-टाक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, यू-ट्यूब जैसे एप पर रोक होगी प्रभावी, पर वाट्सएप को छूट

लंदन, प्रेट्र : आस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मलेशिया के बाद अब ब्रिटेन ने भी 16 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया एप्स का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने सोमवार को घोषणा की कि किशोरवय के इन सभी बच्चों के लिए यह ऐप्स प्रतिबंधित रहेंगे ताकि उनकी 'खुशी और सुरक्षा' सुनिश्चित की जा सके।

प्रधानमंत्री स्टार्मर ने संबोधन में कहा कि यह निर्णय एक प्रधानमंत्री और किशोर बच्चों के पिता के रूप में सही है। उन्होंने स्वीकार किया कि इस तरह के प्रतिबंध को लागू करना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें दुनिया की कुछ सबसे शक्तिशाली तकनीकी कंपनियों का समावेश है, लेकिन बच्चों का स्वास्थ्य और कल्याण सर्वोपरि है। स्टार्मर ने कहा, यह हमारे बच्चों और हमारे भविष्य के लिए एक बड़ा कदम है, क्योंकि आज मैं घोषणा कर सकता हूं कि सरकार 16 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया तक पहुंच पर प्रतिबंध लगाएगी। उन्होंने कहा, यह कोई हल्का निर्णय नहीं है और मेरे लिए यह स्पष्ट है कि पूर्ण प्रतिबंध सही विकल्प है। यह घोषणा एक लंबी परामर्श प्रक्रिया के बाद की गई, जिसमें उन माता-पिता का योगदान शामिल था, जिनके बच्चों पर टिक-टाक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब जैसे इंटरनेट मीडिया एप्स के हानिकारक प्रभाव पड़े हैं।

कानून पर अमल अगले साल वसंत में : ब्रिटेन में हालांकि वाट्सएप जैसे मैसेजिंग एप को प्रतिबंध में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन गेमिंग सेवाओं और लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफार्मों को, जहां अज्ञात लोग बच्चों से संपर्क कर सकते हैं, एक उम्र सत्यापन प्रणाली के माध्यम से प्रतिबंधित किया जाएगा।

गेमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफार्मों पर कार्रवाई

प्रतिबंध कैसे कार्य करेगा, इसके विवरण आगे चलकर संस्कृति, मीडिया और खेल मंत्रालय से प्राप्त डाटा के आधार पर सामने आने की उम्मीद है। ब्रिटेन की यह कार्रवाई आस्ट्रेलिया के बाद आई है, जिसने दिसंबर में प्रतिबंध लागू किया था। फ्रांस, ग्रीस, डेनमार्क व कनाडा की सरकारों ने भी नाबालिगों को इंटरनेट मीडिया से दूर रखने संबंधी बिल लाने की तैयारी की है। स्टार्मर ने कहा, हम केवल प्रतिबंध नहीं ला रहे, हम जहां कहीं भी वर्तमान में अज्ञात लोग किसी भी बच्चे से बिना जांच के संपर्क कर सकते हैं, ऐसी गेमिंग सेवाओं और लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफार्मों पर विश्वस्तरीय कार्रवाई कर रहे हैं।

भारतीय सेना ने नेगेव मशीन गन के लिए इजरायली कंपनी की टेलीस्कोपिक साइट चुनी

यरुशलम, प्रेट्र : भारतीय सेना ने नेगेव मशीन गन के लिए इजरायली कंपनी की दिन के समय इस्तेमाल होने वाली टेलीस्कोपिक साइट (दूरबीन) को चुना है। इसकी मदद से दूर के लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाना आसान हो जाता है। इजरायली कंपनी मेप्रोलाइट की मेप्रो एक्स6 एक फिक्स्ड 6एक्स मैग्निफिकेशन वाली टेलीस्कोपिक साइट है, जिसे असाल्ट राइफल, लाइट मशीन गन और दूसरे हथियार के लिए बनाया गया है, जिनमें सटीकता, मजबूती और बेहतरीन आप्टिकल परफार्मेंस की जरूरत होती है।

इन साइट्स की डिलीवरी भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बीईएल) के जरिये की जाएगी। मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए मेप्रोलाइट ने आरआरपी डिफेंस के साथ टेक्नोलाजी ट्रांसफर का समझौता किया है।

कंपनी भारत में मेप्रो एक्स6 के पूरे प्रोडक्शन के लिए जरूरी जानकारी, प्रक्रिया और मैन्युफैक्चरिंग क्षमताएं ट्रांसफर करेगी।

पिचाई के भाषण शुरू करते ही स्टैनफोर्ड के कई छात्रों ने किया वाकआउट

- गूगल के इजरायल से क्लाउड-कंप्यूटिंग डील से थे खफा

सुंदर पिचाई। फाइल

न्यूयार्क, प्रेट्र : अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में रविवार को दीक्षा समारोह के दौरान जैसे ही गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने संबोधन शुरू किया, 200 के करीब छात्रों ने फलस्तीन के समर्थन में नारे लगाए और वहां से वाकआउट कर गए। पिचाई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र रह चुके हैं। वे 135वें दीक्षा समारोह में छात्रों को संबोधित करने पहुंचे थे। दरअसल, फलस्तीन समर्थक छात्रों ने कंपनी के इजरायली सरकार के साथ संबंधों की निंदा की, खासकर 2021 में देश के साथ हुई 1.2 अरब अमेरिकी डालर की क्लाउड-कंप्यूटिंग डील की, जिसे 'प्रोजेक्ट निंबस' के नाम से जाना जाता है। छात्रों के वाकआउट किए जाने के दौरान पिचाई काफी सहज रहे और अपनी बात जारी रखी। उन्होंने चेन्नई से कैलिफोर्निया तक के अपने सफर और अनुभवों को साझा किया। पिचाई ने कहा, आज की खबरें देखकर यह सोचना आसान है कि हम बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। मेरे लिए यह याद रखना मददगार है कि हर पीढ़ी ने अपने-अपने तरीके से मुश्किलों का सामना किया है। पढ़ाई पूरी करके हम जिस दुनिया में कदम रखते हैं, उसे हम चुन नहीं सकते, लेकिन अपनी परिस्थितियों को किस नजरिए से देखते हैं, यह हम जरूर चुन सकते हैं।

जापानी शाही परिवार उत्तराधिकार सुरक्षित करने के लिए दूर के पुरुष रिश्तेदारों को लेगा गोद

न्यूयार्क टाइम्स से

- वर्तमान में सिर्फ पुरुष ही जापान के शाही सिंहासन पर बैठ सकते हैं
- उत्तराधिकार की कतार में सिर्फ तीन, प्रिंस हिसाहितो एकमात्र युवा

टोक्यो : दुनिया के सबसे पुराने शाही परिवारों में से एक जापान का शाही परिवार एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है, क्योंकि इसके योग्य सदस्यों और संभावित उत्तराधिकारियों की संख्या कम होती जा रही है। इसे देखते हुए अब, देश ने शाही परिवार के घटते सदस्यों की संख्या को फिर से बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया है।

संसद ने एक प्रस्ताव आगे बढ़ाया है, जिसके तहत शाही परिवार दूर के पुरुष रिश्तेदारों को गोद ले सकेगा। इस योजना से जापान के कुछ अधिकारी और एक्टिविस्ट नाराज हैं। उनका कहना है कि इसका एक आसान समाधान है कि महिलाओं को सम्राट बनने की इजाजत देना। पोल के मुताबिक, आम जनता का एक बड़ा हिस्सा इस विचार का समर्थन करता है।

अभी शाही परिवार में 16 सदस्य हैं, जिनमें पांच पुरुष और 11 महिलाएं शामिल हैं। सदस्यों की इतनी कम संख्या के कारण, विदेश यात्राओं और शाही समारोहों जैसे सार्वजनिक कर्तव्यों को पूरा करना मुश्किल हो गया है। इन कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए पर्याप्त शाही सदस्य उपलब्ध नहीं हैं। अभी सिर्फ पुरुष ही 'क्रिसेंथेमम थ्रोन' (जापान के शाही सिंहासन) पर बैठ सकते हैं। जापान के मौजूदा सम्राट नारुहितो की सिर्फ एक बेटी राजकुमारी आइको हैं। साथ ही उत्तराधिकार की कतार में सिर्फ तीन लोग हैं। प्रिंस हिताची (नारुहितो के 90 साल के चाचा), क्राउन प्रिंस अकिशिनो (सम्राट के 60 साल के भाई) और प्रिंस हिसाहितो (सम्राट के 19 साल के भतीजे)। चूंकि प्रिंस हिसाहितो परिवार में बचे एकमात्र युवा पुरुष हैं, इसलिए राजशाही का भविष्य उन्हीं पर टिका है। शाही परिवार की महिलाओं को न सिर्फ राजा बनने का अधिकार नहीं है, बल्कि किसी आम नागरिक से शादी करने पर उनका शाही दर्जा भी छिन जाता है। यही नियम राजकुमारी आइको पर भी लागू होता है।

विचाराधीन नए कानून के तहत शाही परिवार पुरुष उत्तराधिकारियों को गोद ले सकेगा। साथ ही, परिवार की महिला सदस्य शाही दायरे में बनी रह सकेंगी और परिवार से बाहर शादी करने के बाद भी अपने शाही खिताब अपने पास रख सकेंगी।

संपादकीय

सावध ऐका, ट्रम्प यांच्या 'हाका'!

विक्रम-वेताळ गोष्टीतल्या हट्टासारखा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प त्यांचा लहरी स्वभाव सोडायला तयार नाहीत. मात्र, यावेळचा त्यांचा विक्षिप्तपणा जगाला तात्पुरता का होईना दिलासा देणारा आहे. नेहमीप्रमाणे उत्सवी भाषेत त्यांनी अमेरिका व इराण शांतता कराराची घोषणा केली आहे. या घोषणेसाठी त्यांनी स्वत:च्या ८०व्या वाढदिवसाचा मुहूर्त शोधला. प्रत्यक्षात हा पूर्ण व कायमस्वरूपी शांतता करार नाही, तर गेल्या २८ फेब्रुवारीपासून सुरू असलेले युद्ध थांबविण्याचे सामंजस्य आहे. येत्या शुक्रवारी, १९ जूनला युद्धाच्या ११९व्या दिवशी स्वीत्झर्लंडमधील जिनिव्हा येथे करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर होर्मुझ सामुद्रधुनी व्यापारासाठी जगाला खुली होईल. अमेरिकन नौदलाची नाकेबंदी संपुष्टात येईल. पुढच्या साठ दिवसांत इराणच्या आण्विक कार्यक्रमासह विविध मुद्द्यांवर सहमतीचे प्रयत्न होतील. ही शांतता कराराची घोषणा नेमकी साप्ताहिक सुट्टीनंतर अमेरिकेसह जगभरातील शेअर बाजार उघडण्याच्या पूर्वसंध्येला झाली असल्याने आणि अशा घोषणा डोनाल्ड ट्रम्प सतत करीत असल्याने त्यावर कोणीही डोळे झाकून विश्वास ठेवलेला नाही. खुद्द इराणलाही या करारातून फार अपेक्षा नसली तरी विध्वंसक युद्धातून सावरायला, विस्कळीत संसाधनांची जुळवाजुळव करायला वेळ मिळेल. होर्मुझ खुली झाल्यानंतर व्यापार वाढेल, अर्थव्यवस्था सुधारेल, ही आशा आणि सोबतच, आपण बलाढ्य अमेरिकला झुकवले, इस्रायलला अमेरिकेपासून एकटे पाडले हे दाखविण्याची संधी, अशी इराणकडून कराराच्या स्वागताला दुहेरी कारणे आहेत. त्यातूनच हा इराणचा मोठा विजय असल्याचे चित्र उभे केले जात आहे. उर्वरित जगासाठी तेलपुरवठा, अर्थव्यवस्था याबाबत हा करार चांगला असला तरी, तो दीर्घकालीन शांततेची खात्री देत नाही. त्यासाठी बहुपक्षीय व मजबूत करार हवा असतो. पाकिस्तान किंवा कतार या मध्यस्थ देशांना जगात तशी फार किंमत नाही. म्हणूनच, 'भागते भूत की लंगोट सही' म्हणत अमेरिका, इस्रायल व इराण वगळता उर्वरित जग व्यावहारिक पातळीवर याचा फायदा घेण्याचा विचार करीत असेल. याचे उदाहरण म्हणजे शेअर बाजाराने आनंद व्यक्त केला आहे. अशा घोषणेची शक्यता आणि प्रत्यक्ष घोषणा अशा तीन-चार दिवसांत शेअर बाजाराने उसळी मारली आहे. कच्च्या तेलाचे घाऊक दर घसरले आहेत. इंधनटंचाईमध्ये होरपळणाऱ्या भारतासारख्या देशांना हा मोठा दिलासा आहे. टंचाई, महागाई व एकूणच अर्थव्यवस्थेवरील संकटातून सुटका होण्याची शक्यता आहे. आता मधल्या काळात वाढवलेल्या पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस व सीएनजीच्या किमती पूर्वपदावर आणून, झालेच तर त्यापेक्षा कमी करून भारत सरकारने या बदलत्या परिस्थितीचा लाभ ग्राहकांना द्यायला हवा. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर वाढले की कथित तोट्याच्या नावाखाली दरवाढ होते. तथापि, दर कमी झाल्यानंतर त्याचा लाभ ग्राहकांना मिळत नाही, असा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. आताही तसेच होणार का, हा ग्राहकांचा प्रश्न आहे. असो. ट्रम्प लहरी आहेत आणि त्यांच्यावर विश्वास ठेवावा, असे त्यांचे रेकॉर्डही नाही. करार करणे किंवा मोडणे हा त्यांच्यासाठी रोजचा खेळ आहे. इराणसोबतचा २०१५ मधील बहुपक्षीय आण्विक करार 'हॉरिबल डील' म्हणत त्यांनी २०१८ मध्ये एकतर्फी रद्द केला होता. इराणवर नव्याने निर्बंध लादले होते. आताच्या करारातही इराणी अण्वस्त्राचा तिढा पूर्णपणे सुटलेला नाही. आधी दबाव, हल्ल्याच्या धमक्या व अचानक डील ही डोनाल्ड ट्रम्प यांची असे निर्णय घेण्याची शैली आहे आणि खुद्द इस्रायलने कराराला विरोध दर्शविला तेव्हा त्यांनी शिवराळ भाषेत बेंजामिन नेतान्याहू यांना दटावायला मागेपुढे पाहिले नाही. आताचा करार पूर्णपणे ट्रम्प प्रशासनकेंद्रित आहे. सिनेटला विश्वासात घेऊन निर्णय झालेला नाही. अध्यक्षांच्या कार्यकारी अधिकारातील असा करार पुन्हा मूड बदलला तर ते सहज रद्दही करू शकतात. ते असे करत आलेच आहेत. आताचे निर्णय ते मध्यावधी निवडणूक नजरेसमोर ठेवून घेत आहेत. हे सारे पाहता या करारानंतर पश्चिम आशियातील अस्थिरता व अस्वस्थता संपुष्टात येईल, याची खात्री नाही. म्हणूनच भारत, चीन किंवा युरोपातील देशांनी सावध राहण्याची गरज आहे. ...आणि महत्त्वाचे म्हणजे दाखवायला सावध राहून चालणार नाही, तर भविष्यात जगाच्या कानाकोपऱ्यात युद्धाचे प्रसंग येतील तेव्हा त्यात आपली अर्थव्यवस्था कोलमडणार नाही, याची बेगमी करण्याची आवश्यकता आहे. विशेषत: भारतासारख्या आयातनिर्भर देशाने भविष्यासाठी अशी तजवीज करायलाच हवी.

दक्षिणेतील 'चौकडी' भाजपसाठी डोकेदुखी !

व्ही. डी. सतीशन, ए. रेवंथ रेड्डी, डी. के. शिवकुमार आणि जोसेफ विजय.. दक्षिणेकडचे हे चार मुख्यमंत्री एकत्र आले तर वेगळे चित्र दिसू शकते.

प्रभू चावला
ज्येष्ठ पत्रकार

केरळचे व्ही. डी. सतीशन, तेलंगणाचे ए. रेवंथ रेड्डी, कर्नाटकचे डी. के. शिवकुमार आणि तामिळनाडूचे जोसेफ विजय नीति आयोगाच्या बैठकीत एकत्र प्रविष्ट झाले. एरव्ही ती नेहमीची बैठक होती; परंतु यावेळी मात्र भारतीय संघराज्याचे व्याकरण या चौघांनी बदलून टाकले.

राष्ट्रपती भवनाच्या भव्य संकुलात गेल्या आठवड्यात देशापुढील मुद्द्यांवर केंद्र-राज्य संबंधातील मेळ सांभाळत विचार करण्यासाठी नीति आयोगाची बैठक भरली होती. त्यावेळी हे चारही मुख्यमंत्री याचकाच्या भूमिकेतून नव्हे, तर एक समन्वयित शक्ती म्हणून प्रविष्ट झाले. एरव्ही ही नैमित्तिक बैठक होती; परंतु यावेळी मात्र या चौघांनी भारतीय संघराज्याच्या व्याकरणाचा नूरच पालटवला. त्यांनी एकत्रित टाकलेले वजन सहजपणे दुर्लक्षिता येणार नाही असे होते. या चार राज्यांत लोकसभेच्या १०४ म्हणजे एकपंचमांश जागा येतात. चारही मिळून देशाच्या जीडीपीत ते २६ टक्के वाटा उचलतात. प्रत्यक्ष कर महसुलात ३० टक्के भर घालतात. त्यांच्यातले एकही सरकार केंद्रातील सत्तारूढ पक्षाच्या गटातले नाही. त्यांनी दिल्लीपुढे गाऱ्हाणी आणली नव्हती, तर राज्याच्या गरजांचा नीट अभ्यास करून ठामपणे मांडण्यासाठी ते आले होते.

भारतातील विरोधकांचे राजकारण म्हणजे केवळ सत्तेसाठी आरडाओरडा असे चित्र बरीच वर्षे दिसते आहे. प्रादेशिक नेते सदैव गोंधळलेले, निषेध हे साधन न समजता साध्य समजणारे असे राहिले. पहिल्याच बैठकीत या चौघांनी हा शिरस्ता मोडला. चार स्वतंत्र अर्जदार म्हणून सामोरे न येता वैचारिकदृष्ट्या विरोध करणाऱ्यांचा गट म्हणून ते आले. देशाला त्यांनी दक्षिणेच्या ऐक्याची चुणूक दाखवली.

दक्षिणेकडच्या या राज्यांनी प्रत्येकच तांत्रिक निकषावर संघराज्याचे घटक म्हणून आदर्श कामगिरी करून दाखवली आहे. राष्ट्रीय विकासाच्या आड येणारी लोकसंख्या वाढ त्यांनी रोखली, शिक्षणाच्या प्रसारातून मानवी भांडवलाची वृद्धी केली. त्याचप्रमाणे निर्यात अभिमुख अर्थव्यवस्था विकसित करून देशाच्या प्रगतीला हातभार लावला. मोबदल्यात त्यांना काय मिळणार आहे? तर पुढच्या जनगणनेनंतर त्यांचे संसदेतील प्रतिनिधित्व कमी होईल. त्यामुळे चांगला कारभार केल्याची ही शिक्षा झाली असे त्यांना वाटते. लोकसंख्या वाढ ज्यांनी होऊ दिली त्यांना बक्षिसी मिळाली. दक्षिणी राज्यांसाठी हा घटनात्मक विरोधाभास असून, संघराज्यातील समतेला त्यामुळे बाधा पोहोचते.

५६ वर्षीय रेवंथ रेड्डी यांनी नेमक्या शब्दात हा विषय मांडून एक मिश्रसूत्र समोर ठेवले. अर्ध्या जागा लोकसंख्येनुसार आणि अर्ध्या जागा आर्थिक योगदानानुसार द्याव्यात असे त्यांनी सुचवले.

व्ही. डी. सतीशन | ए. रेवंथ रेड्डी | डी. के. शिवकुमार | जोसेफ विजय

अर्थसंकल्पीय गणित आणि लोकसभेतील प्रतिनिधित्व यात या सूत्राने ताळमेळ बसू शकतो. अशा प्रकारे राज्यांना वाटणाऱ्या चिंतेचे रूपांतर त्यांनी घटनात्मक प्रश्नात केले. कोणत्याही गंभीर स्वरूपाच्या संघराज्यात्मक लोकशाहीत असे प्रश्न येतच असतात. मतदारसंघ पुनर्रचनेसंबंधीच्या युक्तीवादाचे रेड्डी यामुळे मुख्य प्रवक्ते झाले.

या चारही नेत्यांची क्षमता वेगवेगळी आहे. ६२ वर्षीय सतीशन हे त्यांच्यातले बुद्धिमान आणि नैतिक आधार ठरतील असे नेते असून, व्यवसायाने वकील आहेत. सहा वेळा आमदारकी उपभोगत त्यांनी केरळमध्ये शांतपणे आपल्या कामातून काँग्रेस पक्षाची उभारणी केली. स्वच्छ कारभार देण्याची ताकद त्यांच्यात आहे. ६४ वर्षीय शिवकुमार हे असाधारण असे संघटनाकुशल नेते आहेत. आठ वेळा आमदार राहिलेले शिवकुमार आघाडीची गणितं सांभाळतात. कर्नाटकात नष्टप्राय होत चाललेल्या काँग्रेसला त्यांनी स्थिर सरकार देण्याइतपत सावरून घेतले. सत्तेच्या मार्गातले खाचखळगे त्यांना ज्ञात आहेत. ५१ वर्षांचे जोसेफ विजय कुठलाही घराणेशाहीचा पाठिंबा नसताना राजकारणात आले. पक्षकारणाचा त्यांना काही अनुभव नाही. तामिळनाडूत सहसा ज्याला महत्त्व असते त्या धोरणात्मक बाबींचाही त्यांना म्हणावा तसा परिचय नाही. सिनेमाविश्वातील लोकप्रियतेचे रूपांतर त्यांनी राजकीय यशात केले. आता ते दक्षिणेतील मोठी अर्थव्यवस्था आणि लोकसभेला ३९ जागा देणाऱ्या राज्याचे प्रमुख आहेत.

हे चारही नेते एकमेकांपेक्षा वेगळे असले तरी एकत्रितपणे ते एक ताकद म्हणून उभे राहू शकतात. विरोधी पक्षांच्या राजकारणात आजवर जे जमले नाही ते घडवू शकतात. केवळ तोंडाचे बळ दाखविण्यापेक्षाही निवडणुकीवर प्रभाव टाकणाऱ्या गोष्टी तसेच संसदेतील प्रतिनिधित्व याबाबतीत दक्षिणेचा एकसंघ गट म्हणून ते वजन टाकतील. दक्षिणी राज्यांत भाजपचा संघटनात्मक प्रभाव क्षीण आहे. तेलंगणा, तामिळनाडू आणि केरळात त्यांना निवडणुकीत यश मिळवता आलेले नाही. कर्नाटकातच काय ती थोडी ताकद दाखवता आली. या विसंगतीचा फायदा चौघांना हिंदी पट्ट्याशी मुकाबला करताना होऊ शकतो.

या गटाचे आर्थिक वजन, खासदारांची संख्या वस्तुनिष्ठ प्रभाव टाकू शकते. मतदारसंघ पुनर्रचनेचा प्रश्न त्यांना एकत्र आणू शकतो. चारही नेत्यांचे वय त्यांच्या बाजूने आहे. पुढच्या दशकभरात ते आपल्या उद्दिष्टापर्यंत पोहोचल्यास निवडणुकांवर त्याचा प्रभाव पडेल. आजवर प्रादेशिक असंतोष शमविण्यासाठी सवलतींचे तुकडे फेकून भागत असे. यापुढे असे करता येणार नाही हे या चौघांनी पहिल्याच पावलात जाणवून दिले. सुरुवात दमदार झाल्याने हे चौघे पुढे काय करतात, याकडे निश्चितच लक्ष राहील. भाजपसाठी ही डोकेदुखी ठरू शकते.

अन्वयार्थ

वाळूच्या राक्षसी भुकेमुळे पोखरली जाताहेत राज्यातील शहरे

पराकोटीचा वाढलेला वाळूचा हव्यास केवळ नद्याच नव्हे, प्रत्येक शहर उद्ध्वस्त करीत आहे. पर्यावरण आणि लोकशाहीलाही ते आव्हान ठरत आहे.

नारायण जाधव
उप वृत्तसंपादक,
लोकमत, मुंबई

पाण्यानंतर सर्वाधिक वापरले जाणारे नैसर्गिक संसाधन म्हणजे वाळू. ती निर्माण होण्यासाठी शेकडो वर्षे लागतात; पण नद्यांचे पोट फाडून आपण काही तासांत ती उपसून नेत आहोत. त्यामुळेच नद्या आज जीवनवाहिन्या राहिलेल्या नसून काँक्रीटच्या साम्राज्यासाठी लुटल्या जाणाऱ्या खाणी बनल्या आहेत. महामुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, दिल्ली, हैदराबाद, बंगळुरू, अहमदाबाद... देशातील प्रत्येक वाढते शहर नदीच्या छातीला नख लावून उभे राहत आहे. मेट्रो, महामार्ग, किनारी रस्ते, डेटा सेंटर, गगनचुंबी इमारती, बंदरे, औद्योगिक कॉरिडॉर आणि गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या राक्षसी भुकेसाठी लाखो ब्रास वाळू उपसली जात आहे. त्यामुळे थोड्याशा पावसानेही अनेक ठिकाणी पूर येत आहेत आणि नद्या मरणासन्न होत आहेत.

खान्देशातील गिरणा आणि तापी नदी खोऱ्यातील वाळू कमी झाल्याने पाण्याचा नैसर्गिक संचय घटला. गिरणेस अगदी नंदगावपर्यंत पोखरल्याचे 'लोकमत'ने सचित्र उघड केले आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील केळी, ऊस आणि भाजीपाला शेतीवर त्याचे गंभीर परिणाम दिसू लागले आहेत. मराठवाड्यातील गोदावरी, पूर्णा, मांजरा आणि दुधना नदी परिसरातही वाळू उपशाने गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. आधीच दुष्काळी पट्टा असलेल्या मराठवाड्यात नदीपात्रातील वाळू कमी झाल्याने भूजल पुनर्भरणाचा वेग घटला. परिणामी, विहिरी आणि बोअरवेल अधिक खोल जाऊ लागल्या. अनेक गावांमध्ये टँकरवर अवलंबून राहण्याची वेळ आली.

छत्रपती संभाजीनगर, बीड, परभणी, जालना परिसरात नदीकाठच्या शेतीला पाण्याअभावी फटका बसत आहे. नाशिक परिसरात मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या वाळू उपशामुळे नदीपात्र खोल गेले आहे. विदर्भातील वैनगंगा, वर्धा, पैनगंगा आणि प्राणहिता नदी खोऱ्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर वाळू उत्खनन सुरू आहे. नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा आणि यवतमाळ भागांत नदीकाठची धूप वाढल्याच्या तक्रारी सातत्याने होत आहेत. खोल उत्खननामुळे मासेमारीवर परिणाम झाला असून, अनेक ठिकाणी नदीच्या प्रवाहात कृत्रिम बदल झाले आहेत. पावसाळ्यात अचानक पूर येणे आणि उन्हाळ्यात नदी कोरडी पडणे, ही परिस्थिती अधिक गंभीर होत चालली आहे.

कोल्हापूर आणि सांगलीतील पंचगंगाकाठची धूप वाढल्याने अनेक शेतकऱ्यांची जमीन नदीने गिळली. पात्रात निर्माण झालेल्या खोल खड्ड्यांमुळे प्रवाह असंतुलित झाला. मासेमारी कमी झाली, जलचरांचे अधिवास नष्ट झाले आणि नदीतील सूक्ष्म जीवसाखळी ढासळली आहे.

कोकणातील सावित्री आणि वशिष्ठी नद्यांची अवस्था तर विकासाच्या क्रौर्याचे प्रतीक बनली आहे. महाडजवळील सावित्री नदीवरील ब्रिटिशकालीन पूल कोसळल्यानंतर स्थानिकांनी अवैध वाळू उपशाकडे बोट दाखवले. सततच्या उत्खननामुळे पुलाचा पाया कमकुवत झाल्याचा आरोप झाला. तो केवळ पुलाचा अपघात नव्हता, तर नदीच्या छातीत वार केल्याचा परिणाम होता.

महामुंबईतील उल्हास नदी, ठाणे खाडी आणि वसई खाडी परिसरातही वाळू उपशामुळे खाडी परिसंस्था कोसळू लागली आहे. फ्लेमिंगो, मासे, खेकडे आणि स्थलांतरित पक्ष्यांचे अधिवास धोक्यात आले आहेत. खाऱ्या पाण्याची घुसखोरी वाढत असल्याने भातशेती संकटात सापडली आहे. आधीच खाडीपुलांच्या कामांमुळे मच्छीमार संकटात सापडलेला आहे.

भारतातील वाळू व्यवसायाचे मूल्य लाखो कोटींच्या उंबरठ्यावर पोहोचल्याचा अंदाज आहे. महाराष्ट्रातही हजारो कोटींची वाळू अर्थव्यवस्था उभी राहिली आहे. अधिकृत लिलावापेक्षा अवैध उत्खनन अधिक वेगाने सुरू आहे. रात्रीच्या अंधारात नदीपात्रात उतरलेली पोकलेन यंत्रे, बनावट परवान्यांवर धावणारे ट्रक, राजकीय संरक्षण, महसूल यंत्रणांतील संगनमत आणि पत्रकार, तसेच अधिकाऱ्यांवरील हल्ले पाहता वाळूमाफिया आता पर्यावरणापेक्षा लोकशाहीलाच अधिक आव्हान देत आहेत.

विकास हवाच; पण विकासाच्या नावाखाली निसर्गाची हत्या करणे परवडणारे नाही. पर्यायी बांधकाम साहित्य, कृत्रिम वाळू, पुनर्वापरित बांधकाम अवशेष, फ्लाय ॲश आणि वैज्ञानिक 'सॅण्ड बजेट' ही आता काळाची गरज आहे. नदी ही केवळ पाण्याची वाहिनी नाही; ती संस्कृतीची रक्तवाहिनी आहे. वाळूचा प्रश्न केवळ पर्यावरणाचा नाही; पुढील पिढ्यांचे अस्तित्वच त्यावर अवलंबून आहे.

narayan.jadhav@lokmat.com

जगभर

५६ वर्षांपासून आजी राहतात सापांच्या जंगलात

शहरांतून काहीकाळासाठी निसर्गाच्या जवळ जायचं, ताजंतवानं होऊन परत शहरात येऊन आपल्या कामाला लागायचं, ही अनेकांच्या विश्रांतीची व्याख्या असते. पण, काही माणसं मात्र कायमस्वरूपीच शहरी आयुष्यापासून दूर जाऊन निसर्गाच्या सहवासात जगायचं ठरवतात आणि संपूर्ण जगाचं लक्ष वेधून घेतात. कॅरोल रकडेशल या अशाच एक अमेरिकन नागरिक. जॉर्जिया राज्याला लागून असलेल्या अटलांटिक महासागराच्या किनाऱ्यापासून दूर एक बेट आहे. या बेटाचं नाव कंबरलँड ! १९६० मध्ये तरुण वयात कॅरोल जीवशास्त्राचा अभ्यास करण्यासाठी कॅरोल पहिल्यांदा तिथे गेल्या आणि मग जातच राहिल्या. कधी संशोधनासाठी तर कधी पर्यटक म्हणून. १९७० मध्ये त्यांनी कायमचं तिथेच राहण्याचा निर्णय घेतला. आज त्या ८४ वर्षांच्या आहेत, मात्र आजही शहरी, धकाधकीपेक्षा कंबरलँड बेटावर निसर्गाच्या सान्निध्यातलं आयुष्यच त्यांना अधिक आपलंसं वाटतं.

कंबरलँड हे बेट अटलांटिक महासागरात जमीन आणि पाणी यांच्या मधल्याच अवस्थेत असलेल्या एका प्रदेशात वसलेलं आहे. भलेमोठे विषारी साप आणि जंगली श्वापदांसाठी हे बेट ओळखलं जातं. पण हे बेटच आता कॅरोल आजींचं घर झालं आहे. तिथे जायचं तर फेरीबोट हा एकमेव वाहतुकीचा पर्याय आजही उपलब्ध आहे. कॅरोल आजी या बेटाच्या उत्तरेकडील भागात राहतात. तिथे सोयीसुविधा फारशा नाहीत. त्यामुळे पर्यटकांची वर्दळही जवळपास नाहीच. बेटावर असलेलं पाणी, जंगल, वाळू आणि दलदलीचे प्रदेश हा त्यांच्या अभ्यासाचा विषय आहे.

१९७० च्या सुरुवातीला त्यांनी या बेटावर पूर्णवेळ

वास्तव्य सुरू केलं. पिण्याचं पाणीही त्यावेळी सहज उपलब्ध होत नसे. ते आणून साठवावं लागत असे आणि अगदी जपून वापरावं लागत असे. तिथल्या वास्तव्यात उष्ण हवामान, डोक्यावरचा निवारा, दोन वेळचं अन्न या सगळ्यासाठीच त्यांना खूप श्रमही करावे लागत असत. त्यांनी तिथे राहायला सुरुवात केल्यावर जमेल तसं हळूहळू स्वत:च आपलं घर बांधलं. आज इतक्या वर्षांनीही हे चित्र फार बदललेलं नाही. घरातली दुरुस्तीची कामं अजूनही कॅरोल आजी स्वतःच करतात. आज या वयातही त्या पायी जंगल पालथं घालतात, निसर्गात होणारे बदल टिपतात आणि त्याच्या नोंदीही ठेवतात. या बेटाचा चेहरामोहरा सतत बदलत असतो. मोठी वादळं येऊन गेली की वाळूच्या रेषा बदलतात. झाडं दिशा बदलतात. दलदलीचे प्रदेशही सतत विस्तारत राहतात.

शेजारीपाजारी माणसं दिसावी एवढ्या सर्रास या बेटावर रानटी घोडे आणि साप यांचा वावर असतो. समुद्री कासवं अंडी घालण्यासाठी किनाऱ्यांवर येतात. स्थलांतरित पक्ष्यांचे थवे सतत ये-जा करतात. डॉल्फिन तर जणू कॅरोल यांचे शेजारीच. त्यांच्या दिवसाचा बराच वेळ समुद्र किनाऱ्याचं निरिक्षण करण्यात जातो. वाहून आलेली लाकडं, पाण्याच्या दाबाने तुटणारे शंख-शिंपले, मृत प्राण्यांचे अवशेष ही सगळी वैज्ञानिक माहिती त्या नोंदवतात. दूर निर्जन बेटावर राहतात म्हणून मुख्यभूमीशी त्यांनी संपर्क तोडलेला नाही. गरजेप्रमाणे त्या तिथेही ये-जा करतात, पण कंबरलँड हेच आता त्यांचं घर झालं आहे..

जनमन

फोन जुनाच, पण विचार मात्र नवा !

आज सुपरमार्केटमध्ये खरेदी करत असताना एका वयोवृद्ध महिलेने मला तिचा छोटासा की-पॅड फोन आणि एका कागदावर लिहिलेला फोन नंबर दिला. तो नंबर फोनमध्ये सेव्ह करून द्यावा, अशी तिची विनंती होती. काम अगदी साधे होते, पण त्या क्षणाने मला विचार करायला भाग पाडले. तो फोन फक्त मूलभूत कामांसाठी होता. फोन कॉल करणे आणि संदेश पाठवणे. सोशल मीडियाच्या सूचना नव्हत्या, अखंड स्क्रोलिंग नव्हते, सतत लक्ष वेधून घेणारी अपडेट्स नव्हती. त्या छोट्याशा फोनने मला अशा काळाची आठवण करून दिली, जेव्हा तंत्रज्ञानाचे उद्दिष्ट मर्यादित होते आणि ते आपल्या आयुष्याचे केंद्रबिंदू नव्हते.

आज स्मार्टफोनमुळे आपण काम करतो, शिकतो, मार्ग शोधतो, संवाद साधतो, खरेदी करतो, बँकिंग करतो आणि मनोरंजनही करतो. त्यांनी निःसंशय जीवन अधिक सोयीचे केले आहे. पण, त्याचबरोबर त्यांनी अशी एक अवलंबित्वाची सवय निर्माण केली आहे, जी काही दशकांपूर्वी कल्पनाही करता आली नसती.

कधी कधी असे वाटते की, आपण आपल्या आजूबाजूच्या जगापेक्षा आपल्या उपकरणांशीच अधिक जोडले गेलो आहोत. स्मार्टफोनशिवाय एक दिवस काढणे कठीण वाटते. त्या छोट्याशा कीपॅड फोनने एका साध्या काळाची आठवण करून दिली. अशा काळाची, ज्यात सुविधा कमी होत्या, पण विचलित करणाऱ्या गोष्टीही कमी होत्या. प्रगती महत्त्वाची आहेच. पण, असे क्षण मनात एक प्रश्न निर्माण करतात की, आपण सोयी मिळवल्या, पण त्या बदल्यात साधेपणा हरवून बसलो आहोत का?

- रसिका उगले, अकोला

समकालीन महत्त्वाचे मुद्दे मांडणारी, नवी चर्चा सुरू करणारी वाचक-पत्रे या स्तंभामध्ये प्रसिद्ध केली जातील. आपली पत्रे येथे पाठवा : **janman@lokmat.com**

गावशिवारातली टिपणं

यश्टीश्टँडवरचं रम्य संथपण आता खलास झालेलं आहे...

काळ पुढे सरकला आणि यश्टीश्टँडचं रूप बदलत गेलं. एसटीची वाट बघणारे लोक अजूनही तसेच आहेत, पण तिथलं निवांतपण, गप्पा संपल्या...

बालाजी सुतार
कवी-कथाकार

गावापासून अर्ध्या मैलावरून एक सडक गावाला वळसा घालून पलीकडे जाते. येणाऱ्या जाणाऱ्या गाड्या तिथे वळणावर थांबत. लोक त्या जागेला एसटीस्टँड म्हणजे 'यश्टीश्टँड' असं म्हणत. गावाशेजारच्या दोनपाच वाड्यांकडून गावाकडे येणाऱ्या वाटांवरून आलेले काही, गावातले काही, असे वेळेनुसार पाचदहा प्रवासी तिथे पायदळ चालत येत. सहसा प्रवास म्हणजे दोन दिशांना अर्ध्या तासाच्या अंतरावर असलेली दोन तालुक्याची गावं. हरगोष्टीसाठी तिथे जावं लागायचं.

तालुक्याच्या गावात मोठ्ठा सरकारी दवाखाना, शेतमालाची आडत, वाणसामानाची, कापडाची आणि आणखी कशाकशाची दुकानं, गावाच्या तुलनेत काही चकचकीत हॉटेलं, सिनेमाची 'टाकी' आणि गावाकडून पोरं शिकायला जात असलेली शाळा-कॉलेजं असत. कुणाची ना कुणाची काही ना काही कामं रोजच निघत. मग माणसं घरून निघत आणि तडातडा चालत यश्टीश्टँडवर दाखल होत. गाड्यांच्या वेळा वगळता सहसा निर्मनुष्य असणारं ते श्टँड. तरीही तिथे एक कुडाचं हॉटेल होतं. समोर दोनपाच बाकडी असत. बाजूला एक मोठं नांदुरकीचं झाड. प्रवासेच्छुक पुरुषमाणसं बाकड्यांवर आणि झाडाच्या सावलीत ठिय्या मांडून बसलेल्या बाया. कुणी आडत्याकडे जायला निघालेला कुणबी, कुणी पंचायत समिती किंवा तहसील कचेरीतून कसलासा 'कागद' काढून घेण्यासाठी निघालेले गरजू, लेकासोबत दवाखान्यात जायला निघालेली एखादी म्हातारी. आणि सकाळी संध्याकाळी शाळकरी किंवा कॉलेजात जाणारी 'पास'धारक पोरे-पोरी. कुणाजवळ मोठ्ठंच्या मोठं गाठोडं, कुणाजवळ खताच्या पोत्याची मजबूत शिवलेली पिशवी किंवा कुणाच्या हातात वह्या-पुस्तकांचं बाड. तंबाखूची चिमूट मळत किंवा बिडीचा धूर काढत आणि गप्पा हाकत एसटीची वाट बघणारी

धोतर-पटका-टोपीतली खेडवळ माणसं.

मोबाइल वगैरे लफडी नव्हती, त्यामुळे बसल्या जागी मुंड्या वाकवून मुडद्यासारखं निश्चल न बसता वेळ घालवण्यासाठी माणसे एकमेकांशी बोलत. पावसाचा अंदाज, पीकपाण्याच्या चौकश्या, तूर-कापसाचे भाव, गावातल्या कटकटी, भाऊबंदकीतल्या हाणामाऱ्या, गावपुढाऱ्यांच्या भानगडी, असल्या कैक गोष्टी. बस उशिरा आली तरी कुणाला फारशी घाई नसे. 'यश्टी' म्हणजे उशिराच येणार, हे समीकरण मनात पक्कं असे. आणि घड्याळी वेळा फारशा खिजगणतीत नसत कुणाच्या.

मधूनमधून जाणारे-येणारे कुणी श्टँडवरच्या त्या एकमेव हॉटेलातला तांबडाभडक चहा पीत. कोळशाच्या शेगडीवर किंवा स्टोव्हवर चहा उकळत उभा असलेला धुरकट मालक, धुराने काळवंडलेली भिंत आणि तीवर देवादिकांची किंवा नटनट्यांची चित्रं डकवलेली, एखाददुसऱ्या काचेच्या बरणीमध्ये विकायला ठेवलेली प्राचीन गोळ्या-बिस्किटं- असं, एवढंच ते 'नेपथ्य' असायचं.

काळ पुढे सरकला आणि यश्टीश्टँडचं रूप क्रमश: बदलत गेलं. मधल्या काळात यश्टीश्टँडच्या जागी वीतभर लांबीरुंदीची काँक्रीटची शेड उभी राहिली. लोक त्याला 'कॅन्टीन' म्हणत. तिथे रिकामटेकडी तरणी पोरे दुपारभर सावलीत बसून राहायला लागली. त्यामुळे प्रवासी पुन्हा मूळच्याच जागी झाडाखाली उभे राहत. पुढेपुढे गाव वाढायला लागलं आणि हळूहळू रस्त्याच्या दुतर्फा अतिक्रमणं झाली. अवैध वाहतुकीच्या जीपगाड्या, टमटमी वाढल्या. गावात खासगी दुचाकी, चारचाकी वाहनांची संख्या वाढली. एसटीची वाट बघत बसणारे लोक संपले नाहीत, पण तिथलं निवांतपण, तिथल्या गप्पा संपल्या. लोक आता मोबाइलमध्ये गुंगलेले दिसतात.

दुकाना-माणसांच्या त्या गर्दीकडे पाहताना यश्टीश्टँडवर आता फक्त कोलाहल दिसतो. तिथलं रम्य संथपण खलास झालेलं आहे.

majhegaane@gmail.com

तिरकस आणि चौकस — गजानन घोंगडे

हे पत्र लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेडच्या वतीने मुद्रक व प्रकाशक **बालाजी मुळे** यांनी प्लॉट नं. ए - ८१८ इंडस्ट्रियल एरिया, एम.आय.डी.सी., महापे, नवी मुंबई येथे मुद्रित करून 'लोकमत', पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई कार्यालय - ४००७०५ येथून प्रसिद्ध केले. ● दूरध्वनी क्र : ०२२ ४६०४१७८४
● **मुंबई कार्यालय :** लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेड, तिसरा मजला, पारिजात हाउस, प्लॉट नं. १०७६, आपटे इंडस्ट्रियल इस्टेट, लक्ष्मीनरसिंग पपन मार्ग, डॉ. ई मोझेस रोडसमोर, गांधीनगर, वरळी, मुंबई, ४०००१८. ● दूरध्वनी क्र : ०२२- ४६०३५९३०, ०२२- ४७५०७९४६ ● **ठाणे कार्यालय :** वेस्टर्न व्ह्यू, श्री गजानन महाराज चौक, वारकरी भवनाजवळ, ठाणे, फोन : २५४४१९०५, २५३८१७७४ ● **नवी मुंबई कार्यालय :** पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई ४००७०५. फोन : ०२२ ४६०४१७८४ ● संस्थापक संपादक : **स्व. जवाहरलाल दर्डा** ● मानद संपादिका : **श्रीमती उषाताई दर्डा** ● चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड : **डॉ. विजय दर्डा** ● एडिटर इन चिफ : **राजेंद्र दर्डा** ● समूह संपादक : **विजय बाविस्कर**
● संपादक : **अतुल कुलकर्णी*** (*पी. आर. बी. कायद्यानुसार संपादकीय जबाबदारी यांची आहे.) 'लोकमत'मधील लेखांचे हक्क राखून ठेवले आहेत. लोकमत ® हे चिन्ह लोकमत मीडिया प्रायव्हेट लि. चे. व्यापारचिन्ह आहे.

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

तृणमूल से सबक

तृणमूल कांग्रेस का टूटना बदलती भारतीय राजनीति का एक ऐसा संकेत है, जिससे तमाम राजनेता सबक ले सकते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणामों को अभी चालीस दिन ही पूरे हुए हैं और यह बात अब शीशे की तरह साफ है कि तृणमूल कांग्रेस का स्वर्णिम दौर लद गया है। एक हारी हुई पार्टी को एकजुट रखने के जैसे प्रयास तृणमूल कांग्रेस कर सकती थी, उनका नितांत अभाव दिखा है। तृणमूल कांग्रेस के आला नेताओं ने साबित कर दिया कि उनमें जुड़ने-जोड़ने का हुनर कम है। वैसे, राज्य स्तर पर विधानसभा में भी पार्टी बंट चुकी है, लेकिन उसका कोई स्पष्ट स्वरूप सामने नहीं आया है, जबकि पार्टी से अलग हुए 20 सांसदों की स्थिति स्पष्ट है। इन्होंने एक नए अल्प-चर्चित दल के नाम का सहारा लिया है। यह अलग तरह का दलबदल अपने आप में बहस का मुद्दा है। आम तौर पर राजनीतिक दल अपने चुनाव अभियान से सांसद तैयार करते हैं, पर यहां तो एक दल को एकमुश्त 20 सांसद हासिल हो गए हैं। यह कानूनन सही हुआ है या गलत, इस पर जरूरी बहस शुरू हो गई है और होनी भी चाहिए।

कुछ संकेत बहुत स्पष्ट हैं और जिनसे अनेक सवाल खड़े होते हैं। ममता बनर्जी ने खून-पसीने से बनाई अपनी पार्टी को बचाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर क्यों नहीं लगाया? अगर वह मिल-बैठकर बात करतीं, तो संभव है, उनकी पार्टी सलामत रहती। ऐसा लगता है कि वह पूरी तरह से भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी पर निर्भर हो गईं। वंशवादी दलों के साथ यही समस्या है, इनमें दलीय लोकतंत्र का विशेष महत्व नहीं बचता है। वंशवाद ऐसी कमजोरी साबित हुआ है कि ममता बनर्जी ने न केवल राज्य में, बल्कि अपनी पार्टी में भी बहुमत गंवा दिया है। यह कहने में हर्ज नहीं कि तृणमूल अंदर से मजबूत नहीं थी और केवल सत्ता के रसायन ने उसे जोड़े रखा था। सत्ता का रसायन जैसे ही खत्म हुआ, पार्टी बिखर गई। कौन भूल सकता है कि राज्य में लगभग दुश्मनी की राजनीति हुई है? इसी का नतीजा है कि सूबे के बड़े-बड़े बड़बोले नेता शर्मसार से हैं और अपने बचाव के लिए किसी मजबूत छतरी की तलाश में हैं। यह सबक बड़ा है, जिसे शायर बशीर बद्र ने कुछ ऐसे बयान किया था- *दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हों।*

सत्ता का रसायन जैसे ही खत्म हुआ, तृणमूल कांग्रेस बुरी तरह बिखर गई। यह कौन भूल सकता है कि पश्चिम बंगाल में लगभग दुश्मनी की राजनीति हुई है?

बंगाल में यह नए किस्म की राजनीतिक संस्कृति है, जिसमें टूटने का सलीका खास है। कुछ ही सप्ताह पहले आम आदमी पार्टी के सात सांसद समूह बनाकर भाजपा में शामिल हुए हैं। ऐसे में, सवाल उठता है कि तृणमूल से अलग हुए सांसद भाजपा में क्यों शामिल नहीं हुए? यहां फिर एक बार जमीनी प्रतिद्वंद्विता वाली बात सामने आती है। तृणमूल के नेताओं-कार्यकर्ताओं ने बीते 15 वर्ष में जिस तरह दुर्व्यवहार किया है, उस वजह से भाजपा के जमीनी कार्यकर्ता तत्काल मेल-मिलाप के पक्ष में नहीं हैं। यहां राजनीतिक संस्कृति का अंतर आड़े आ रहा है और इस अंतर को सकारात्मक रूप से पाटना ममता बनर्जी की नई राजनीति की प्राथमिकता होनी चाहिए। हालांकि, युवा सांसद अभिषेक बनर्जी अपनी सियासत को जिस अदावत तक उतार लाए हैं, वहां से तृणमूल की स्वस्थ प्रतिद्वंद्विता की ओर वापसी आसान नहीं होगी। अब रही बात एनडीए की, तो उसकी लोकसभा सीटों की संख्या 294 से बढ़कर 314 होने वाली है, पर वह अभी भी दो-तिहाई बहुमत से 46 सीट पीछे है। यहां फिर इसी सबक को याद करना होगा कि लोकतंत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों-दलों का यकीन जीतना ही सबसे सही रणनीति है।

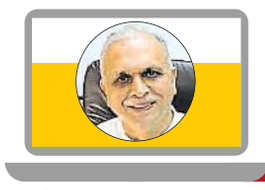

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 16 जून, 1951

काश्मीर का मूल प्रश्न

पाकिस्तान के विदेश-मंत्री श्री जफरुल्ला खां ने काश्मीर के संबंध में नेहरूजी के वक्तव्य का एक लम्बा उत्तर दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी सारी तर्क-शक्ति व्यय कर डाली है। श्री जफरुल्ला एक सफल वकील रहे हैं और वह अपने ब्रिटिश तथा अमरीकी सहायकों के हाथ सबल करने का ढंग भली-भांति जानते हैं। स्पष्टतः उनके इस वक्तव्य का उद्देश्य ब्रिटेन एवं अमरीका के लोकमत को प्रभावित करना और भारत के विरुद्ध पाकिस्तान की जनता का द्वेष-भाव कायम रखना है।

श्री जफरुल्ला ने अनेक सबल प्रतीत होनेवाले तर्क प्रस्तुत करके यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि भारत ने सुरक्षा-परिषद का 'पंच-निर्णय प्रस्ताव' अस्वीकृत करके न केवल एक असंगत कार्य, वरन् अपराध भी किया है, जिसके लिए उसे दंड मिलना चाहिए। उन्होंने काश्मीर में पुनः 'जेहाद' की धमकी भी दी है।... पाकिस्तानी नेताओं ने धर्मान्ध एवं कट्टर कबायलियों को काश्मीर में जाकर लूट-पाट तथा हत्याएं करने के लिए भड़का दिया। एक ओर उन्हें काश्मीर की सम्पदा और रूपवती स्त्रियों का लोभ दिखाया गया, दूसरी ओर पाकिस्तानी शस्त्रास्त्रों तथा सैन्यबल की सहायता का आश्वासन दिया गया। इस पर स्वभाव से ही अपराधी और रक्तपिपासु कबायली खर-दूषण की सेना की भांति काश्मीर की मनोरम एवं सुकुमार घाटी में पिल पड़े।

डोगरा महाराजा हरि सिंह की छोटी सी सेना अपने मध्य युगीन आयुध लेकर आधुनिक शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित इन कबायलियों का प्रतिरोध करने में असमर्थ रही। कबायली काश्मीरी जनता को लूटते-पाटते उनकी हत्या करते, स्त्रियों का अपहरण करते बढ़ने लगे। उस समय ऐसा प्रतीत होने लगा कि कुछ ही दिनों में सम्पूर्ण निहत्था काश्मीर इन आततायियों के पैरों तले कुचल जायेगा।

इस पर काश्मीर के महाराजा और जनता ने भारत से सहायता की याचना की। उन्होंने पुकार की कि हम भारत-संघ में रहना चाहते हैं, हमारी रक्षा करो। भारत के तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर-जनरल लार्ड माउंटबेटन ने काश्मीर को 'अस्थायी रूप से' भारत-संघ में प्रविष्ट कर लिया। किन्तु हमारे न्याय और प्रजातंत्र-परायण प्रधानमंत्री ने कहा- जब तक जनता का स्पष्ट मत प्राप्त न कर लिया जाये, काश्मीर का प्रवेश स्थायी न समझा जायेगा।

पूरी दुनिया को अमन का इंतजार

यहां स्कैन करें

अरविंद गुप्ता | पूर्व राजनयिक एवं डायरेक्टर, वीआईएफ

यदि अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित समझौता साकार होता है, तो पूरी दुनिया में कायम राजनीतिक, आर्थिक व सुरक्षा संबंधी संकट जल्द खत्म हो जाएंगे।

लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार पश्चिम एशिया से वह खबर आ गई, जिसका इंतजार पूरे विश्व समुदाय को था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 15 जून की सुबह अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये बताया कि ईरान के साथ समझौते का मसौदा तैयार हो गया है और होर्मुज जलमार्ग खुलने के साथ ही अमेरिकी नाकेबंदी हटाने को मंजूरी दे दी गई है। बाद में तेहरान ने भी इसकी पुष्टि कर दी। खबरों के मुताबिक, शुक्रवार को दोनों देश 'शांति समझौते' पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।

यदि यह समझौता साकार होता है, तो पूरी दुनिया में कायम राजनीतिक, आर्थिक व सुरक्षा संबंधी संकट जल्द खत्म हो जाएंगे। 28 फरवरी, 2026 को इस युद्ध की शुरुआत तब हुई थी, जब अमेरिकी-इजरायली फौजों ने ईरान पर हवाई हमला किया था। जवाब में तेहरान ने भी अपने सभी घोड़े खोल दिए। नतीजतन, होर्मुज जलमार्ग पर जहाजों की आवाजाही बंद हो गई। इससे विश्व व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। एक हालिया अध्ययन बताता है कि ईरान युद्ध के कारण सालाना आकलन के हिसाब से विश्व अर्थव्यवस्था को लगभग 2.2 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता था। बेशक, 8 अप्रैल को दोनों देशों ने संघर्ष-विराम की घोषणा की थी और पाकिस्तान सहित कुछ अन्य देशों की मध्यस्थता में उनमें बातचीत भी हो रही थी, लेकिन बीच-बीच में संघर्ष-विराम के उल्लंघन की खबरें भी आती रहीं और जल्द समझौते के दावे के साथ ही ट्रंप के आक्रामक तेवर भी दिखते रहे। ऐसे में, यदि तेहरान ने पहली बार समझौते को लेकर अपनी हामी भरी है, तो इसका अर्थ है कि इस बार सफलता नजदीक है।

खबरों के मुताबिक, दोनों पक्ष इस बात पर राजी हैं कि ईरान होर्मुज जलमार्ग को खोल देगा और अमेरिका अपनी नाकेबंदी हटा लेगा। इससे होर्मुज से, जहां सैकड़ों जहाज और नाविक फंसे हुए हैं, सुरक्षित आवाजाही का रास्ता खुल जाएगा। इस एलान का त्वरित फायदा यह हुआ है कि कच्चे तेल की कीमतें गिर गई हैं और उसके दाम 100 डॉलर से गिरकर 85 डॉलर प्रति बैरल हो गए हैं। हालांकि, यह कोई पूर्ण समझौता नहीं है और इसमें ऐसे कई मुद्दे हैं, जिन पर अगले 60 दिनों में बातचीत होगी। फिर भी इसका तात्कालिक सकारात्मक असर हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे सवाल अब भी कायम हैं, जिनके जवाब नहीं मिल सके हैं।

पहला, अमेरिका बार-बार यह कहता रहा है कि वह ईरान को परमाणु क्षमता हासिल नहीं करने देगा। क्या व्हाइट हाउस अपनी मंशा में पूरी तरह कामयाब हो सका है? इसका पता तो अगले 60 दिनों में ही लगेगा।

दूसरा, ईरान अब भी दोहरा रहा है कि सभी मोर्चों पर लड़ाई रुकेगी। इसका सीधा-सा अर्थ है कि हिज्बुल्लाह के ऊपर इजरायल जो अभी हमले कर रहा है, उसको भी रोका जाएगा। क्या वाकई ऐसा हो सकेगा?

तीसरा, तेहरान यह भी दावा कर रहा है कि उसकी जब्त संपत्तियों को अमेरिका वापस कर देगा, मगर इसकी सच्चाई स्पष्ट नहीं हो सकी है।

चौथा, युद्ध के दौरान होर्मुज जलमार्ग पर ईरान ने बारूदी सुरंगे बिछा दी थीं। इनको साफ करने के लिए बड़े पैमाने पर माइन-स्वीपिंग अभियान चलाने की जरूरत होगी। इस काम को कैसे और कब तक पूरा किया जाएगा?

पांचवां, अमेरिका ने कहा है कि संभावित समझौते में होर्मुज जलमार्ग स्वतंत्र रहेगा। यानी, इस पर ईरान का कब्जा नहीं रहेगा, जबकि तेहरान इस पर टोल लगाने का पक्षधर रहा है। क्या इस विवाद का अंतिम तौर पर निपटारा हो गया है?

वैसे, देखा जाए, तो इस समझौते से सबसे अधिक राहत अगर किसी को मिलेगी, तो वह स्वयं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कूटनीतिक दांव की वजह से वह एक ऐसे पचड़े में फंस गए थे, जिसकी गंभीरता का उन्हें शुरू में अंदाजा नहीं था और इससे बाहर निकलने के लिए वह लगातार प्रयासरत थे। समझौता होने पर न सिर्फ उनकी मुश्किलें कम होंगी, बल्कि अपने देश के मध्यावधि चुनाव में उनको फायदा भी मिल सकता है। मुमकिन है कि वह खुद को शांति-दूत बताकर फिर से नोबेल पुरस्कार की मांग करने लगें। होर्मुज जलमार्ग के खुलने से आपूर्ति सुधरेगी, जिससे अमेरिका में भी महंगाई कम हो सकती है, जो इन दिनों तेजी से बढ़ी है।

इसमें कोई दोराय नहीं कि इस समझौते से ईरान का कद न सिर्फ पश्चिम एशिया में, बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ेगा। अब वह अपने पुनर्निर्माण पर ध्यान दे सकता है। युद्ध में भारी नुकसान उठाने के बावजूद उसने दुनिया को यह तो बता ही दिया कि वह किसी भी महाशक्ति का मुकाबला कर सकता है। चूंकि उसने संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, बहरीन जैसे इस खित्ते के तमाम देशों में स्थित अमेरिकी अड्डों को सफल निशाना बनाया, इसलिए भविष्य के मध्य-पूर्व के शक्ति संतुलन में ईरान खुद को बीस ही मानेगा।

अब तक यही माना जा रहा था कि इजरायल के पास ऐसी सुरक्षा प्रणाली है, जो सभी मिसाइलों को निरर्थक बना सकती है, लेकिन इस युद्ध में यह धारणा पूरी तरह से टूट गई है। तेहरान ने बार-बार यह बताया कि वह इजरायल तक अपनी मिसाइलें भेज सकता है, जिससे तेल अवीव की अचूक सैन्य ताकत वाली छवि खंडित हो गई है। अमेरिकी प्रतिबंध हटने से ईरान अब अपना तेल-गैस फिर से बेच सकेगा, जिससे उसे आर्थिक लाभ होगा। हालांकि, वहां इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) जैसी कट्टर ताकतें ज्यादा मजबूत हो जाएंगी, और इनसे विश्व समुदाय किस तरह रिश्ता रखेगा, यह देखने वाली बात होगी। कुछ लोग यह कह रहे हैं कि प्रस्तावित समझौता शायद कट्टरपंथी तबकों को स्वीकार्य नहीं है, लेकिन ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची का एलान यही बता रहा है कि यह फैसला सभी की सहमति से हुआ है।

भारत के लिए भी इन सबके गहरे निहितार्थ हैं। हमारे कई जहाज व नाविक वहां अटके हुए हैं। इतना ही नहीं, हमारी अर्थव्यवस्था पर ऊर्जा संकट का खतरा बना हुआ था, जिससे हम बच सकेंगे। युद्ध के दौरान यह धारणा बनने लगी थी कि भारत का अमेरिका-इजरायल की तरफ झुकाव बढ़ गया है। अब ईरान के पुनर्निर्माण में मदद करके भारत इस धारणा को तोड़ सकता है। वहां से तेल व गैस की आपूर्ति फिर से शुरू हो सकती है। बहुत मुमकिन है कि चाबहार बंदरगाह व अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा को आगे बढ़ाया जाए। यह तेहरान के साथ नई दिल्ली की एक नई शुरुआत होगी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

सरकारी और निजी नौकरी का अंतर मिटाना चाहिए

राय की राय
यहां स्कैन करें

विभूति नारायण राय | पूर्व कुलपति एवं साहित्यकार

पूरे उत्तर प्रदेश में 6 जून से 10 जून के मध्य रेलवे और बस स्टेशनों पर लोगों को थके उदास चेहरों वाली एक अनियंत्रित भीड़ दिखाई दी। इसमें वे नौजवान शरीक थे, जो किसी न किसी तरह एक सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं, भले ही यह नौकरशाही के पदक्रम में सबसे निचले पायदान पर स्थित क्यों न हो। इसके लिए वे कुछ भी करने को तैयार थे। उन्होंने महीनों, कुछ मामलों में तो वर्षों, इसके लिए शारीरिक और बौद्धिक तैयारी की थी। जिन्हें उम्मीद नहीं थी कि ईमानदारी से कुछ हो सकता है, वे खेत-बारी बेचकर दलालों की तलाश कर रहे थे। ये सब उन शहरों की तरफ भागे चले जा रहे थे, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस के 32 हजार से अधिक कांस्टेबलों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होने वाली थी। 28 लाख से कुछ अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे और उनमें से लगभग 22 लाख लिखित परीक्षा में बैठे।

पिछले कुछ वर्षों में नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी हो गया है। अपने गांव के एक पुस्तकालय में बैठकर मैंने बहुत से ऐसे नौजवानों से बात करके समझने की कोशिश की है कि आखिर वह कौन सा चुंबक है, जो इन्हें छोटी सी सरकारी नौकरी के लिए इस कदर आकर्षित करता है कि वे येन-केन-प्रकारेण इसे हासिल करने में जुट जाते हैं? वहां मुझे एक नौजवान मिलता है, जिसने पश्चिमी यूपी के एक कॉलेज से बीएससी (बायो-टेक्नोलॉजी) कर रखा है। उसकी भारी-भरकम डिग्री से प्रभावित होकर मैं जानने की कोशिश करता हूं कि वह अपने अध्ययन क्षेत्र की संभावनाओं को छोड़कर कांस्टेबल की नौकरी हासिल करने की कोशिश क्यों कर रहा है? समझना बहुत मुश्किल नहीं है। वह देहरादून की एक फर्म में नौकरी कर रहा था, जहां उसे 18,000 रुपये महीने पगार मिलती थी। प्रतिदिन दस घंटे से अधिक काम वाली इस नौकरी में कोई स्थायित्व या सुरक्षा नहीं थी।

बढ़ती युवा शक्ति के लिए एक बड़ी औद्योगिक क्रांति की जरूरत होगी, जिसमें सेवा क्षेत्र के मुकाबले विनिर्माण क्षेत्र पर ध्यान देना होगा।

हमारी बातचीत से आकर्षित होकर दूसरे लड़के-लड़कियां भी अपनी पढ़ाई छोड़कर हमारे इर्द-गिर्द सिमट आते हैं। वे सब किसी न किसी तरह से एक अदद सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए पुस्तकालय में हाड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं। सबके चेहरे निस्तेज हैं और किसी की आंखों में यह विश्वास नहीं झलक रहा कि उनकी मेहनत सफल हो सकेगी। कारण स्पष्ट है, सरकारी नौकरियां बहुत कम हैं। सालों बाद जब कोई परीक्षा होती भी है, तो कुछ सौ जगहों के लिए कई लाख अभ्यर्थी टूट पड़ते हैं और अगर पेपर आउट होने या अदालती हस्तक्षेप जैसी आशंकाओं से बच भी जाएं, तो इस प्रक्रिया में जिन युवाओं को नौकरी मिलती है, उनकी संख्या ऊंट के मुंह में जीरा जैसी होती है।

सरकारी और निजी क्षेत्र की नौकरियों के बीच वेतन का अंतर पिछले वर्षों में भयानक रूप से बढ़ा है। खास तौर से पांचवें और छठे वेतन आयोगों के बाद यह खाई और चौड़ी हो गई है। इस फर्क को समझने के लिए एक उदाहरण पर्याप्त होगा। मुझे याद है, जब 2008 में मैं हिंदी विश्वविद्यालय का कुलपति हुआ, तब तक सरकारी संस्थानों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के ज्यादातर पद ठेके पर दे दिए गए थे। विश्वविद्यालय में आधे ड्राइवर स्थायी सरकारी नौकर थे, जिन्हें 40 हजार रुपये के लगभग वेतन मिलता था और साथ में छुट्टियां, आवास, चिकित्सा व बच्चों के लिए शिक्षा भत्ते जैसी सुविधाएं अलग थीं। इनके बरक्स ठेके पर आने वाले ड्राइवर बिना किसी अतिरिक्त सुविधा के 15-20,000 पर वही काम कर रहे थे। यह असमानता दिनोंदिन बढ़ती ही चली गई।

यह एक सामान्य समझ है कि दुनिया में कोई भी सरकार अकेले सबको नौकरी नहीं दे सकती। सरकारें रोजगार सृजन के लिए सहायक स्थितियां निर्मित कर सकती हैं। एक साक्षात्कार में राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषक अजित कुमार झा ने जोर देकर कहा है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है (साल 2023-24 में राष्ट्रीय वृद्धि दर से अधिक 2.2 प्रतिशत आंकी गई) और इसकी औसत उम्र 24.7 वर्ष हो गई है। इस बढ़ती युवा शक्ति के लिए एक बड़ी औद्योगिक क्रांति की जरूरत होगी, जिसमें सेवा क्षेत्र के मुकाबले विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसे सुधारों की जरूरत है, जिनसे बेरोजगारों की फौज के स्थान पर रोजगार योग्य नौजवान तैयार हो सकें।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

साधना का लक्ष्य

किसी सुनार को कुछ अशुद्धि वाला सोना दे दिया जाए, तो वह उसका क्या करेगा? वह उसे फेंकेगा नहीं, क्योंकि सुनार भली-भांति यह जानता है कि आग, धैर्य और सही प्रक्रिया से वही सोना फिर चमकने लगेगा। आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य भी कुछ ऐसा ही है। उसके भीतर अनंत संभावनाएं हैं, किंतु क्षणिक कामना, भय, मोह, क्रोध व अहंकार जैसी मानसिक अशुद्धियां उसकी वास्तविक चमक को ढक देती हैं। साधना का असली उद्देश्य इन्हीं अशुद्धियों को मिटाकर मनुष्य को उसके मूल स्वरूप से परिचित कराना है।

आध्यात्मिक दर्शन के अनुसार, सृष्टि का विकास सूक्ष्म से स्थूल की ओर हुआ है। ब्रह्मांडीय चेतना पहले आकाश तत्व में, फिर वायु, अग्नि, जल और अंततः पृथ्वी तत्व में क्रमशः अधिक स्थूल रूप में प्रकट हुई। यही कारण है कि पृथ्वी तत्व सबसे अधिक इंद्रियगोचर है और आकाश सबसे सूक्ष्म। मन सामान्यतः स्थूल वस्तुओं की ओर आकर्षित होता है, क्योंकि उन्हें इंद्रियां आसानी से ग्रहण कर लेती हैं। साधना का प्रथम चरण इसी प्रवृत्ति को उलटना है; मन को स्थूल से हटाकर सूक्ष्म की ओर ले जाना। जब मन बाहर से हटकर भीतर की ओर मुड़ता है, तब आत्मशुद्धि की यात्रा प्रारंभ होती है।

लेकिन, यह यात्रा आसान नहीं है। मन में वर्षों से संचित संस्कार, इच्छाएं और प्रतिक्रियाएं गहराई तक जमी होती हैं। सुख मिलने पर हम उनसे चिपक जाते हैं और दुख मिलने पर उनसे भागना चाहते हैं। यही आकर्षण और विकर्षण मन को अस्थिर बनाए रखते हैं। आध्यात्मिक साधक का लक्ष्य इन दोनों के पार जाना है। वह न सुख का दास बनता है, न दुख का शिकार। वह दोनों को जीवन के अनुभवों के रूप में स्वीकार करना सीखता है। तब यम- नियम का महत्व सामने आता है।

सत्य, अहिंसा, अस्तेय (ईमानदारी), शौच, संतोष व अनुशासन जैसे सिद्धांत मन को शुद्ध करने वाले पवित्र जल के समान हैं। इस संदर्भ में मनुष्य की तुलना अशुद्ध सोने से अत्यंत सार्थक है। अशुद्धियां सोने का स्वभाव नहीं होतीं; वे केवल उस पर चढ़ी हुई परतें होती हैं। उसी प्रकार लोभ, ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार भी मनुष्य का वास्तविक स्वरूप नहीं हैं। वे प्रकृति द्वारा निर्मित अस्थायी विकृतियां हैं। साधना की अग्नि में तपकर ये धीरे-धीरे दूर होती हैं।

अशुद्धियां सोने का स्वभाव नहीं होतीं, वे उस पर चढ़ी हुई परतें होती हैं। उसी प्रकार, लोभ, ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार भी मनुष्य का स्वरूप नहीं हैं। वे प्रकृति द्वारा निर्मित अस्थायी विकृतियां हैं।

आत्मशुद्धि की यह यात्रा किसी विशेष वर्ग या संप्रदाय की नहीं, बल्कि प्रत्येक मनुष्य की यात्रा है। जिस दिन हम अपने भीतर छिपे सोने को पहचान लेंगे और उसे साधना की अग्नि में तपाने का साहस जुटा लेंगे, उसी दिन जीवन की दिशा बदल जाएगी। तब बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हों, भीतर एक ऐसी शांति और प्रकाश का उदय होगा, जिसे कोई छीन नहीं सकता।

श्री श्री आनंदमूर्ति

योगी आदित्यनाथ | मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

आज घर सूने हो रहे हैं और वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं। यह स्थिति क्यों आई? सनातन संस्कृति में माता-पिता व गुरु को साक्षात ईश्वर माना जाता है। वृद्ध जनों का सम्मान केवल संस्कार नहीं, बल्कि हमारी गौरवशाली सभ्यता की पहचान है।

अनुलोम-विलोम

प्लास्टिक मुद्रा

नकदी व्यवस्था अधिक सुरक्षित होगी

भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से प्लास्टिक नोट जारी करने को लेकर जो खबर आई है, वह पुरसुकून है। यूपीआई और डिजिटल भुगतान की क्रांति ने भारत की वित्तीय व्यवस्था को नई दिशा दी है। आज देश में प्रतिमाह अरबों डिजिटल लेन-देन हो रहे हैं, फिर भी एक बड़ा वर्ग ऐसा है, जो नकद मुद्रा पर निर्भर है। किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, ग्रामीण बाजार और असंगठित क्षेत्र में नकद रुपये का महत्व आज भी बरकरार है। यही कारण है कि डिजिटल भुगतान के बढ़ते प्रसार के बावजूद नकद मुद्रा की मांग बनी हुई है। ऐसे में, भारतीय मुद्रा को अधिक सुरक्षित, टिकाऊ और आधुनिक बनाने के लिए प्लास्टिक नोटों की तरफ बढ़ना सुखद है।

प्लास्टिक नोट देखने और उपयोग में सामान्य नोटों जैसे ही होते हैं, लेकिन इनकी आयु कागजी नोटों की तुलना में पांच से सात गुना अधिक होती है। पानी, नमी, धूल, गंदगी और फटने के प्रति इनकी प्रतिरोधक क्षमता कहीं अधिक होती है। भारत जैसे जलवायु की विविधता वाले देश में, जहां तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक नमी और कई इलाकों में धूल-मिट्टी की समस्या रहती है, वहां प्लास्टिक नोट अधिक उपयोगी साबित हो सकते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भी प्लास्टिक मुद्रा महत्वपूर्ण है। नकली नोटों का कारोबार लंबे समय से देश की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती बना हुआ है। प्लास्टिक नोटों में विशेष सुरक्षा फीचर होते हैं, जिनकी नकल करना बेहद कठिन है, नतीजतन इसके जाली होने की आशंका काफी कम हो जाती है।

प्लास्टिक नोटों का एक अन्य लाभ स्वच्छता से भी जुड़ा है। कागजी नोटों पर बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्मजीव आसानी से पनप सकते हैं, जबकि प्लास्टिक की चिकनी सतह पर इनका टिकना अपेक्षाकृत कठिन होता है। कोविड-19 महामारी के बाद स्वच्छ मुद्रा की आवश्यकता को अधिक गंभीरता से महसूस किया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने 1988 में सबसे पहले प्लास्टिक नोटों को अपनाया था। आज ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम और रोमानिया सहित लगभग 60 देशों में इस तरह की व्यवस्था सफलतापूर्वक काम कर रही है। भारत में भी 2009 से इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं और अगले तीन-चार वर्षों में कुछ शहरों में परीक्षण की योजना भी बनी थी, पर बात आगे नहीं बढ़ सकी। आज समय की मांग है कि इस विचार को पुनः गति दी जाए। हालांकि, इसके उपयोग के बाद इनके पुनर्चक्रण (रिसाइक्लिंग) की प्रभावी व्यवस्था भी विकसित करनी होगी, ताकि प्लास्टिक कचरे की नई समस्या उत्पन्न न हो।

विभूति बुपक्या, टिप्पणीकार

पहले रुपया पर वैश्विक भरोसा लौटाइए

यह सही है कि भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर मुद्रा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, टिकाऊ और आधुनिक बनाने के लिए नए प्रयोग करता रहा है, और इसी क्रम में प्लास्टिक नोट जारी करने की भी संभावना है, लेकिन यह ऐसा कदम होगा, जिसकी सफलता की स्पष्ट भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। भले ही, पॉलिमर नोटों के सामान्य कागजी नोटों की तुलना में अधिक टिकाऊ होने की बात कही जाती है, लेकिन सबसे पहले जरूरी यह है कि रुपये पर वैश्विक भरोसे को टिकाऊ बनाया जाए। ऐसे वक्त में, जब डॉलर के मुकाबले रुपया अपने मूल्य की जंग लड़ रहा हो, तब प्लास्टिक नोट शुरू करने जैसी बातें भला क्या मतलब रखती हैं? पहले रुपये पर वैश्विक भरोसा तो लौटाइए, फिर उसे कागजी से प्लास्टिक की ओर ले जाइए।

समझना यह भी चाहिए कि पूर्व में ऐसी कोशिश परवान नहीं चढ़ सकी है। तथ्य यही है कि साल 2014 के आसपास सरकार ने देश के पांच शहरों- जयपुर, शिमला, भुवनेश्वर, मैसूर और कोच्चि में 10 रुपये के प्लास्टिक नोटों का एक छोटा सा टेस्ट (ट्रायल) किया था, जो सफल नहीं हो सका। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि देश के एटीएम और बैंकों की नोट गिनने वाली मशीनें केवल कागजी नोटों के हिसाब से बनी थीं, जिस कारण प्लास्टिक के नोटों की वजह से मशीनें बार-बार जाम होने लगीं। इतना ही नहीं, भारत गर्म देश है, यहां तेज गर्मी पड़ती है। गर्मी के कारण प्लास्टिक नोटों के आपस में चिपकने और सिकुड़ने का डर भी था। इन्हीं सब कारणों से इस काम को रोक दिया गया और सरकार ने अपने कदम वापस ले लिए। आज फिर से उसी तरह की कवायद को आगे बढ़ाया जा रहा है, जबकि देश की भौगोलिक दशा में कोई बदलाव नहीं हुआ है, अलबत्ता ग्लोबल वार्मिंग के कारण बेहिसाब गर्मी का दौर लंबा रहने लगा है।

इसका अर्थ है कि या तो प्लास्टिक नोट चलाने की कोई जरूरत नहीं है और अगर इसे चलाना जरूरी है, तो पूर्व के अनुभवों से सबक लेना चाहिए और पूरी सुरक्षा के साथ इसे लागू करना चाहिए। यह सही है कि मुद्रा से जुड़े सुरक्षा उपायों पर काम होना चाहिए, जिसके लिए रिजर्व बैंक को प्रयास करना ही चाहिए। किंतु इसके लिए पुरानी मुद्रा में ही सुरक्षा उपाय बेहतर किए जा सकते हैं, क्योंकि नई मुद्रा छापने और उस अनुकूल व्यवस्था बनाने में काफी खर्च होगा। भारत जैसे देश में, जो अपने लोगों को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने में ही अभी ज्यादा खर्च कर रहा हो, वहां नई मुद्रा पर फिजूल खर्च करने का कोई मतलब नहीं है।

स्वाति कुमारी, टिप्पणीकार

हिंसा की भावना से भी दूर रहिए

हमारे शास्त्र हिंसा का विरोध करते हैं। फिर भी हिंसा होती है, तो क्यों? हिंसा के क्या बड़े कारण हैं? एक धारणा यह भी है कि समस्त क्रूरता के लिए विचार ही जिम्मेदार है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम हिंसा की भावना से भी दूर रहें।

अध्यात्म
जे. कृष्णमूर्ति

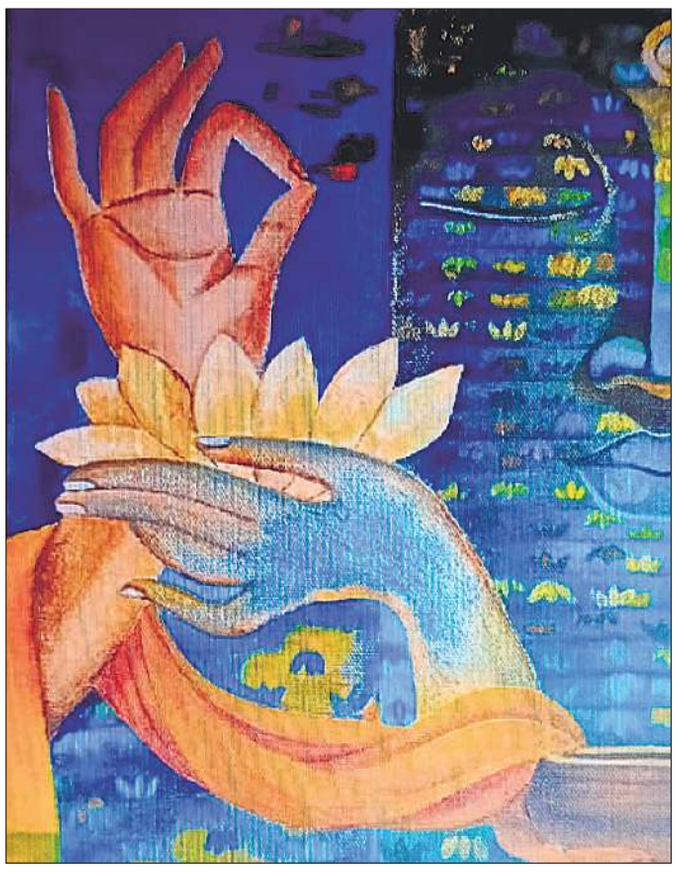

मनुष्य की मदद के लिए विचार ने आश्चर्यजनक काम किए हैं, किंतु साथ ही साथ वह बहुत बड़े विध्वंस तथा आतंक का भी कारण बना है। इस विचार के स्वरूप को, इसकी गति को हमें समझना है। आप विशिष्ट ढंग से ही क्यों सोचते हैं। विचार के कुछ विशिष्ट प्रकारों से आप क्यों चिपके रहते हैं। कुछ विशेष अनुभवों को क्यों पकड़े रहते हैं। आज तक विचार मृत्यु की प्रकृति क्यों नहीं समझ पाया है?

क्रूरता के लिए विचार जिम्मेदार

विचार की समस्त संरचना की ही हमें जांच करनी होगी। आपके अपने विचार की नहीं, क्योंकि यह तो जाहिर ही है कि आपके विचार क्या हैं, इसलिए कि आप तो पूर्वनियोजित हैं, परंतु विचार-प्रक्रिया की यदि आप गंभीरता से जांच-पड़ताल करते हैं, तो आप एक पूर्णतः भिन्न आयाम में प्रवेश करते हैं। अपनी छोटी-मोटी जाती समस्या के दायरे में नहीं। आपको विचार की इस विस्मयकारी गति को, इसकी प्रकृति को समझना होगा। किसी दार्शनिक, किसी धार्मिक मनुष्य, किसी विशिष्ट व्यवसायी या किसी गृहिणी की दृष्टि से नहीं, अपितु आपको विचार-प्रक्रिया की प्रचंड जीवंतता को समझना होगा।

युद्ध, युद्ध-तंत्र, युद्ध की बर्बरता, हत्याएं, आतंक, बमबारी, किसी उद्देश्य के बहाने या बिना किसी उद्देश्य के बंधक बनाना, इस समस्त क्रूरता के लिए विचार ही जिम्मेदार है। विचार ही धर्मागारों के लिए, उनकी सुंदर बनावट के लिए और प्यारी कविताओं के लिए भी जिम्मेदार है। सारे तकनीकी विकास के लिए, सीखने की तथा मानवीय चिंतन के परे निकल जाने की असाधारण क्षमता रखने वाले कंप्यूटर के लिए भी यह विचार ही जिम्मेदार है।

यह विचार करना, सोचना अपने आप में है क्या? यह है स्मृति का प्रत्युत्तर, स्मृति की प्रतिक्रिया। यदि आपके पास स्मृति नहीं होती, तो आप विचार नहीं कर पाते। स्मृति मस्तिष्क में जानकारी के रूप में संचित होती है। जानकारी अनुभव का परिणाम होती है। यही है हमारे मस्तिष्क के कार्य करने का ढंग। पहले अनुभव, वह अनुभव संभवतः मनुष्य के आरंभ से चला आ रहा है, जो हमें विरासत में मिला है। उस अनुभव से जानकारी आती है। वह जानकारी मस्तिष्क में संगृहीत होती है। उस जानकारी से स्मृति और स्मृति से विचार का आगमन होता है।

सुख-दुख के कारण

विचार के कारण आप कर्म में प्रवृत्त होते हैं। कर्म से आप और अधिक सीखते हैं। यह चक्र चलता रहता है। अनुभव, जानकारी, स्मृति, विचार, कर्म तथा कर्म से और सीखना। फिर इसी चक्र का आवर्तन। हम इसी प्रकार पूर्वनियोजित हैं। हमेशा हम यही कर रहे हैं। अतीत में भोगे गए दुख की स्मृति दुख के कारण से बचने के लिए हमें प्रवृत्त करती है, ताकि भविष्य में दुख से बच सकें। यही अनुभव फिर जानकारी का रूप धारण कर लेता है और फिर वही पुनरावर्तन। काम-सुख और फिर वही पुनरावृत्ति। यही है विचार की गति।

मजे की बात देखिए विचार कैसे यंत्रवत कार्य करता है, विचार अपने आपसे कहता है, 'मैं कार्य करने के लिए स्वतंत्र हूं।' फिर भी विचार कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि वह जानकारी पर निर्भर होता है और जानकारी स्पष्ट रूप से हमेशा सीमित होती है। जानकारी हमेशा सीमित ही रहेगी, इसलिए कि वह समय का अंश है।

विचार सीमित होता है और परिणामस्वरूप विचार से उत्पन्न हर एक कर्म भी सीमित ही होगा। यह सीमितता अवश्य ही द्वंद्व उत्पन्न करेगी, विभाजन उत्पन्न करेगी। हम जिन समस्याओं से घिरे हुए हैं, वे सारी विचार की ही उपज हैं। हमारा मस्तिष्क इन समस्याओं को सुलझाने के लिए शिक्षित, प्रशिक्षित तथा संस्कारबद्ध है। समस्याएं विचार की ही उपज हैं, इसलिए राष्ट्रीयताओं में विभाजन होता है। विभिन्न आर्थिक संरचनाओं के बीच विभाजन तथा द्वंद्व विचार की ही निर्मिति हैं।

द्वंद्व के कारण संघर्ष

विचार ने ही विभिन्न धर्मों को जन्म दिया है और उनके बीच विभाजन भी उसी की देन है, परिणामस्वरूप धर्मों के बीच द्वंद्व रहता है। हमारा मस्तिष्क विचार ही से उत्पन्न समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करने के लिए प्रशिक्षित है। अपने विचार का तथा उससे उत्पन्न अपनी प्रतिक्रियाओं का स्वरूप गहराई से समझना हमारे लिए अत्यावश्यक है। हम चाहे कुछ भी कर रहे हों, विचार हमारे जीवन पर छाया रहता है। कुछ भी कर्म घटित हो, उसके पीछे विचार ही होता है। गतिविधि चाहे ऐंद्रिक हो, बौद्धिक हो या जैविक, विचार लगातार कार्यरत रहता है। जैविक रूप से हमारा मस्तिष्क सदियों से पूर्वनियोजित किया गया है। हर कर्म की शुरुआत विचार से होती है, इसलिए हमें चाहिए कि हम वैचारिक हिंसा से भी दूर रहें। जब मन में हिंसा के विचार नहीं आएंगे, तो हम हिंसा से भी दूर रहेंगे।

संस्कारित किया गया शरीर अपने ढंग से कार्य करता है- सांस लेने की क्रिया, हृदय की धड़कनें और ऐसी ही और कई सारी क्रियाएं। उसी प्रकार यदि आप कैथलिक हैं या हिंदू अथवा बौद्ध, तो आप भी अपनी उस संस्कारबद्धता की बार-बार पुनरावृत्ति करते रहेंगे।

विचार समय तथा अवकाश के तहत घटित होने वाली गतिविधि है। विचार स्मृति, विगत बातों का स्मरण है। विचार है, जानकारी की क्रिया। यह ज्ञान लाखों वर्षों से संगृहीत हो कर मस्तष्कि में स्मृति के रूप में संचित है।

विचार सीमित होता है और परिणामस्वरूप विचार से उत्पन्न हर एक कर्म भी सीमित ही होगा। यह सीमितता अवश्य ही द्वंद्व उत्पन्न करेगी, विभाजन उत्पन्न करेगी। हम जिन समस्याओं से घिरे हुए हैं, वे सारी विचार की ही उपज हैं, इसलिए विचारों पर नियंत्रण जरूरी है।

योग दिवस (21 जून)

हनुमान ने किया सूर्य नमस्कार

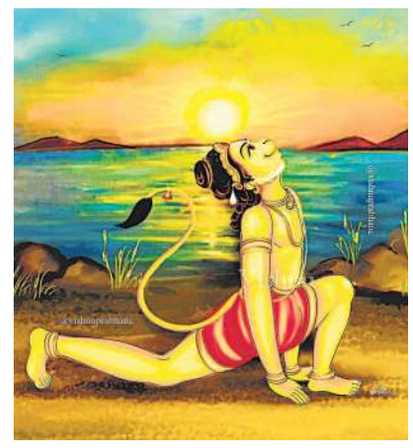

हनुमान बड़े हुए, तो उनकी शिक्षा की बात सामने आई। उनके माता-पिता अंजना और केसरी ने उन्हें ज्ञान प्राप्ति के लिए समस्त वेदों के ज्ञाता सूर्य के पास भेजा। हनुमान ने सूर्य से निवेदन किया कि वे उनका शिष्य बनना चाहते हैं। सूर्य ने कहा कि उनके लिए एक क्षण भी रुकना संभव नहीं है। वे निरंतर गतिमान हैं। हां, यदि वे उनकी गति से चलते हुए शिक्षा ग्रहण कर सकें, तभी उन्हें उनका गुरु बनना स्वीकार होगा। हनुमान ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। वे सूर्य के सम्मुख मुख करके पीछे की ओर उड़ने लगे। यह उनका गुरु के प्रति सम्मान और समर्पण का भाव था। हनुमान की पीछे की ओर चलते हुए शिक्षा ग्रहण करने की यात्रा सूर्य नमस्कार का आधार बनी।

एक अन्य कथा के अनुसार शिक्षा पूर्ण होने पर जब हनुमान ने गुरु दक्षिणा देनी चाही, तो सूर्य ने मना कर दिया, तब हनुमान ने सूर्य को गुरु दक्षिणा के रूप में विभिन्न मुद्राओं द्वारा अपना नमस्कार अर्पित किया, जो सूर्य नमस्कार के रूप में जाना गया।

आगे चलकर ऋषि कण्व ने सूर्य नमस्कार को साधना का रूप दिया। इसके बारह आसनों के साथ बारह मंत्र जोड़े। ये आसन हैं- प्रणामासन, हस्तउत्तानासन, पादहस्तासन, अश्व संचालन आसन, दंडासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालन आसन, पादहस्तासन, हस्तउत्तानासन और ताड़ासन। इसके प्रत्येक चरण का अलग सूर्य मंत्र है :

ओम सूर्याय नमः – यहां सूर्य को अंधकार दूर करने वाले ईश्वर के रूप में मानकर उनकी स्तुति इस भाव से की जाती है कि हमारे जीवन से भी अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो।

ओम मित्राय नमः – इस मंत्र से सूर्य को मित्र भाव से प्रणाम किया जाता है। यही मित्र भाव हमारा सबके प्रति रहना चाहिए।

ओम रवये नमः – जो स्वयं प्रकाशवान होकर संपूर्ण जगत को प्रकाश देता है। वही प्रकाश हमें भी प्राप्त हो।

ओम भानवे नमः – भौतिक स्तर पर गुरु के रूप में सूर्य हमारे सभी भ्रम को दूर करें।

ओम खगाय नमः – यानी आकाशगामी सूर्य को प्रणाम, जो समय का ज्ञान करवाते हैं।

ओम पूष्णे नमः – हमारा सभी प्रकार से पोषण करने वाले सूर्य देव हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करें।

ओम हिरण्यगर्भाय नमः – प्रदीप्त अंडे के समान और सूर्य की तरह तेजस्वी ईश्वर को प्रणाम।

ओम मरीचये नमः – हमें जीवन की मृग मरीचिकाओं से बचाने वाले सूर्य देव को प्रणाम।

ओम आदित्याय नमः – अदिति सुत को प्रणाम।

ओम सवित्रे नमः – हमें जाग्रत करने वाले उगते हुए सूर्य देव को नमस्कार।

ओम अर्काय नमः – संपूर्ण ब्रह्मांड के ऊर्जा स्रोत को प्रणाम।

ओम भास्कराय नमः – जीवन के मुक्ति मार्ग को प्रकाशित करने वाले आत्मज्ञान के प्रतीक सूर्य को प्रणाम।

अरुण कुमार जैमिनि

धूमावती जयंती (22 जून)

धुएं से प्रकट हुईं धूमावती माता

दस महाविद्याओं में सातवीं महाविद्या धूमावती की जयंती ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। ऋग्वेद में सती के धूमावती रूप को सुतरा कहा गया है। धूमावती के कुछ अन्य नामों में ज्येष्ठा, अलक्ष्मी और निर्ऋति भी है। धूमावती के इस स्वरूप की दो भुजाएं हैं, जिसमें एक हाथ में सूप तथा दूसरा हाथ वरदान मुद्रा में है या ज्ञान प्रदायनी मुद्रा में है। उनका यह स्वरूप कुरूप, खुले हुए केश, दुबली-पतली, सफेद साड़ी पहने हुए बिना अश्व के रथ पर सवार हैं, जिसके शीर्ष पर ध्वज एवं प्रतीक के रूप में कौआ विराजमान रहता है।

इनके इस नामकरण के पीछे एक कथा है। कहा जाता है कि एक बार सती के पिता राजा दक्ष ने अपने यहां विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन राजा दक्ष ने शिव और सती को इस आयोजन में आमंत्रित नहीं किया। सती ने विचार किया कि पुत्री तो बिना निमंत्रण के भी पिता के घर जाने का अधिकार रखती है। यह सोचकर उन्होंने अपने मन की बात शिव से कही।

शिव ने उन्हें समझाते हुए कहा कि विवाह के पश्चात पुत्री को अपने पिता के घर भी बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। सती शिव के तर्कों से सहमत नहीं हुईं, लेकिन वहां जाकर वे अपने पिता के तिरस्कारपूर्ण व्यवहार और शिव के अपमान से दुखी होकर यज्ञ की अग्नि में जलकर भस्म हो गईं। उनके जलने पर जो धुआं निकला, उससे ही धूमावती का जन्म हुआ।

पुराणों में धूमावती के जन्म के संबंध में एक अन्य कथा भी मिलती है। एक बार कैलास पर खाने के लिए कुछ नहीं था, तब पार्वती भगवान शिव के पास गईं, लेकिन शिव समाधि में लीन थे। उन्होंने भूख से व्याकुल होकर शिव को ही निगल लिया, लेकिन शिव के कंठ में विष होने के कारण पार्वती के मुंह से धुआं निकलने लगा। उनका शरीर जर्जर और विकृत होने लगा। तब पार्वती की प्रार्थना पर शिव उनके शरीर से बाहर निकल आए और कहा कि आज से तुम देवी 'धूमावती' के रूप में पूजी जाओगी। अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए तुमने अपने पति को ही निगल लिया, इसलिए तुम्हारे इस रूप को विधवा होने का शाप मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि इस शाप के कारण ही माता धूमावती की पूजा विवाहिताएं नहीं करती हैं।

धूमावती रोग, दरिद्रता और शत्रुओं से मुक्ति दिलाती हैं। इनकी पूजा पश्चिम दिशा में मुख करके की जाती है। इनकी आराधना से केतु से संबंधित दोष मिटते हैं। इन्हें भोग में मीठा नहीं, बल्कि नमकीन का प्रसाद चढ़ाया जाता है और पूजा में किसी भी प्रकार की रंगीन वस्तु या वस्त्र का उपयोग नहीं किया जाता। मध्य प्रदेश के दतिया के अलावा वाराणसी स्थित मां धूमावती मंदिर और असम में मां कामाख्या मंदिर परिसर में दिव्य मां धूमावती के सिद्ध मंदिर हैं।

अश्वनी कुमार

पूजा-पाठ में संकल्प क्यों जरूरी

पूजा-पाठ और कर्मकांड में संकल्प अनिवार्य क्यों होता है?

-माधव अरोड़ा, नोएडा

आस्था-अनास्था

डॉ. प्रकाशचंद्र गंगराड़े

आमतौर पर संकल्प किसी कार्य को करने की दृढ़ इच्छाशक्ति को कहते हैं। यह किसी कार्य को करने से पहले की स्थिति होती है। जैसे कहा जाता है कि यदि मेरा अमुक संकल्प पूरा हो जाए, तो मैं भगवान के मंदिर जाऊंगा या किसी जरूरतमंद को कुछ दान करूंगा।

पूर्ण श्रद्धा, आत्मविश्वास, एकाग्रता के साथ किसी शुभ कार्य, जैसे पूजा-पाठ आदि कर्मकांड को पूर्ण करने वाली धारणाशक्ति का नाम ही संकल्प है। उल्लेखनीय है कि दान और यज्ञ का पुण्य तभी प्राप्त होता है, जब संकल्प सहित उन्हें पूरा किया जाता है, इसलिए पूजा-पाठ सहित किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान में संकल्प अनिवार्य होता है। मनुस्मृति में लिखा है-

संकल्पमूलः कामयो वै यज्ञः संकल्पसंभवाः।
व्रतानि यमधर्मश्च सर्वे संकल्पजाः स्मृताः॥

(मनुस्मृति 2/3)

अर्थात कामना का मूल संकल्प ही होता है और यज्ञ संकल्प से ही होते हैं। व्रत, यज्ञादि समस्त धर्मानुष्ठानों का आधार संकल्प ही कहा गया है।

संकल्प के माध्यम से हमें अपने गोत्र, जाति व अन्य विशेषताओं का निरंतर स्मरण रहता है और गौरव की अनुभूति होती है। इसी से व्यक्ति द्वारा किए गए दुष्कर्मों का नाश होकर शक्ति और स्फूर्ति मिलती है।

पुरोहित संकल्प के द्वारा जल ग्रहण कराते हैं, ताकि जिस काम को यजमान करने जा रहा है, उस कार्य को पूरा करने में प्रभु उसकी पूर्ण मदद करें, क्योंकि वह उसके प्रति संकल्पबद्ध है। चूंकि जल में वरुण देव का निवास माना गया है, अतः उसे ग्रहण कर संकल्प का पालन न करने वाले को वे कठोर दंड देते हैं।

वेद में लिखा है- *'अप्सु वै वरुण' (तैत्तिरीय 16/3/6)* तथा *'अनृते खलु वै क्रियमाणे वरुणो गृह्णति' (तैत्तिरीय 1/7/2/6)*, इसलिए जीवन में जल का विशेष महत्व है। धर्मानुष्ठानों के अलावा मरणोपरांत पितृ-तर्पण में भी जल की विशेष जरूरत होती है।

(साभार : 'हिंदुओं के रीति रिवाज तथा मान्यताएं', पुस्तक महल, दिल्ली)

सप्ताह के व्रत-त्योहार

16 जून से 22 जून 2026 तक

16 जून (मंगलवार) : द्वितीय (शुद्ध) ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया तिथि रात्रि 12.53 मिनट तक। द्वितीय (शुद्ध) ज्येष्ठ शुक्ल प्रारंभ। चंद्रदर्शन।

17 जून (बुधवार) : द्वितीय (शुद्ध) ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया तिथि रात्रि 09.39 मिनट तक। रंभा तृतीया व्रत। महाराणा प्रताप जयंती। मोहर्रम (मु.) मास शुरु। हिजरी सन् 1448 प्रारंभ।

18 जून (गुरुवार) : द्वितीय (शुद्ध) ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी तिथि सायं 06.59 मिनट तक। विनायकी श्रीगणेश चतुर्थी व्रत। श्री गुरु अर्जुनदेव बलिदान दिवस। गुरुपुष्य योग।

19 जून (शुक्रवार) : द्वितीय (शुद्ध) ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी तिथि सायं 05.00 बजे तक पश्चात षष्ठी तिथि। गंडमूल विचार।

20 जून (शनिवार) : द्वितीय (शुद्ध) ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी तिथि अपराह्न 03.47 मिनट तक पश्चात सप्तमी तिथि। अरण्य षष्ठी। विंध्यवासिनी पूजा। गंडमूल प्रातः 09.26 मिनट तक।

21 जून (रविवार) : द्वितीय (शुद्ध) ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी तिथि अपराह्न 03.21 मिनट तक। भद्रा अपराह्न 03.21 मिनट से रात्रि 03.31 मिनट तक। सायन दक्षिणायन प्रारंभ।

22 जून (सोमवार) : द्वितीय (शुद्ध) ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी तिथि अपराह्न 03.41 मिनट तक पश्चात नवमी तिथि। श्रीदुर्गाष्टमी। धूमावती जयंती। मेला क्षीर भवानी (काश्मीर)। शक आषाढ़ प्रारंभ।

-पं. ऋभुकांत गोस्वामी

भेजें अपने सवाल

स्वर्ग-नरक की कल्पना का आधार क्या है?

पाप क्या है, पुण्य क्या है? धर्म क्या है, अधर्म क्या है? ईश्वर की आराधना कैसे करें? ऐसे सवाल अकसर हमारे मन में उठते हैं, पर इनका जवाब हमारे पास नहीं होता। मन-मस्तिष्क में आने वाले ऐसे ही सवालों के जवाब हमारे पैनल में शामिल धर्माचार्य आपको देंगे।

अपने सवाल हमें इस पते पर भेजें :
धर्मक्षेत्रे, हिन्दुस्तान, 11वां तल, द आइकॉन टॉवर, एफ सी-24 सी, फिल्म सिटी, सेक्टर-16ए, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर-201301 (उत्तर प्रदेश)

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

मेष : मन अशांत हो सकता है। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। वाहन सुख में वृद्धि होगी। आय भी बढ़ेगी।

वृष : नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा, परंतु कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है। परिश्रम अधिक रहेगा। कठिनाइयां भी आ सकती हैं। आय में वृद्धि होगी।

मिथुन : आत्मसंयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। कारोबार में वृद्धि होगी। परिवार का साथ मिलेगा। किसी मित्र के सहयोग से लाभ के अवसर भी मिलेंगे।

कर्क : मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। परिवार का साथ मिलेगा। कारोबार में बदलाव के योग बन रहे हैं। किसी दूसरे स्थान पर भी जा सकते हैं। खर्चों में वृद्धि होगी।

सिंह : मन अशांत हो सकता है। पिता की सेहत का ध्यान रखें। खर्चों में वृद्धि होगी। नौकरी में कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है। आय में वृद्धि भी होगी।

कन्या : कारोबार में वृद्धि होगी। भागदौड़ भी अधिक रहेगी। लाभ के अवसर भी मिलेंगे। किसी पुराने मित्र से काफी समय बाद भेंट हो सकती है। सेहत का ध्यान रखें।

तुला : किसी मित्र के सहयोग से किसी नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है। पिता का साथ भी मिलेगा। मित्र के साथ यात्रा पर भी जा सकते हैं।

वृश्चिक : पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी। शैक्षिक कार्यों में सफल रहेंगे। कारोबार में बदलाव हो सकता है। भागदौड़ अधिक रहेगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

धनु : मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं, परंतु स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। कार्यक्षेत्र में वृद्धि भी हो सकती है।

मकर : कला व संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है। किसी रुके हुए धन की प्राप्ति भी हो सकती है।

कुंभ : किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में वृद्धि हो सकती है। भागदौड़ अधिक रहेगी। माता की सेहत का ध्यान भी रखें। रहन-सहन कष्टमय हो सकता है।

मीन : कारोबार में भागदौड़ अधिक रहेगी। रहन-सहन भी अव्यवस्थित रहेगा। लाभ में वृद्धि होगी। परिवार का साथ मिलेगा। किसी मित्र का आगमन हो सकता है।

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

16 जून, मंगलवार, **शक संवत्** : 26 ज्येष्ठ (सौर) 1948, **पंजाब पंचांग** : 02 आषाढ़ मास प्रविष्टे 2083, **इस्लाम** : 29 जिल्हिजा, 1447, **विक्रमी संवत्** : द्वितीय (शुद्ध) ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया तिथि रात्रि 12.53 मिनट तक पश्चात तृतीया तिथि, आर्द्रा नक्षत्र सायं 04.13 मिनट तक पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र, वृद्धि योग रात्रि 12.35 मिनट तक पश्चात ध्रुव योग, बालव करण। चंद्रमा मिथुन राशि में (दिन-रात)। **सूर्य उत्तरायण।** ग्रीष्म ऋतु। अपराह्न 03 बजे से सायं 04.30 मिनट तक राहुकालम्। द्वितीय (शुद्ध) ज्येष्ठ शुक्ल प्रारंभ। चंद्रदर्शन।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

फिटकरी के कुछ वास्तु उपाय बताएं?

-अलकनंदा जावेरी, रांची

- फिटकरी को रसोई में रखने से अन्न में बरकत होती है। परिवार में स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। टॉयलेट में रखने से वास्तु दोष कम होता है। नकारात्मकता दूर होती है। मुख्य द्वार के पास रखने से घर में सकारात्मकता बनी रहती है और बुरी नजर का प्रभाव भी दूर होता है। पूजा स्थान पर रखने से शुद्धता एवं पवित्रता बनी रहती है। परिवार में भी प्रेम बढ़ता है। बेडरूम में रखने से तनाव कम होता है। नकारात्मक विचार कम आते हैं। नींद भी अच्छी आती है। धन रखने वाली जगह पर रखने से धन की निरंतरता बनी रहती है। धन में स्थिरता आती है।

वर्ग पहेली : 8361

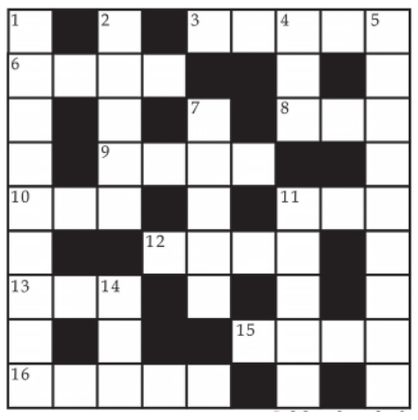

बाएं से दाएं
3. सफेद रंग पर काले, लाल या पीले दागों वाला; चित्तीदार; पुष्पित; रंग-बिरंगा; शबल (5)
6. चमचमाता; चमचमाने वाला (4)
8. अंदाज; ढंग; विधि; रीति; व्यवहार (3)
9. हिंडोले पर पेंग मारना; झूमते इतराते हुए चलना (4)
10. कामिनी; जिह्वा; प्यारा बेटा (3)
11. ढोर बांधने की रस्सी; गिराव; पघा (3)
12. इधर से उधर तक; इस किनारे से उस किनारे तक; एक छोर से दूसरे छोर तक (2,2)
13. टिकना; बसना; रुकना; बचना; छूटना (3)
15. लड़ना; झगड़ा करना (4)
16. ईश्वर में विश्वास न होना; आस्तिक न होना; धर्महीन होना (3,2)

ऊपर से नीचे
1. एक पक्ष को छोड़ कर दूसरे पक्ष में भेजना; दलबदल करने के लिए प्रवृत करना (5,4)
2. स्मरण करना; रटना (2,3)
4. जिसकी कल्पना की गई हो; नकली; फर्जी; मनगढ़ंत; सोचा हुआ (3)
5. जरा-सी बात को बहुत बढ़ाना; बात का बतंगड़ बनाना; मामूली-सी बात को बहुत बढ़ाना (2,1,3,3)
7. गलती करना; भूल करना; अवसर खो देना; चूकना (2,3)
11. पंख आना; बहुत तेज दौड़ना; इतराना; सीधे-सादे व्यक्ति से धूर्तता करना (2,3)
14. केवट; नाव चलाने वाला; मल्लाह; मांझी (3)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली

(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8360

1 म	2 न	ख	3 रा	ब	क	4 र	ना	■	
■	र	■	य	■	■	सी	■	5 घ	
6 प्र	सं	ग	■	7 क	रे	ला	■	र	
■	हा	■	■	ल	■	हो	■	बा	
8 क	र	9 त	ब	■	10 अ	ना	11 द	र	
लं	■	द	■	12 ध	■	■	र	■	
कि	■	13 नु	क्क	ड़	■	14 टि	कि	या	
त	■	रू	■	■	15 बा	■	ना	■	
■	16 अ	प	ह	र	ण	क	र	ना	

सुडोकू : 8343 *मध्यम

	3		2	5			4	
7			1		8			3
				3				
	9						6	4
4		1				5		7
5	8						9	
				1				
2			5		4			8
	5			6	9		7	

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3×3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8342

7	1	6	4	9	8	5	3	2
3	9	8	6	2	5	4	1	7
2	4	5	3	1	7	6	9	8
5	3	9	2	6	1	7	8	4
6	7	4	5	8	9	3	2	1
8	2	1	7	4	3	9	5	6
9	5	2	1	7	4	8	6	3
1	8	7	9	3	6	2	4	5
4	6	3	8	5	2	1	7	9

प्रेरणा

संतुष्टि यानी आपके पास जो कुछ है, उसका मजा उठाएं। - एपिक्यूरस

संपादकीय

देश में इलाज बिना होने वाली मौतें चिंताजनक हैं

सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2020 के बाद देश में औसतन हर दूसरे व्यक्ति की मृत्यु प्रशिक्षित डॉक्टर से इलाज के अभाव में हुई है। 2020 तक लगभग हर छह में केवल एक (18%) को इलाज मयस्सर नहीं था, लेकिन अचानक अगले चार साल में स्थिति असाधारण रूप से बदली और 2024 तक 45.5% मरने वाले वे थे, जिनका मृत्यु के पहले न तो अस्पताल में इलाज हुआ न किसी प्रशिक्षित डॉक्टर की देखरेख में। विश्लेषक ही नहीं सरकार भी इन आंकड़ों से चिंतित है। बदलाव के तीन कारण हो सकते हैं- डॉक्टरों और अस्पताल का पहुंच में न होना, इलाज की बढ़ती कीमत और मौत की स्थिति की सही रिपोर्टिंग। लेकिन आंकड़ों पर भरोसा इसलिए भी है क्योंकि बिहार में वर्ष 2020-24 के दौरान पाया गया कि औसतन हर तीन में दो ऐसे हैं, जिनकी बिना किसी डॉक्टर या अस्पताल (सरकारी या निजी) में इलाज के मृत्यु हुई, जबकि केरल में हर चार में से केवल एक की इलाज-विहीन मौत हुई। बिहार के बाद झारखण्ड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और ओडिशा में इलाजविहीन मौतों का प्रतिशत क्रमशः 61.8, 60.1, 54.2, 52.6, और 52 रहा। इसके उलट केरल के बाद ऐसी मौतों का प्रतिशत जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और एमपी में सबसे कम रहा है।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
humarehanuman@gmail.com

यदि हम अहंकारी हैं तो अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं

अहंकार को लेकर हमारे शास्त्रों में अलग-अलग ढंग से कई बातें बोली गई हैं। अभिमान भक्ति के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है और संसार में भी घमंड आखिर में तकलीफ ही देता है। अब इस बात को एक नए ढंग से तुलसीदास जी प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने अभिमान को क्लेश और शोक से जोड़ दिया : संसृत मूल सूलप्रद नाना, सकल सोक दायक अभिमाना- अभिमान जन्म-मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों का देने वाला है। क्लेश पांच होते हैं- अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये मनुष्य को पीड़ा पहुंचाते हैं। इसीलिए अभिमानी व्यक्ति कभी शांत नहीं पाया जाता। उसका अहंकार उसको भीतर से कम्पित रखता है, बेचैन रखता है, वो बाहर से भले ही शांत रहने का अभिनय करे। इसी तरह शोक मन में उत्पन्न होने वाली पीड़ा की एक मानवीय प्रतिक्रिया होती है। तो तुलसीदास जी का संदेश यह है कि यदि हम अहंकारी हैं तो हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं।

• Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

नया विचार • डिजिटल-पीढ़ी का सामना राजनीति से

2011 और 2026 के भारतीय युवाओं में क्या अंतर आया है?

युवा मन

चेतन भगत
अंग्रेजी के उपन्यासकार
chetan.bhagat@gmail.com

कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी के देखते ही देखते करोड़ों फॉलोअर्स बन गए। लेकिन फॉलोअर्स की विशाल संख्या सोशल मीडिया हैंडलों पर थी। सड़कों पर नहीं। सीजेपी ने जंतर-मंतर पर एक वास्तविक सभा जरूर की और मीडिया ने भी इसे अच्छे से कवर किया। फिर भी वहां कुछ सौ या हजार लोग ही पहुंचे। भारत के मॉल्स में किसी मामूली सेलिब्रिटी के आने पर भी इससे ज्यादा भीड़ जुट जाती है। ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच इतना अंतर क्यों था? क्या जेन-जी आलसी है? या वे उतने असंतुष्ट नहीं हैं और अपेक्षाकृत आरामदायक जीवन जी रहे हैं? लेकिन यह एक सामान्यीकरण होगा। असली वजह इससे कहीं गहरी है। सीजेपी को समझना एक मायने में मौजूदा जेन-जी को समझने का भी एक बेहतरीन तरीका है।

तुलना की जा रही है कि सीजेपी वर्ष 2011 के भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन जैसी नहीं है। यह समानता समझ में आती है। दोनों ने जनता की निराशा को आवाज दी। दोनों ने युवाओं को आकर्षित किया। दोनों पारंपरिक राजनीतिक ढांचे से बाहर उभरे। लेकिन सीजेपी ने वैसा मामूली-सा भी जनसमर्थन पैदा नहीं किया, जैसा 2011 में अन्ना हजारे ने किया था। लेकिन इससे पहले हमें एक बड़े सवाल को समझना होगा : जब स्मार्टफोन के दौर में पली-बढ़ी डिजिटल-फर्स्ट पीढ़ी का सामना राजनीति से होता है, तो क्या होता है? क्योंकि 2011 और 2026 के बीच यही सबसे बड़ा अंतर है।

2011 में देश लगभग वही प्रमुख टीवी चैनलें देखता था। लोग एक जैसी सुर्खियों पर चर्चा करते थे। जंतर-मंतर पर हुआ प्रदर्शन राष्ट्रीय खबर बन जाता था, क्योंकि हर कोई एक ही स्क्रीन पर था। आज देश एल्गोरिदम से बने अलग-अलग डिजिटल दायरों में जीता है। कोई सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाला छात्र पूरा दिन यूपीएससी संबंधी वीडियो देख सकता है। कोई दूसरा स्टार्टअप से जुड़े प्रभावशाली लोगों को फॉलो करता है। तीसरा मेकअप ट्यूटोरियल देखता है। चौथा राजनीतिक मीम्स की दुनिया में रहता है। सभी ऑनलाइन हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि वे सभी एक ही वास्तविकता का अनुभव कर रहे हों। इससे लोगों को एकजुट व संगठित करना कठिन हो जाता है।

2011 के आंदोलन का एक मुद्दा था : भ्रष्टाचार खत्म करो। देश जानता था कि वह किस बात से नाराज है और क्या चाहता है। सीजेपी का मामला इससे अलग है। इसके समर्थक कई तरह की बातें करते हैं- बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाएं, पेपर लीक, जीवन-यापन की बढ़ती लागत, राजनीतिक अहंकार, अवसरों की कमी, युवाओं की निराशा। ये सभी वास्तविक चिंताएं हैं। समस्या यह है कि चिंताएं बहुत अधिक हैं। एक शिकायत के आधार पर देश को संगठित करना दस शिकायतों के आधार पर करने की तुलना में आसान होता है।

फिर दोनों का लहजा भी अलग है। भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन गंभीर था। लगभग आध्यात्मिक। लोग गांधी-टोपी पहनकर रैलियों में जाते थे। उन्होंने उपवास तक किए! वहीं सीजेपी हास्य के माध्यम से उभरी। यह मीम्स, व्यंग्य, विडंबना पर आधारित है। यह पूरी तरह डिजिटल भी है, जिससे यह अविश्वसनीय गति से फैल सकती है। लेकिन इस प्रणाली के साथ एक समस्या है। बहुत से लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। वे इसे पसंद करेंगे और साझा करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि वे आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए आगे आएं। और हर कंटेंट क्रिएटर इस कड़वी सच्चाई को जानता है।

अगर लाखों युवा रोजगार और परीक्षाओं जैसे मुद्दों से जुड़ रहे हैं, तो ऐसा तब नहीं होता जब वे पूरी तरह संतुष्ट हों। निराशा वास्तविक है। सवाल यह है कि उसे व्यक्त

यह किसी कमजोर या आलसी पीढ़ी की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी पीढ़ी की कहानी है, जो राजनीति को अलग तरीके से व्यक्त करती है। जो विरोध के बैनर उठाने से पहले अपने फोन की ओर हाथ बढ़ाती है। पर क्या डिजिटल आक्रोश वास्तविक दुनिया को बदल सकता है?

कैसे किया जा रहा है। पुरानी पीढ़ी अकसर राजनीति को भौतिक कार्रवाई के माध्यम से देखती है- प्रदर्शन, विरोध, धरना, मार्च। लेकिन जेन-जी अलग साधनों के साथ बड़ी हुई है- पोस्ट करना, कमेंट करना, शेयर करना, कंटेंट बनाना। यहीं पर पुरानी और नई पीढ़ी के बीच गलतफहमी पैदा होती है। कोई बुजुर्ग व्यक्ति पूछ सकता है, अगर आप इतने नाराज हैं तो सड़कों पर क्यों नहीं हैं? एक युवा जवाब दे सकता है, अगर लाखों लोगों ने मेरी पोस्ट देख ली है, तो फिर सड़कों पर आने की जरूरत क्या है? 2011 में अगर लोगों को लगता था कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो वे इकट्ठा होते थे। 2026 में अगर लोगों को लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो वे पोस्ट करते हैं। सोशल मीडिया एक तरफ आवाज को बढ़ाने वाला माध्यम बन गया है, तो दूसरी तरफ दबाव निकालने का रास्ता भी। इंटरनेट राजनीतिक ऊर्जा के एक बड़े हिस्से को अपने भीतर समाहित कर लेता है, जो कभी सड़क पर उतरकर आंदोलन का रूप ले सकती थी। **(ये लेखक के अपने विचार हैं)**

विश्लेषण • वहीं यूएस-इजराइल की साख घटी है

युद्ध के तमाम नुकसानों के बावजूद ईरान मजबूत हुआ है

भू-राजनीति

मनोज जोशी
विदेशी मामलों के जानकार
manoj1951@gmail.com

तमाम आकलनों से अब यह स्पष्ट है कि ईरान के खिलाफ युद्ध अमेरिका-इजराइल गठबंधन के लिए एक रणनीतिक विफलता साबित हुआ है। 28 फरवरी को यह युद्ध होर्मुज को फिर से खोलने के उद्देश्य से नहीं शुरू किया गया था; उस समय वह पहले ही खुला हुआ था। न ही इसका उद्देश्य ईरान की परमाणु क्षमता को कम करना था; क्योंकि युद्ध शुरू किए जाने से कुछ दिन पहले कतर की मध्यस्थता में हुई वार्ताओं में ईरान इसके लिए पहले ही सहमत हो चुका था। यह युद्ध ईरान की इस्लामिक हुकूमत को गिराने के मकसद से छेड़ा गया था और इसी के तहत अयातुल्लाह खामेनेई की हत्या की गई थी। जबकि हकीकत यह है कि खामेनेई ने ही ईरान को अभी तक परमाणु हथियार बनाने से रोक रखा था। अब सर्वोच्च नेता के रूप में मोज्तबा खामेनेई के नेतृत्व वाला शासन-युद्ध में भारी नुकसान के बावजूद- पहले से अधिक संगठित और आत्मविश्वास से भरा हुआ है।

इस युद्ध ने ईरान की होर्मुज में यातायात रोकने की क्षमता और दुनिया की दो प्रमुख सैन्य शक्तियों अमेरिका और इजराइल से मुकाबला करने की उसकी क्षमता को उजागर किया। गहरे भूमिगत ठिकानों से दागी गई मिसाइलों और ड्रोन के संयोजन के जरिए ईरान इजराइल पर हमले करने, खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को गंभीर क्षति पहुंचाने और अमेरिका के खाड़ी सहयोगियों को भी नुकसान पहुंचाने में सक्षम रहा।

अब इसे आप चाहे जिस नजरिए से देखें, संभावना यही है कि हमें आर्थिक, राजनीतिक और क्षेत्रीय दृष्टि से एक अधिक मजबूत ईरान देखने को मिलेगा। इस युद्ध ने खाड़ी क्षेत्र में पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा ढांचे की सीमाओं को उजागर कर दिया है। दशकों तक पूरे क्षेत्र में फैले अमेरिकी बेस स्थिरता और प्रतिरोध की गारंटी के रूप में काम करते रहे थे, लेकिन आज उनकी प्रभावशीलता पहले जैसी नहीं दिखती। पहले ही कई खाड़ी सहयोग परिषद देश ईरान के प्रति अपने सुरक्षा संबंधों और रुख का पुनर्मूल्यांकन करने लगे हैं।

भारत के दो-तिहाई आकार वाले ईरान के पास तेल और गैस जैसे पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन हैं, साथ ही शिक्षित मध्यम वर्ग के रूप में मानव संसाधन भी मौजूद है। अब तक ईरान का प्रभाव अमेरिका के साथ उसके टकराव के कारण सीमित रहा है। इसकी शुरुआत 1979 में हुई थी, जब एक राजनीतिक विद्रोह ने अमेरिका के सहयोगी शाह को सत्ता से हटा दिया था। आंतरिक उथल-पुथल और बाहरी प्रतिबंधों के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन ने भी ईरान को एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक दिया।

लेकिन अब बदलाव का अवसर मौजूद है। हालांकि बड़ी बाधाएं अभी भी बनी हुई हैं। सबसे बड़ी बाधा तो इजराइल ही है, जो बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता वाले और हिजबुल्ला-हूती के साथ गठबंधन रखने वाले ईरान को स्वीकार नहीं कर सकता। इजराइल ने यह दावा करते हुए अमेरिका को युद्ध शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया था कि इस्लामिक हुकूमत तेजी से ढह जाएगी, लेकिन इसके बजाय उसने ऐसी घटनाओं की शृंखला शुरू कर दी है, जिसने वास्तव में ईरान की रणनीतिक स्थिति को और मजबूत किया है।

दो चरणों वाली वार्ताओं को देखते हुए इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि परमाणु मुद्दे पर ईरान वास्तव में अमेरिकी शर्तों पर हस्ताक्षर करेगा। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने सभी समृद्ध यूरेनियम भंडार को देश से बाहर भेज दे और अपने सेंट्रीफ्यूज को नष्ट कर दे। ईरान अपने तीन में से दो यूरेनियम संवर्धन स्थलों को बंद करने के लिए तैयार है, लेकिन सभी को बंद करने

इजराइल ने यह दावा करते हुए अमेरिका को युद्ध शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया था कि इस्लामिक हुकूमत तेजी से ढह जाएगी। लेकिन इसके बजाय उसने ऐसी घटनाओं की शृंखला शुरू कर दी है, जिसने वास्तव में ईरान की रणनीतिक स्थिति को और मजबूत किया है।

के लिए नहीं। ईरान का कहना है कि परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) के तहत उसने परमाणु हथियार नहीं बनाने की प्रतिबद्धता जताई है, लेकिन अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए यूरेनियम संवर्धन का उसे अधिकार है।

ट्रम्प का लक्ष्य परमाणु समझौते के हिस्से को उस समझौते से अधिक सख्त बनाना है, जिस पर 2015 में ओबामा प्रशासन के दौरान बातचीत हुई थी और जिसे उन्होंने 2018 में रद्द कर दिया था। लेकिन स्थिति कठिन है। चूंकि इस मुद्दे पर शांति समझौते के दूसरे चरण में ही चर्चा होगी, इसलिए बड़ा सवाल यह है कि अगर चीजें अमेरिका की इच्छा के अनुसार नहीं चलती हैं तो क्या अमेरिका में फिर से ईरान को सैन्य रूप से धमकाने की क्षमता होगी? **(ये लेखक के अपने विचार हैं)**

इस लेख को मोबाइल पर सुनने के लिए **QR कोड** को स्कैन करें।

दैनिक भास्कर अब आप NYT के सभी आर्टिकल DB एप पर हर मंगलवार पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें डीबी एप।

© The New York Times

दैनिक भास्कर से विशेष अनुबंध के तहत

अर्थव्यवस्था अमेरिका में मिलने वाले प्रति घंटा वेतन में पिछले तीन माह से गिरावट जारी, मध्यम वर्ग की आय धीमी गति से बढ़ रही, एआई से भी बढ़ी समस्या

अमेरिका में 20 शीर्ष अमीरों की संपत्ति राष्ट्रीय उत्पादन के 12% तक पहुंची

बेनकैसलमैन

अमेरिकी अर्थव्यवस्था इस समय एक विरोधाभास से गुजर रही है, जहां एक ओर अरबपतियों की संपत्ति नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है, वहीं आम वर्कर्स बढ़ती महंगाई और भविष्य की अनिश्चितताओं से जूझ रहे हैं। पिछले सप्ताह इसकी झलक दो घटनाओं में दिखाई दी। बुधवार को लेबर ब्यूरो ने बताया कि ऊर्जा कीमतों (बिजली, पेट्रोल, गैस, डीजल) में बढ़ोतरी ने औसत अमेरिकी कर्मचारी की पिछले डेढ़ साल की वास्तविक वेतन वृद्धि लगभग खत्म कर दी। वहीं शुक्रवार को स्पेसएक्स के आईपीओ के बाद इलॉन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए।

अर्थशास्त्रियों गैब्रियल जकमैन और इमैनुएल साएज के अनुसार, 19वीं सदी के उत्तरार्ध के तथाकथित 'गिल्डेड एज' में सबसे अमीर अमेरिकियों की संपत्ति देश के वार्षिक आर्थिक उत्पादन के लगभग 3% के बराबर थी। आज अमेरिका के शीर्ष 0.00001% यानी लगभग 20 लोगों की संपत्ति राष्ट्रीय उत्पादन (अमेरिकी कंपनियों द्वारा अमेरिका और अन्य देशों में सालाना किया जाने वाला उत्पादन) के 12% तक पहुंच चुकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी इतिहास में शीर्ष स्तर पर संपत्ति का इतना बड़ा केंद्रीकरण पहले कभी नहीं देखा गया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर स्टीफेनी स्टेंटचेवा के अनुसार, शेयर बाजार में लगातार उछाल ने लोगों में यह भावना पैदा की है कि आर्थिक व्यवस्था कुछ चुनिंदा लोगों के लिए अधिक काम कर रही है। हालांकि आधे से अधिक अमेरिकी परिवार प्रत्यक्ष रूप से या रिटायरमेंट फंड के माध्यम से शेयर बाजार में निवेश रखते हैं और उन्हें भी लाभ मिला है, लेकिन फेडरल रिजर्व के आंकड़े बताते हैं कि पिछले दशक में मध्यम वर्ग की संपत्ति अमीरों की तुलना में कहीं धीमी गति से बढ़ी है। ईरान से जुड़े तनाव और ऊर्जा कीमतों में उछाल के कारण मई में अमेरिका की मुद्रास्फीति तीन वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। महंगाई को समायोजित करने के बाद प्रति घंटे मिलने वाला वास्तविक वेतन लगातार तीन महीनों से घट रहा है। नतीजतन, ट्रम्प के मौजूदा कार्यकाल के शुरुआती दौर में हुई वेतन वृद्धि का बड़ा हिस्सा खत्म हो गया है।

अमेरिकी परिवार पहले ही कोविड-19 महामारी, चार दशक की सबसे ऊंची महंगाई, ऊंची ब्याज दरों, टैरिफ और मंदी की आशंकाओं का सामना कर चुके हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) एक नई चिंता बनकर उभरा है। कई तकनीकी कंपनियों के प्रमुख चेतावनी दे चुके हैं कि एआई आने वाले वर्षों में अनेक श्रेणियों की नौकरियों को प्रभावित कर सकता है। कोलंबिया बिजनेस स्कूल के अर्थशास्त्री ग्लेन हबार्ड का कहना है कि जब तकनीकी कंपनियां स्वयं यह संदेश देती हैं कि उनकी तकनीक लोगों की नौकरियां खत्म कर सकती है, तो उसके खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। इसी वजह से अमेरिका में आर्थिक असमानता, सुपररिच वर्ग के बढ़ते प्रभाव और आम लोगों की आर्थिक सुरक्षा को लेकर बहस पहले से अधिक तेज हो गई है।

© The New York Times

महंगाई बढ़ने के साथ कमाई घटी

- अमेरिका में महामारी के बाद महंगाई चार दशक में सबसे अधिक हो गई ।
- राष्ट्रीय आय में वर्कर्स के हिस्से में लगातार गिरावट।
- अमीरों की तुलना में मध्यम वर्ग की संपत्ति में बढ़ोतरी की गति धीमी।
- लंबे समय तक महंगाई रहने से कंज्यूमर खर्च से बचते हैं।
- प्रति घंटा वेतनों में तीन माह से गिरावट जारी।

एआई कंपनियों के कई बड़े आईपीओ आएंगे

टेक कंपनियों को अभी हाल में शेयर मार्केट की तेजी से फायदा हुआ है। स्पेसएक्स के बाद एआई कंपनियों के बड़े-बड़े आईपीओ की श्रंखला आ सकती है। महंगाई और आय में गिरावट की चिंता के बीच एआई में उछाल के से लोगों का अमीरों की संपत्ति में बढ़ोतरी से असहज होना असामान्य नहीं है।

कम आय वालों को करना पड़ रहा संघर्ष

अर्थशास्त्रियों के अनुसार महंगाई के दौर से कंज्यूमर का आर्थिक व्यवहार लंबे समय तक प्रभावित रहता है। यह उनके बजट पर बोझ के साथ अनुचित भी है क्योंकि अमीर लोग तो महंगाई का सामना अपेक्षाकृत आसानी से कर लेते हैं जबकि कम आय वाले परिवारों को संघर्ष करना पड़ता है।

कई अमेरिकी राज्यों में डेटा सेंटरों का विरोध

सर्वेक्षणों के अनुसार कई वर्कर्स करिअर पर एआई टेक्नोलॉजी के पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चिंतित हैं। अमेरिका के कई राज्यों में वोटर अपने इलाके में डेटा सेंटरों के निर्माण पर विरोध जता चुके हैं। वे अपने बिजली के बिल, पानी सप्लाई और हवा की क्वालिटी पर इसके असर की बात कह रहे हैं।

इस हफ्ते चर्चा में...

स्विस आबादी को सीमित रखने का प्रस्ताव नामंजूर

1 करोड़

तक देश की आबादी सीमित रखने का प्रस्ताव स्विटजरलैंड के वोटरों ने रविवार को एक जनमतसंग्रह में रद्द कर दिया है।

8.21 लाख रुपए

मूल्य है न्यूजर्सी, अमेरिका में 19 जुलाई को होने वाले वर्ल्ड कप फुटबॉल फाइनल मैच के एक टिकट का।

1.13 लाख करोड़ रुपए

जुटाए हैं जेफ बेजोस के एआई स्टार्टअप प्रोमेथ्यूस ने शेयर बाजार से। कुछ और एआई कंपनियों के आईपीओ आ सकते हैं।

टेक्नोलॉजी राष्ट्रपति ट्रम्प ने भी दिए संकेत

एआई से कमाई कर रही कंपनियों पर टैक्स लगाने की मांग बढ़ी

पीटर कॉय

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से पैदा हो रही संपत्ति और उसके लाभों के वितरण को लेकर अमेरिका में नई बहस शुरू हो गई है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यदि एआई बड़ी संख्या में नौकरियां और वेतन आधारित काम अपने हाथ में ले लेता है, तो सरकार के टैक्स राजस्व पर भी असर पड़ेगा। ऐसे में एआई से होने वाले लाभ का कुछ हिस्सा सीधे जनता तक पहुंचाने की मांग जोर पकड़ रही है। राष्ट्रपति ट्रम्प ने हाल ही में संकेत दिया है कि वे प्रमुख टेक कंपनियों के अधिकारियों से इस मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं। वहीं निर्दलीय सीनेटर बर्नी सैंडर्स ऐसी योजना लाने की तैयारी में हैं, जिसके तहत बड़ी एआई कंपनियों पर एकमुश्त टैक्स लगाकर उनके कुछ शेयर सार्वजनिक स्वामित्व वाले फंड में रखे जा सकें। दिलचस्प बात यह है कि ओपनएआई ने भी एआई कंपनियों में सीमित सार्वजनिक स्वामित्व के विचार का समर्थन किया है। हालांकि इस प्रस्ताव का विरोध भी हो रहा है। डेमोक्रेट सांसद ग्रेग कैसर का तर्क है कि एआई कंपनियों पर अतिरिक्त टैक्स नवाचार और रोजगार सृजन को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी ओर सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने डेटा सेंटरों की बिजली खपत पर विशेष लेवी लगाने का सुझाव दिया है। कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि भविष्य में एआई स्वयं निवेश निर्णय लेने लगेंगे। उनके अनुसार, यदि एआई आधारित पूंजी का विस्तार मानव श्रम से तेज होता है, तो भविष्य में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और पूंजी पर कर लगाना अधिक उपयुक्त विकल्प बन सकता है।

फाइनल प्रोडक्ट पर टैक्स

अर्थशास्त्री वर्जीनिया लॉकवुड कहती हैं, एआई कंपनी की प्रोडक्शन प्रक्रिया की बजाय फाइनल प्रोडक्ट पर टैक्स लगाना चाहिए। अगर कोई प्रेमपत्र लिखने के लिए चैटजीपीटी का इस्तेमाल करता है तो उस पर टैक्स लगे न कि विज्ञापन बनाने पर।

© The New York Times

कानून

मीडिया को निशाना बना रहे हैं एफबीआई चीफ

एरिक तेम्पले

अमेरिका की प्रमुख अपराध जांच एजेंसी एफबीआई के चीफ काश पटेल ने मीडिया के खिलाफ कड़ा रुख अपना रखा है। वे पिछले सात वर्षों में मीडिया संस्थानों और पत्रकारों के खिलाफ मानहानि के करीब छह मुकदमे दायर कर चुके हैं।

2019 में व्हाइट हाउस में सहायक रहे पटेल ने यूक्रेन के मामले में राष्ट्रपति ट्रम्प की भूमिका को लेकर प्रकाशित खबरों पर पॉलिटिको, न्यूयॉर्क टाइम्स और सीएनएन जैसे प्रमुख मीडिया संस्थानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की थी। 2023 में ट्रम्प समर्थकों पर टिप्पणी करने वाले ब्लॉगर जिम स्टीवर्टसन के खिलाफ भी उन्होंने एक करोड़ डॉलर का मानहानि दावा दायर किया था। इस साल अप्रैल में द अटलांटिक में प्रकाशित एक रिपोर्ट के बाद पटेल ने पत्रिका पर 2.5 अरब डॉलर की क्षतिपूर्ति का मुकदमा दायर कर दिया। जॉर्जिया यूनिवर्सिटी की विशेषज्ञ सोनजा वेस्ट के अनुसार, ऐसी कानूनी कार्रवाई का उद्देश्य केवल मुकदमा जीतना नहीं, बल्कि पत्रकारों को यह संदेश देना भी हो सकता है कि आलोचनात्मक रिपोर्टिंग की कीमत चुकानी पड़ सकती है।

© The New York Times

इमेज अमेरिका में रायटर-इप्सोस के सर्वे में खुलासा

10 में से 6 लोग मानते हैं कि ट्रम्प पर बढ़ती उम्र का असर दिखने लगा है

केटी रोजर्स

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प रविवार को 80 साल के हो गए। वे लगातार खुद को ऊर्जावान और सक्रिय नेता के रूप में पेश करने में लगे रहते हैं। वे देर तक जागते हैं, वकीलों और सांसदों को फोन करते हैं, साथ ही ट्रुथ सोशल साइट पर रात में 150 बार पोस्ट करते हैं। वे रविवार की सुबह दुनियाभर के नेताओं से मिडिल ईस्ट युद्ध पर बात करते रहे। फिर ओवल ऑफिस में आकर बैठे। हालांकि उनकी बढ़ती उम्र को लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। फरवरी में रायटर-इप्सोस के एक सर्वे में दस में से लगभग छह अमेरिकी सोचते हैं कि ट्रम्प अधिक अस्थिर होते जा रहे हैं।

ट्रम्प को कई बार सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान झपकी लेते पाया गया है। पिछले सोमवार के मेडिसन स्क्वेयर गार्डन में न्यूयॉर्क निक्स के एक मैच के बीच वे झपकी ले रहे थे। ऐसे ही 4 जून को ओवल ऑफिस में एक घंटे लंबी बैठक के बीच ट्रम्प अपनी कुर्सी पर कुछ सेकंड तक आंख बंद करके झुके रहे। इस माह

की शुरुआत में जब ट्रम्प ने एक सप्ताह तक किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया तब कुछ पर्यवेक्षकों ने अनुमान लगाया कि वे बीमार हैं। वे इससे पहले वाल्टर रीड नेशनल मिलिटरी मेडिकल सेंटर में शारीरिक परीक्षण कराकर आए थे। जांच के तीन दिन बाद डॉ. सीन बारबबेला ने कहा कि 79 वर्षीय ट्रम्प की सेहत अच्छी है। उनके कार्डियक, पल्मोनरी और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम अच्छे से काम कर रहे हैं।© The New York Times

बिज़नेस भास्कर

Business Standard और TheEconomist की ख़बरों के साथ

नई दिल्ली, मंगलवार 16 जून, 2026

भास्कर एनालिसिस ईरान डीलः कंपनियां कमाई का नया दौर देखेंगी, 7% से बढ़कर 15% तक पहुंचेगी ग्रोथ

सेंसेक्स में 1%, स्मॉलकैप इंडेक्स में 3% उछाल

भास्कर न्यूज | मुंबई

क्रूड ऑयल के घटते दाम, पश्चिम एशिया (ईरान) में युद्ध खत्म होने की उम्मीद और मजबूत कॉरपोरेट नतीजे अब शेयर बाजार को सहारा दे रहे हैं। अगले दो साल में देश की टॉप-50 कंपनियों की आय वृद्धि 6.6% से बढ़कर 15% तक पहुंचने की उम्मीद है। विश्लेषकों का मानना है कि इससे आगामी महीनों में बाजार में तेजी का नया दौर आ सकता है। जिसकी शुरुआत संभवतः सोमवार को हो गई।

सेंसेक्स 1.6% और निफ्टी 1.5% बढ़त पर बंद हुए। लेकिन बीएसई का स्मॉलकैप इंडेक्स 2.8% चढ़ गया, जो सेंसेक्स से तीन गुना है। बीएसई के 24 में से 21 सेक्टोरल इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। यह महज एक दिन की तेजी नहीं है। पृष्ठभूमि में बड़े बदलाव हो रहे हैं। कच्चा तेल 113 डॉलर प्रति बैरल से गिरकर 80 डॉलर से नीचे आ गया है। 19 जून को स्विट्जरलैंड में अमेरिका-ईरान डील पर दस्तखत होने की उम्मीद है। इससे पहले रुपया दो दिन में 1.3% मजबूत हो गया है।

66% शेयरों में तेजी, 162 एक साल की ऊंचाई पर

ट्रेडिंग	तेजी	गिरावट	स्थिर	52 हफ्तों का हाई	52 हफ्तों का लो
4,615	3,030	1,384	201	162	63

स्रोतः बीएसई

सेंसेक्स के सिर्फ 30 शेयरों से इतर बाजार में तेज रैली

इंडेक्स	तेजी
सेंसेक्स, निफ्टी	0.98%
बीएसई लार्जकैप	2.08%
बीएसई मिडकैप	2.39%
बीएसई स्मॉलकैप	2.82%

उछाल वाले टॉप-10 सेक्टर

रियल्टी	3.93%
ऑटो	2.69%
कंज्यू. डिस्क्रिशनरी	2.44%
कंज्यूमर ड्यूरेबल्स	2.02%
इंडस्ट्रियल्स	1.73%
सर्विसेज	1.66%
ऑयल-गैस	1.53%
एनर्जी	1.36%
फाइनेंशियल सर्वि.	1.24%
आईटी	1.07%

बीएसई के 24 में से 21 सेक्टोरल इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए

अगले दो साल में इन सेक्टरों के शेयरों में उछाल के आसार

बैंकिंग-एनबीएफसीः रिजर्व बैंक का सपोर्ट, वाजिब वैल्युएशन। **ऑटोमोबाइलः** कच्चे तेल के दाम घटने से इनपुट लागत कम। **फार्मा-केमिकल्सः** आगामी महीनों में मार्जिन बढ़ने की उम्मीद। **कैपिटल गुड्स-डिफेंसः** मजबूत ऑर्डर बुक, सरकारी खर्च। **कंज्यूमर डिस्क्रिशनरीः** मांग में साइक्लिकल रिकवरी के आसार। **टेलीकॉम-रिन्युएबल एनर्जीः** सरकार का नीतिगत सपोर्ट जारी।

• विशेषज्ञों का मानना है कि रियल एस्टेट, मेटल्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर बाजार के आम रुझान से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।

मुनाफा काटें या अभी टिके रहें... ऐतिहासिक डेटा कह रहे- धैर्य रखें

• साल 2000 से 2025 के बीच हर साल शुरू होने वाला 10 वर्षों की अलग-अलग अवधि में 'बाय-एंड-होल्ड' यानी शेयर खरीदकर बने रहने की रणनीति ने प्रॉफिट बुकिंग को लगभग हर बार पछाड़ा है।

• निफ्टी-50 टीआरआई (टोटल रिटर्न इंडेक्स) में 10 साल टिकने पर सालाना औसतन 6.7% से 20% रिटर्न मिला है।

• साल 2001-2010 के बीच 'बाय-एंड-होल्ड' रणनीति ने 19% रिटर्न दिया, जबकि 20% प्रॉफिट बुकिंग रणनीति से 5% ही रिटर्न मिला।

स्रोतः फंड्सइंडिया

अगले दो साल में इन सेक्टरों के शेयरों में उछाल के आसार

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के मुताबिक, निफ्टी-50 कंपनियों की शुद्ध आय 2.2% अनुमान की जगह 6.6% बढ़ी। सभी कंपनियों में ये ग्रोथ 14% रही (अनुमान 7.3%)। एसबीआई सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल का अनुमान है कि 2026 से 28 के बीच टॉप-50 कंपनियां 15% ग्रोथ देखेंगी।

युद्ध से भारत ज्यादा नुकसान में, फायदा भी इसी को होगा

भास्कर एक्सपर्ट

विनोद नायर
रिसर्च हेड, जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स

पश्चिम एशिया संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित बाजारों में भारत शामिल है। इस लिहाज से कच्चे तेल की कीमतें घटने और होर्मुज जल मार्ग पूरी तरह खुलने पर सबसे ज्यादा फायदा भी भारत को ही होगा। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर को विदेशी निवेशकों की बिकवाली घटने और रिजर्व बैंक के सपोर्ट से राहत मिलेगी। ऑटो, केमिकल, फार्मा और एफएमसीजी सेक्टर को इनपुट लागत घटने से फायदा होगा। निवेशक पोर्टफोलियो का दो-तिहाई से तीन-चौथाई हिस्सा इक्विटी में रख सकते हैं।

मुनाफा • टाइमपीस से 35% ज्यादा उसमें मौजूद सोने का दाम

अब गोल्ड के लिए पिघलाई जा रहीं 'टाइमलेस' घड़ियां

भास्कर न्यूज | मुंबई

ओमेगा, टैग ह्यूअर जैसी मशहूर लग्जरी घड़ियां अब कलेक्टर्स के शोकेस से निकलकर सीधे भट्टी में में जा रही हैं। इसकी वजह दिलचस्प है, इनमें से ज्यादातर में मौजूद सोने की कीमत बाजार में घड़ी के दाम से 35% तक ज्यादा हो गई है।

सोने की कीमतें इस साल जनवरी में रिकॉर्ड 5,600 डॉलर प्रति औंस (घरेलू बाजार में ₹1.75 लाख/10 ग्राम) तक पहुंच गई थी। सोने की कीमत अब भी 2024 के औसत से करीब दोगुनी है। इस उछाल ने सेकंड-हैंड लग्जरी वॉच मार्केट का गणित पलट दिया है। ब्रिटिश डीलर जॉन व्हाइट ने इस साल दर्जनों मेनस्ट्रीम लग्जरी घड़ियां गलाई हैं। मई में उन्होंने 1970 के दशक की एक बेहतरीन ओमेगा कॉन्स्टेलेशन पिघलाई, जिसका सोना 5,750 पाउंड (₹7.3 लाख) में बिका। नीलामी में वह घड़ी ज्यादा से ज्यादा 4,500 पाउंड (₹5.7 लाख) में बिकती।

घड़ी पिघलाई जाएगी या बचेगी, इन चार फैक्टर्स से तय होगा...

- लग्जरी घड़ी में सोने की मात्रा- कुछ मॉडल्स में 200 ग्राम तक
- कलेक्टर मार्केट में डिमांड
- सर्विस और रिपेयर की लागत
- ब्रांड का एक्सक्लूसिविटी फैक्टर
- ऐतिहासिक, सांस्कृतिक अहमियत

लोकप्रियता कम, सोना ज्यादा... ऐसी विंटेज घड़ियों का अस्तित्व खतरे में

विशेषज्ञों के मुताबिक, ज्यादा खतरा उन विंटेज घड़ियों को है जो न तो दुर्लभ हैं, और ही न कलेक्टर्स के बीच लोकप्रिय हैं। लेकिन उनमें काफी सोना है। पैटेक फिलिप और रोलेक्स जैसे ब्रांड्स अब भी सुरक्षित हैं क्योंकि उनकी वेटिंग लिस्ट 2 से लेकर 8 साल तक है। मसलन...

1. **ओमेगा कॉन्स्टेलेशन** • केस व स्ट्रैप में सोना, रिसेल वैल्यू कम 2. **टैग ह्यूअर** • मेनस्ट्रीम अपील, कलेक्टर प्रीमियम नहीं 3. **ब्रेटलिंग** • सेकंड-हैंड बाजार में ज्यादा प्रतिस्पर्धा 4. **ओमेगा स्पीडमास्टर** • बिकते ही तेजी से दाम कम होते हैं।

...लेकिन इन चुनिंदा ब्रांड्स की पुरानी घड़ियों का भविष्य अब भी सुरक्षित

ब्रांड	सुरक्षित इसलिए
रोलेक्स	61% बाजार हिस्सेदारी, 2-8 साल वेटिंग लिस्ट
पैटेक फिलिप	सीमित उत्पादन, मजबूत कलेक्टर बाजार
ऑडेमर्स पिगुए	रेयर मॉडल्स, ऊंचा कलेक्टर प्रीमियम

सोने ने ऐसे बिगाड़ा विंटेज लग्जरी घड़ियों के बाजार का गणित

पिछला उछालः 2024 से 2026 के बीच सोने की कीमत 167% बढ़ चुकी है। इससे लग्जरी घड़ी के री-सेल दाम से ज्यादा उसमें मौजूदा सोने की कीमत हो गई है।

मौजूदा भावः सोना अब भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में 4,200 डॉलर/औंस और घरेलू बाजार में ₹1.50/10 ग्राम है। यह 2024 में औसत भाव से करीब दोगुना है।

डिमांडः वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल जनवरी-मार्च में दुनियाभर में गोल्ड रीसाइक्लिंग 5% बढ़ी और गहनों की मांग 31% उछली है।

निवेश • सेबी ने ईटीएफ ट्रेडिंग का ढांचा बदला

ईटीएफः अब एनएवी नहीं, बाजार ही तय करेगा प्राइस

भास्कर न्यूज | मुंबई

बाजार नियामक सेबी ने ईटीएफ ट्रेडिंग का पूरा ढांचा बदल दिया है। दो दिन पुरानी एनएवी (नेट एसेट वैल्यू) की जगह अब पिछले दिन का बाजार भाव आधार बनेगा और प्राइस बैंड भी बाजार में उतार-चढ़ाव के हिसाब से बदलेगा।

सेबी ने सोमवार को जारी सर्कुलर में कहा कि नए नियमों के तहत बेस प्राइस के लिए पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस लिया जाएगा, जो अंतिम 30 मिनट के वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस से तय होगा। अगर आखिरी 30 मिनट में ट्रेडिंग न हुई हो तो 'लास्ट ट्रेडेड प्राइस' और उसके भी न होने पर ताजा एनएवी आधार बनेगा। यह नियम 1 सितंबर से लागू होंगे। 1 अप्रैल 2027 से टी-1 क्लोजिंग और एनएवी को आधार कीमत बनाने की दिशा में काम होगा।

मौजूदा व्यवस्था में ये दो समस्याएं...

1. कीमत का आधार पुरानाः यदि आप सोमवार है तो ईटीएफ की प्राइस बैंड गुरुवार की एनएवी से तय होती है। यानी दो कारोबारी दिन पुरानी कीमत से। इस बीच अगर सोने या शेयरों में बड़ा उतार-चढ़ाव आ गया, तो ईटीएफ की ट्रेडिंग कीमत और उसकी असली वैल्यू में फर्क आ जाता है।

2. सबके लिए एक ही नियमः गोल्ड ईटीएफ हो या सॉवरेन बॉन्ड (डेट) ईटीएफ, दोनों पर एक जैसी 20% प्राइस बैंड है। जबकि सोने की कीमत एक दिन में 5-6% कम-ज्यादा हो सकती है। बॉन्ड की कीमत 0.5% भी नहीं घटती-बढ़ती। यानी नियम न सोने के लिए सही है और न ही बॉन्ड के लिए।

अब प्राइस बैंड के मामले में ये नियम लागू होंगे...

ईटीएफ कैटेगरी	शुरुआती	अधिकतम
इक्विटी, डेट ईटीएफ	10%	20%
गोल्ड, सिल्वर ईटीएफ	6%	लचीला
लिक्विड ईटीएफ	5%	5%

नोटः ये नियम 1 सितंबर से लागू होंगे, अभी एकसमान 20%

गोल्ड-सिल्वर ईटीएफ में शेयरों जैसी प्राइस डिस्कवरी

• **गोल्ड-सिल्वर ईटीएफः** प्री-ओपन कॉल ऑक्शन लागू। इसका मतलब है कि शेयरों जैसी प्राइस डिस्कवरी होगी।

• **एक्सचेंज को छूटः** घरेलू बाजार बंद होने के बाद वैश्विक बाजार में दाम तेजी से बदलें तो सीमा घटाई-बढ़ाई जा सकेगी।

एआई आउटसोर्सिंग में सबसे आगे निकला भारत

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

ग्लोबल एआई आउटसोर्सिंग रेडीनेस इंडेक्स 2026 में भारत 84.55 अंक के साथ 25 देशों में पहले स्थान पर पहुंच गया है। इस मामले में दूसरे नंबर पर ब्राजील भारत से 8 अंक पीछे है। यह इंडेक्स एक रिपोर्ट कार्ड है, जो बताता है कि किस देश की कंपनियां और कर्मचारी एआई से जुड़े काम संभालने के लिए कितना तैयार हैं।

अटारैक्सिस द्वारा जारी इंडेक्स में भारत की सबसे बड़ी ताकत वर्कफोर्स है। वर्कफोर्स रेडीनेस में भारत को 89 अंक मिले। ब्राजील और फिलीपींस भारत से 13 अंक पीछे हैं। एंटरप्राइज प्रिपेयर्डनेस में भारत का स्कोर 88 रहा, जबकि ब्राजील और मलेशिया, दोनों 77 पर हैं। दक्षिण एशिया में भारत का पूरा दबदबा है। भारत के 84.55 के मुकाबले पाकिस्तान 40.6, नेपाल 34.3 और बांग्लादेश 32.8 पर हैं। अटारैक्सिस के मुताबिक, भारत की यह बढ़त सिर्फ मौजूदा ताकत नहीं, बल्कि भविष्य की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयारी भी दर्शाती है।

तीन पैरामीटर पर भारत की रैंकिंग पहली

पैरामीटर	स्कोर	रैंक
वर्कफोर्स रेडीनेस	89	पहला
उद्योगों की तैयारी	88	पहला
जुकेशन, फ्यूचर स्किल्स	83	दूसरा
कंपोजिट स्कोर	84.55	पहला

स्रोत अटारैक्सिस

एक मामले में हम अनूठे • भारत एकमात्र देश है जिसने वर्कफोर्स रेडीनेस और एंटरप्राइज प्रिपेयर्डनेस, दोनों मामलों में 85 से ऊपर स्कोर किया। यही नहीं, इंडेक्स के 4 में से 3 पैरामीटर में भारत या तो पहले या दूसरे स्थान पर रहा। एजुकेशन और फ्यूचर स्किल्स कैटेगरी में भारत 83 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहा।

नीति आयोग ने जारी किए आंकड़े

तीन साल में सिर्फ 3 फीसदी ही पुराने वाहन स्क्रैप में गए

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

देश में पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में बदलने की रफ्तार सुस्त है। नीति आयोग के मुताबिक, अगस्त 2022 से जुलाई 2025 के बीच 3% से भी कम वाहन अधिकृत माध्यमों से स्क्रैप किए गए। देश की सड़कों पर करीब 1.2 करोड़ एंड-ऑफ-लाइफ वाहनों (ईएलवी) हैं। लेकिन तीन साल में रजिस्टर्ड सेंटर्स के जरिए महज 3.5 लाख गाड़ियां स्क्रैप की गईं। कमजोर वित्तीय लाभ और जागरूकता की कमी इसके सबसे बड़े कारण हैं। वाहन मालिकों को स्थानीय स्क्रैप डीलरों से बेहतर कीमतें मिल जाती हैं। इसके अलावा बड़े शहरों तक सीमित इन्फ्रास्ट्रक्चर, सरकारी विभागों के बीच तालतेल की कमी और स्क्रैप पर 18% जीएसटी का बोझ बड़ी रुकावटें हैं। मंत्रालयों के डिजिटल सिस्टम आपस में नहीं जुड़े होने से गाड़ियों को ट्रैक करना मुश्किल होता है। सरकारी 'वीस्क्रैप' पोर्टल भी अभी शुरुआती चरण में है।

...ये दुर्लभ • मासेराती रेस कार 27 करोड़ रुपए में नीलाम हो सकती है, दुनिया में इसके केवल 52 मॉडल उपलब्ध

कार्मेल | कैलिफोर्निया में अगस्त में 1954 मॉडल की दुर्लभ 'मासेराती ए6जीसीएस' रेस कार नीलाम होगी। नीलामी में कार की अनुमानित कीमत 24-29 लाख डॉलर यानी ₹23-27 करोड़ आंकी गई है। ट्यूबलर-स्टील चेसिस और एल्युमीनियम बॉडी वाली यह ओपन 2-सीटर कार अपने दौर की सबसे खूबसूरत 'फैक्टरी रेस कार' थी। इसमें 2.0-लीटर इंजन और फोर-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स है। मासेराती ने ऐसे केवल 52 मॉडल बनाए थे।

इस कार को मिल चुकी मशहूर 'ग्रैन टूरिस्मो ट्रॉफी'

फैक्टरी रेस कार का मतलब कंपनी की अपनी आधिकारिक और असली रेसिंग कार से होता है। इसे कंपनी खुद अपनी वर्कशॉप में विशेष रूप से तैयार करती है। मशहूर ड्राइवर लुइगी मुसो ने इसी कार से इटली और आयरलैंड में कई ऐतिहासिक रेस जीती थी। 2014 में इसे प्रतिष्ठित 'ग्रैन टूरिस्मो ट्रॉफी' का खिताब भी मिल चुका है।

बिजनेस ब्रीफ

थोक महंगाई बढ़कर 9.7%, ईंधन की 30%

नई दिल्ली | मई में थोक बाजार में कीमतों के हिसाब से महंगाई दर बढ़कर 9.68% हो गई, जो अप्रैल में 8.3% थी। पश्चिम एशिया संकट के कारण ईंधन की महंगाई दर 30.33% पहुंच गई, जबकि खाने की चीजें 4.49% महंगी हुईं। क्रूड पेट्रोलियम और खनिज तेलों की कीमतों में तेज बढ़ोतरी इसकी मुख्य वजह रही।

वेदांताः डीमर्जर से ₹49 हजार करोड़ बढ़ी वैल्यू

मुंबई | वेदांता के डीमर्जर के बाद बनी 5 कंपनियों का कुल मार्केट कैप ₹3.52 लाख करोड़ हो गया, जो पहले 3.03 लाख करोड़ था। इससे करीब ₹49,000 करोड़ का अतिरिक्त मूल्य सृजन हुआ। वेदांता एल्युमिनियम मेटल सबसे बड़ी कंपनी बनी (₹1.94 लाख करोड़ कैप)। वेदांता के शेयरधारकों को हरेक शेयर के बदले नई कंपनियों के शेयर मिले।

रेजरपे ने आईपीओ के लिए गोपनीय आवेदन किया

मुंबई | फिनटेक कंपनी रेजरपे ने सेबी के पास गोपनीय ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस फाइल करके आईपीओ की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बाजार का अनुमान है कि आईपीओ के जरिए कंपनी ₹5-6 हजार करोड़ जुटाएगी। कंपनी का वैल्युएशन ₹50-60 हजार करोड़ तक हो सकता है। रेजरपे ने पहले ही पैरेंट कंपनी को अमेरिका से भारत शिफ्ट कर लिया है।

मई में निर्यात 18 फीसदी बढ़कर 45.2 अरब डॉलर

नई दिल्ली | मई में भारत का माल निर्यात 18% बढ़कर 45.2 अरब डॉलर हो गया। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, बीते माह आयात 20.6% बढ़कर 73.41 अरब डॉलर रहा। इससे व्यापार घाटा 28.21 अरब डॉलर हो गया। अप्रैल-मई में निर्यात 16% बढ़कर 88.9 अरब डॉलर हो गया। पश्चिम एशिया को निर्यात घटकर 5.3 अरब डॉलर का रहा।

बिटकॉइन दो हफ्तों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा

मुंबई | सबसे लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत सोमवार को लगभग 3% बढ़कर 65,400 डॉलर (₹61.8 लाख) हो गई। एथर में 3.7% की तेजी आई। इससे पहले उतार-चढ़ाव के बीच बिटकॉइन 60,000 डॉलर से नीचे आ गया था। विशेषज्ञों का कहना है कि क्रिप्टो मार्केट में मजबूती दिख रही है, हालांकि अनिश्चितताएं बनी हुई हैं।

सर्वम यूनिकॉर्न, HCL ने लगाए 1,427 करोड़ रुपए

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

देश की फुल-स्टैक सॉवरेन एआई कंपनी सर्वम ने सिरीज-बी फंडिंग के पहले चरण में ₹2,210 करोड़ जुटाए हैं। इस राउंड से कंपनी का वैल्युएशन 1.5 बिलियन डॉलर (₹14,168 करोड़) हो गया है। जिससे यह यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो गई। एचसीएल टेक लीड स्ट्रैटेजिक निवेशक के रूप में शामिल हुई। यह आईटी कंपनी सर्वम में 10.46% हिस्सेदारी के लिए ₹1,427 करोड़ निवेश करेगी। बेसेमर वेंचर पार्टनर्स के साथ खोसला वेंचर्स और पीक XV पार्टनर्स ने भी सर्वम में पैसा लगाया।

एआई के आर्थिक फायदे के लिए इंसानी दिमाग बेहद जरूरीः नडेला

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला के मुताबिक बिना इंसानी दिशा-निर्देश के कंप्यूटर सिर्फ गोल-गोल घूमता रहेगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर चेतावनी दी कि एआई की तकनीकी होड़ पूरी हो चुकी है। अब वैश्विक बहस मॉडल के प्रदर्शन से हटकर सीधे श्रम बाजार और इसके आर्थिक फायदों पर केंद्रित हो गई है।

ओपनएआई और एंथ्रोपिक के नीतिगत दस्तावेज भी यही सवाल उठा रहे हैं कि एआई के पूरी तरह सक्षम होने के बाद दुनिया में क्या बदलाव आएगा। नडेला के अनुसार भविष्य में एआई इंटरनेट की तरह हर जगह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होगा। ऐसे में कंपनियों के बीच असली अंतर खुद मॉडल से नहीं, बल्कि उसके ऊपर तैयार अनूठे इंसानी ज्ञान से तय होगा। माइक्रोसॉफ्ट और ओपनएआई का मानना है कि एआई कर्मचारियों को हटाएगा नहीं, बल्कि उनकी क्षमता बढ़ाएगा। सभी कंपनियां सहमत हैं कि मुनाफे का समान वितरण जरूरी है।

टेस्लाः यूरोप में पेश किए सुरक्षा के गलत आंकड़े

एजेंसी | एम्सटर्डम

टेस्ला ने यूरोप में फुल सेल्फ-ड्राइविंग टेक की मंजूरी के लिए नीदरलैंड्स और स्वीडन के नियामकों के समक्ष गलत सुरक्षा आंकड़े पेश किए हैं। टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क और शीर्ष अधिकारियों ने दावा किया कि ऑटोपायलट असिस्टेंस फीचर इंसानों से 10 गुना सुरक्षित है। कंपनी ने प्रेजेंटेशन में कहा कि एफएसडी गाड़ियां क्रैश होने से पहले इंसानों से सात गुना अधिक दूरी तय करती हैं। जिससे 32,000 जानें बच सकती हैं। स्वतंत्र रिसर्चर्स ने इसे भ्रामक मार्केटिंग बताया है।

तेज ग्रोथ • कारों की थोक बिक्री रिकॉर्ड 4.4 लाख, 27% बढ़ोतरी

मई में दोपहिया से दोगुनी रफ्तार से बिकीं कारें

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

मई में कारें दोपहिया से लगभग दोगुनी रफ्तार से बिकी हैं। दोपहिया की 14.8% ग्रोथ के मुकाबले कारों की बिक्री 27.3% बढ़ी। इसी के साथ कंपनियों की तरफ से ऑटो डीलरशिप पर भेजी गई कारों की संख्या बढ़कर 4,38,854 यूनिट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई, जो पिछले साल मई में 3,44,656 थी। ऑटो उद्योग के संगठन सिआम के आंकड़ों के मुताबिक दोपहिया की कुल बिक्री 19,02,209 यूनिट रही, जो पिछले साल मई में 16,57,116 यूनिट थी।

अब यूटिलिटी व्हीकल बनीं सबसे बड़ी वॉल्यूम ड्राइवर

यूटिलिटी व्हीकल (यूवी) सबसे बड़ी वॉल्यूम ड्राइवर बन गई है। इस सेगमेंट में सालाना 24.8% ग्रोथ दर्ज की गई। पिछले साल मई में जहां 1.97 लाख यूवी बिके थे, वहीं इस साल मई में 2.45 लाख बिके।

मोटरसाइकिलों की बिक्री 7%, स्कूटर की 27% बढ़ी

बीते माह मोटरसाइकिल की बिक्री 7.2% बढ़कर 11.14 लाख हो गई। लेकिन स्कूटरों की बिक्री 27.4% बढ़कर 7.39 लाख हो गई। पिछले साल मई में घरेलू बाजार में 5.80 लाख स्कूटर बिके थे।

सिआम के डायरेक्टर जनरल राजेश मेनन के मुताबिक पिछले साल मई में कम वाहन बिके थे, इससे भी इस बार मजबूत ग्रोथ देखने को मिली है। घरेलू बाजार में सभी श्रेणियों के वाहनों की कुल थोक बिक्री मई में 16.8% बढ़कर 23,52,693 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई, जबकि पिछले साल मई में यह आंकड़ा 20,14,158 यूनिट था।

बिजनेस एंकर टैक्स-फ्री माहौल, इन्वेस्टर-गोल्डन वीसा, 100% विदेशी मालिकाना हक बड़े आकर्षण

दुबई में प्रॉपर्टी पर 15% तक डिस्काउंट, मौका भुना रहे रईस

प्राची पिसाल | मुंबई

पश्चिम एशिया में युद्ध के बीच दुबई का रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मार्केट दिलचस्प तस्वीर पेश कर रहा है। वहां के आम निवेशकों ने इस बाजार में जो जगह खाली की है, उसे भरने के लिए एशिया और यूरोप के रईस (जैसे प्रवासी भारतीय या एनआरआई) आगे आ रहे हैं। वजह साफ है, चुनिंदा प्रॉपर्टी पर 12-15% छूट मिल रही है। साथ ही बाजार में ऐसी डील्स मिल रही हैं, जो एक साल पहले संभव नहीं थी। निसस फाइनेंस के सीएमडी अमित गोयनका के मुताबिक, फौरन डील चाहने वाले विक्रेताओं की वजह से बाजार में नए विकल्प खुले हैं।

जनवरी-मार्च में 4.6 लाख करोड़ के घर बिके

दुबई में 2026 की पहली तिमाही में 47,996 डील्स के जरिए 176.7 अरब दिरहम यानी करीब 4.6 लाख करोड़ रुपए के मकानों की बिक्री हो गई। यह सालाना आधार पर वैल्यू में 23.4% और वॉल्यूम (संख्या) में 5.5% की बढ़त है। अमित गोयनका के मुताबिक, संकटग्रस्त विक्रेताओं की वजह से फिलहाल बाजार में एंट्री के ऐसे विकल्प खुले हैं, जो एक साल पहले उपलब्ध नहीं थे।

एनारॉक चैनल पार्टनर्स के सीईओ आयुष पुरी का कहना है कि सामान्य निवेशकों की तादाद जरूर घटी है, लेकिन बड़े खिलाड़ी तैयार और अंडर-कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स दोनों में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तनाव के चरम पर दुबई का डीएफएम रियल एस्टेट इंडेक्स सिर्फ पांच दिन में 20% टूट गया था, लेकिन लंबी अवधि के निवेशक इसे संकट नहीं, एंट्री पॉइंट मान रहे हैं।

दुबई की असली ताकत उसकी नीतिगत बनावट में है। टैक्स-फ्री माहौल, इन्वेस्टर वीसा, गोल्डन वीसा और 100% विदेशी मालिकाना हक- ये चार खूबियां इसे वैश्विक निवेशकों के लिए स्थायी आकर्षण बनाए रखते हैं। नाइट फ्रैंक इंडिया के सीनियर ईडी गुलाम जिया के मुताबिक, वैश्विक निवेशक मौजूदा प्राइस करेक्शन को एंट्री का मौका मान रहे हैं। खासतौर पर भारतीय एनआरआई के लिए दुबई का टैक्स-फ्री ढांचा और 5-9% नेट रेंटल इनकम बड़ा आकर्षण है। कीमतों की बात करें तो इस साल मार्च में 'वैल्यूस्ट्रैट होम प्राइस इंडेक्स' 5.9% टूटा, जो 2020 के बाद पहली मासिक गिरावट है। इसके बावजूद कीमतें 1,980 दिरहम यानी करीब 51,300 रुपए प्रति वर्ग फुट के स्तर पर हैं, जो 12 महीनों में 4.59% बढ़ा है। एटमॉस्फियर लिविंग के एमडी संदीप आहूजा का कहना है कि दुबई का न्यूट्रल हब होना लंबी अवधि के नजरिए से निवेश की दिलचस्पी बनाए रखता है और खरीदार अभी मोलभाव की स्थिति में हैं। आयुष पुरी इसे बाजार का क्रैश नहीं, बल्कि कीमतों का एडजस्टमेंट मानते हैं। गुलाम जिया का अनुमान है कि सेंटिमेंट सुधरते ही बाजार तेजी से स्थिर हो जाएगा।

चीन की सप्लाई चेन को चुनौती, भारत-अमेरिका ने मिलाए हाथ

भास्कर न्यूज | मुंबई

क्रिटिकल मिनरल्स के मोर्चे पर चीन का दबदबा खत्म करने के लिए भारत और अमेरिका ने मिलकर एक संयुक्त टास्कफोर्स बनाई है। इसमें दोनों देशों की 17 बड़ी कंपनियां शामिल हैं।

'अमेरिका-भारत क्रिटिकल मिनरल्स सिक्योरिटी टास्कफोर्स' की पहली बैठक पिछले हफ्ते वाशिंगटन में हुई। यह कदम उस द्विपक्षीय समझौते के बाद उठाया गया है, जिस पर भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पिछले महीने दस्तखत किए थे। इसका मकसद माइनिंग, प्रोसेसिंग में सहयोग बढ़ाना है। नया टास्कफोर्स क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव से भी जुड़ी है, जो एशिया-प्रशांत में माइनिंग, प्रोसेसिंग और रीसाइक्लिंग में निवेश जुटा रही है। लिथियम रिफाइनिंग, बैटरी-ग्रेड सिंथेटिक ग्रेफाइट, रेयर अर्थ प्रोसेसिंग और मिनरल रीसाइक्लिंग के मामले में दोनों देश मिलकर चीन पर निर्भरता कम करना चाहते हैं।

टास्कफोर्स के 5 लक्ष्य

- लिथियम रिफाइनिंग, कैथोड एक्टिव मटेरियल्स का उत्पादन
- फीडस्टॉक कॉरिडोर-कच्चे माल की पूरी सप्लाई चेन
- बैटरी-ग्रेड सिंथेटिक ग्रेफाइट का उत्पादन बढ़ाना
- रेयर अर्थ प्रोसेसिंग और मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस
- क्रिटिकल मिनरल्स की रीसाइक्लिंग

Lifetime Free Newspapers Access

Editorials PDF

- English Editorials PDF with International Neespapers Editorials [35-40pages]
- Hindi Editorials PDF
- Daily Vocabulary PDF

Magazine Channel

National & International
[Genaral & Exam related]

International Newspapers

Newspapers around world.
Asian, Europian & American

Hindi Newspapers

1) दैनिक जागरण
2) जनसत्ता
3) हरिभूमि
4) हिंदुस्तान

Indian Newspapers Channel

1. The Indian Express
2. The Hindu
3. Business Line
4. Financial Express
5. Times of India
6. Hindustan Times
7. Economic Times
8. Live Mint
9. Business Standard

Click below to Join this Community 👇